



सत्यमेव जयते

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड  
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  
भारत सरकार

24<sup>वीं</sup>  
वार्षिक  
रिपोर्ट  
2019-20





## विषय—वस्तु

सचिव की कलम से	05
टीडीबी का अधिदेश	06
टीडीबी द्वारा वित्त पोषित क्षेत्र	06
बोर्ड के सदस्य	08
विहंगवावलोकन	09
टीडीबी – वर्ष एक दृष्टि में	21
हस्ताक्षरित करार	27
पूर्ण की गई परियोजनाएं	33
प्रोत्साहक क्रियाकलाप	41
प्रशासन	49
वर्ष 2019–20 के लिए लेखा-परीक्षित वार्षिक विवरण	51
वर्ष 2019–20 की पृथक सी एंड एजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट	79





## सचिव की कलम से

**टी**डीबी की वर्ष 2019-20 की उपलब्धियों को आपके साथ साझा करने में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस वर्ष में, टीडीबी ने विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता देने के लिए पाँच करारों पर हस्ताक्षर किए।

इन करारों के माध्यम से टीडीबी ने ₹ 70.32 करोड़ के कुल परियोजना परिव्यय में से ₹ 29.87 करोड़ की प्रतिबद्धता विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, ऊर्जा और अपशिष्ट उपयोग, स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए व्यक्त की है।

इस वर्ष में, टीडीबी को विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कुल 23 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

वर्ष के दौरान टीडीबी ने चालू और नई परियोजनाओं और अन्य योजनाओं के लिए ₹ 128.74 करोड़ की राशि का वितरण किया, जिसमें क्रमशः ₹ 128.37 करोड़ ऋण, ₹ 0.11 करोड़ अनुदान और ₹ 0.26 करोड़ वीसीएफ में निवेश किया गया।

वर्ष 2015-16 में अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी), यूनाइटेड किंगडम (यूके) के साथ शुरु किया गया इन्वेंट

कार्यक्रम, इस साल पूर्ण हो गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 150 उद्यमियों को उद्भवित किया है, जिनमें से 141 उद्यमियों ने करारों पर हस्ताक्षर किए हैं और जिनमें से 30 उद्यमियों ने ₹ 76.50 करोड़ के लिए फॉलो-ऑन फंडिंग जुटाई है। उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमान लगाया गया है कि कम आय वाले राज्यों में लगभग 5000 लोगों के लिए रोजगार सृजित किये गये हैं, जिससे लगभग 6.2 लाख लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है।

टीडीबी ने अब तक अन्य निवेशकों के साथ 11 वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) में भाग लिया है, जिसमें कुल निवेश प्रतिबद्धता ₹ 285.00 करोड़ थी। टीडीबी ने लगभग 220 कंपनियों में निवेश किया। इस वर्ष वीसीएफ के लिए ₹ 0.28 करोड़ का निवेश किया गया।

टीडीबी द्वारा पूर्व में अनुमोदित परियोजनाओं में से सात को पूर्ण रूप से वाणिज्यीकरण कर दिया गया है, जिसमें से एक मेसर्स ग्रोसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई द्वारा ₹ 250.00 करोड़ के निवेश और ₹ 689.00 करोड़ की कुल परियोजना लागत के साथ "बिरला एक्सल साल्वेंट स्पान सेलुलॉसिक फाइबर संयंत्र" स्थापित करने के लिए थी। टीडीबी से लाभान्वित कुल 10 कंपनियों ने पुनर्भुगतान पूरा करके अपने ऋण खाते का निपटान कर दिया है।

वर्ष 2019-20 में बोर्ड की कुल दो बैठकों का आयोजन हुआ, जिससे तेजी से प्रभावशाली निर्णय लेने में सहायता मिली।

अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी टीडीबी ने सक्रिय रूप से विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रदर्शनियों में भाग लिया, जिससे देश भर में प्रौद्योगिकी सुविधा प्रदाता के रूप में टीडीबी की भूमिका को उजागर करने में मदद मिली।

इस वर्ष भी टीडीबी ने स्वयं को पुनर्निवेशित करते हुए स्वदेशी तकनीक के व्यवसायीकरण के अपने अधिदेश का अनुपालन किया। टीडीबी ने अपने सक्रियता को बढ़ाने हेतु नए कर्मियों को शामिल किया। वर्ष के समाप्ति पर, जहाँ विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा था, उस समय बोर्ड ने सक्रिय दृष्टिकोण अपनाते हुए, भारतीय कंपनियों और उद्यमों से विभिन्न क्षेत्रों से तकनीकी रूप से नये समाधानों के लिए दिनांक 20.03.2020 को आवेदन आमंत्रित किये।

कुल मिलाकर, वर्ष 2019-20 टीडीबी के लिए एक प्रभावशाली वर्ष रहा है।

(डॉ. नीरज शर्मा)

## टीडीबी का अधिदेश

- स्वदेशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक अनुप्रयोग का प्रयत्न करने वाले अथवा वृहत घरेलू अनुप्रयोगों के लिए आयातित प्रौद्योगिकी का अनुशीलन करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना;
- जैसा केन्द्र सरकार मान्यता प्रदान करे, स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करने अथवा वाणिज्यिक अनुप्रयोग के लिए आयातित प्रौद्योगिकी के अनुशीलन में संलग्न ऐसी अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना;
- केन्द्र सरकार द्वारा इन्हें सौंपे जाने वाले ऐसे अन्य कार्यों को निभादित करना।

## टीडीबी द्वारा अब तक वित्त पोषित क्षेत्र



स्वास्थ्य एवं चिकित्सा



सूचना प्रौद्योगिकी



इलेक्ट्रॉनिक्स



दूरसंचार



सुरक्षा एवं  
नागर विमानन



कृषि



अभियांत्रिकी



सड़क परिवहन



वस्त्र



रसायन



ऊर्जा एवं अपशिष्ट  
उपयोग



अन्य

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का संघटन

(31 मार्च, 2020 तक)

1.	<b>प्रो. आशुतोष शर्मा</b> सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	पदेन अध्यक्ष
2.	<b>डॉ. शेखर सी. माण्डे</b> सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	पदेन सदस्य
3.	<b>डॉ. जी. सतीश रेड्डी</b> सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग	पदेन सदस्य
4.	<b>डॉ. टी. वी. सोमनाथन</b> सचिव, व्यय विभाग	पदेन सदस्य
5.	<b>डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र</b> सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	पदेन सदस्य
6.	<b>श्री राजेश भूषण</b> सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	पदेन सदस्य
7.	<b>प्रो. देशदीप सहदेव</b> परामर्शदाता, क्वाजर टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य
8.	<b>सुश्री बिनीशा पी.</b> कार्यकारी निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान, बंगलौर	सदस्य
9.	<b>श्री साबू एम. जैकब</b> प्रबंध निदेशक, कीटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड, अर्नाकुलम, केरल	सदस्य
10.	<b>श्री प्रदीप गोयल</b> अध्यक्ष, प्रदीप मेटल्स लिमिटेड, नवी मुंबई	सदस्य
11.	<b>डॉ. नीरज शर्मा</b> सचिव, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड	पदेन सदस्य (सदस्य सचिव)

# बोर्ड सदस्य

(31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार)



प्रो. आशुतोष शर्मा



डॉ. रोखर सी. मांडे



डॉ. जी. सतीश रेड्डी



डॉ. टी. वी. सोमनाथन



डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र



श्री राजेश भूषण



प्रो. देशदीप सहदेव



सुश्री वीनीशा पी.



श्री साबू एम. जेकब



श्री प्रदीप गोयल



डॉ. नीरज शर्मा



विहंगावलोकन

# विहंगावलोकन

**भ**ारत सरकार ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी के निर्माण एवं वाणिज्यीकरण और वृहत घरेलू अनुप्रयोगों के लिए आयातित प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 1996 को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) गठित किया था। टीडीबी ऐसे निर्माण एवं वाणिज्यिक अनुप्रयोग का प्रयास करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

इस अधिनियम ने टीडीबी द्वारा प्रशासित किए जाने वाले प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग कोष निर्माण को समर्थ बनाया। इस कोष को वर्ष 1995 में यथा संशोधित, अनुसंधान एवं विकास उपकर अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत औद्योगिक प्रतिष्ठानों से सरकार द्वारा संकलित आरएंडडी उपकर में से भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। यह अधिनियम किसी अन्य स्रोत, कोष से प्रदत्त राशि से की गई पुनर्वसूली और कोष की राशि के निवेश से प्राप्त किसी आय से सभी धनराशियों को जमा कर कोष बनाने में भी टीडीबी को समर्थ बनाता है। वित्त अधिनियम 1999 ने आयकर प्रयोजनों के लिए कोष में अंशदान के लिए पूर्ण कटौती को समर्थ बनाया।

2017-18 के अपने आम बजट में, केन्द्र सरकार ने अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 को 1 अप्रैल, 2017 से समाप्त कर दिया गया। 1996-97 से 2016-17 की अवधि के दौरान, सरकार ने आर एंड डी उपकर के रूप में ₹ 7974.32 करोड़ की राशि संग्रहित की है।

टीडीबी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के गैर-योजना बजट से सहायता अनुदान के रूप में 24 वर्ष (1996-97 से 2019-20) की अवधि में ₹ 977.47 करोड़ संचय राशि प्राप्त हुई।

## वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रकार

टीडीबी से वित्तीय सहायता ऋण या इक्विटी और/या आपवाधिक मामलों में अनुदान के रूप में उपलब्ध है। औद्योगिकी प्रतिष्ठानों से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन (कंपनी अधिनियम 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार शामिल) पूरे वर्ष के दौरान स्वीकार किया जाता है।

## ऋण

औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता 5 प्रतिशत प्रति वर्ष के साधारण ब्याज दर पर आसान ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। ऋण के रूप में वित्तीय सहायता की सीमा अव्ययित परियोजना लागत का 50 प्रतिशत है। ऋण राशि का वितरण ऋण करार में यथा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संबंधित लक्ष्य के कार्यान्वयन के अनुसार किस्तों में किया जाता है। रॉयल्टी, ऋण की निरंतरता के दौरान टीडीबी की परियोजना के तहत उत्पादों की बिक्री पर यह देय है।

कुछ मामलों में, टीडीबी में सहायित औद्योगिक प्रतिष्ठान के निदेशक मंडल में नामित निदेशक हो सकते हैं। किसी परियोजना की कार्यान्वयन अवधि आमतौर पर तीन साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऋण और ब्याज को संपार्श्विक राशि और गारंटी के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है। आमतौर पर, ऋण की अदायगी और ब्याज का भुगतान परियोजना के पूरा होने के बाद शुरू होता है और ऋण अधिस्थगन अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होती। ऋण की राशि आमतौर पर नौ, छमाही किस्तों में वसूली योग्य है। पहली किस्त के पुनर्भुगतान तक संचित ब्याज तीन साल की अवधि में वितरित किया जाता है।

टीडीबी आवेदकों से प्रशासनिक, प्रक्रमण या प्रतिबद्धता शुल्क एकत्र नहीं करता है।

## इक्विटी

टीडीबी, द्वारा यथा मूल्यांकित आवश्यकताओं के अनुसार और ऋण इक्विटी अनुपात को ध्यान में रखते हुए उसकी शुरुआत, स्टार्ट अप और/अथवा विकास चरणों में औद्योगिक प्रतिष्ठान में इक्विटी पूंजी (कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत अथवा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार समाविष्ट) के जरिए अंशदान करता है। इक्विटी अंशदान का निर्णय टीडीबी के पूर्ण बोर्ड द्वारा किया जाता है। यह स्वीकृत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक है, बशर्ते कि ऐसा निवेश प्रवर्तकों द्वारा भुगतान की गई पूंजी से अधिक नहीं हो।

टीडीबी मौजूदा ऋणों या औद्योगिक प्रतिष्ठानों की इक्विटी को प्रतिस्थापित करने पर विचार नहीं करता है, जिन्होंने अन्य संस्थाओं से इस तरह के वित्त प्राप्त किए हैं।

## अनुदान

टीडीबी औद्योगिक प्रतिष्ठानों और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास में लगी आर एण्ड डी संस्थाओं को अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय हित को पूरा करने की दिशा में महत्व रखने वाले आपवादिक मामलों में अनुदान प्रदान की मंजूरी पूर्ण बोर्ड द्वारा तय की जाती है।

निम्न सारणी 31 मार्च 2020 तक टीडीबी द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के प्रकार को इंगित करती है—

(रु. करोड़ में)

साधन	*टीडीबी द्वारा स्वीकृत	टीडीबी द्वारा संवितरित
ऋण	1729.17	1506.17
इक्विटी	33.06	34.66
अनुदान	150.66	150.60
वेंचर फंडस	285.00	252.77
<b>कुल</b>	<b>2197.89</b>	<b>1944.20</b>

\* टीडीबी द्वारा 31.03.2020 तक वार्षिक स्वीकृत वधि, पिछले कुछ मामलों में प्रत्येक इक्विटी में करारपत्र की अवधि, वित्तीय सहायता की मात्रा में संशोधन, परियोजनाओं के परिवर्तन आदि तदर्थ होने की संभावना है।

## करारों का क्षेत्र-वार कवरेज

टीडीबी की वित्तीय सहायता अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रदान की जाती है। वर्ष 1996 में अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च, 2020 तक, टीडीबी ने ₹ 8407.64 करोड़ की परियोजना लागत और ₹ 2197.89 करोड़ की टीडीबी की प्रतिबद्धता के साथ, अब तक 360 करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। टीडीबी ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ₹ 977.47 करोड़ के सहायता अनुदान में से और आंतरिक प्राप्तियों के माध्यम से ₹ 1944.20 करोड़ संवितरित किया है।

निम्नलिखित सारणी वर्ष 1996-97 में टीडीबी की स्थापना से लेकर 31 मार्च 2020 तक इसके द्वारा क्षेत्र-वार स्वीकृत परियोजना दर्शाती है—

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	करारों की संख्या	कुल लागत	टीडीबी की प्रतिबद्धता
1	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	96	2015.62	587.85
2	अभियांत्रिकी	69	699.96	256.98
3	सूचना प्रौद्योगिकी	45	454.54	169.31
4	रसायन	26	236.80	84.69
5	कृषि	27	217.48	69.85
6	दूरसंचार	12	99.88	37.85
7	सड़क परिवहन	10	527.04	81.20
8	ऊर्जा एवं अपशिष्ट उपयोग	10	140.10	59.61
9	इलेक्ट्रॉनिक्स	4	52.56	17.75
10	रक्षा एवं नागर विमानन	10	648.83	229.95
11	वस्त्र	1	689.00	250.00
12	अन्य - सहित			
	वेन्चर फंडस	11	2463.00	285.00
	एसटीईपी - टीबीआई	35	35.00	35.00
	सीआईआई	1	0.83	0.50
	मिलेनियम अलायंस	1	112.00	25.00
	ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस	1	15.00	7.35
	इवेंट कार्यक्रम	1	-	-
	<b>कुल योग</b>	<b>360</b>	<b>8407.64</b>	<b>2197.89</b>

टीबीबी द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता मुख्य रूप से अपने सभी नये उद्यमों एवं विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में बाजार आधारित एवं प्रौद्योगिकी उन्मुख है।

### करारों का राज्य-वार वितरण (1996-2020)

वर्ष 1996-2020 के दौरान हस्ताक्षर किए गए करारों का राज्यवार वितरण (कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर आधारित) नीचे दिया गया है:

(रु. करोड़ में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	करारों की संख्या	कुल लागत	टी डी बी की प्रतिबद्धता
1	असम	1	18.31	8.20
2	आंध्रप्रदेश/तेलंगाना	86	1677.97	541.34
3	कर्नाटक	45	1027.96	355.67
4	महाराष्ट्र	48	1624.18	450.93
5	तमिलनाडु	37	319.51	100.38
6	दिल्ली	22	310.57	114.38
7	गुजरात	14	149.06	45.94
8	पश्चिम बंगाल	10	137.39	57.57
9	उत्तर प्रदेश	12	94.77	50.44
10	मध्य प्रदेश	7	155.92	42.20
11	हरियाणा	7	47.57	19.48
12	पंजाब	7	91.79	21.98
13	घड़ीगढ़	4	43.75	16.50
14	केरल	5	21.63	8.15
15	हिमाचल प्रदेश	1	6.24	1.90
16	जम्मू एवं कश्मीर	1	5.65	2.38
17	मणिपुर	1	7.94	2.70
18	पाण्डिचेरी	1	5.83	1.90
19	राजस्थान	1	35.77	3.00
20	अन्य-सहित			
	वैधर फंडस	11	2463.00	285.00
	एसटीईपी - टीबीआईएस	35	35.00	35.00
	सीआईआई	1	0.83	0.50
	मिलेनियम अलायंस	1	112.00	25.00
	ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस	1	15.00	7.35
	इवेंट कार्यक्रम	1		
	<b>कुल योग</b>	<b>360</b>	<b>8407.64</b>	<b>2197.89</b>

## परियोजना प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण

टीडीबी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होता है। वित्तीय सहायता और अन्य विवरण के लिए आवेदन प्रपत्र टीडीबी की वेबसाइट पर उपलब्ध "परियोजना वित्त पोषण दिशा-निर्देश" में दिया गया है। औद्योगिक प्रतिष्ठान, 10 वर्ष भर <http://e-techcom.tdb.gov.in> पर किसी भी समय ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं।

## परियोजना प्रस्तावों का प्रक्रमण

प्राप्त आवेदनों को तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञों वाली समिति द्वारा बड़े पैमाने पर प्रक्रमित किया जाता है।

## आवेदनों की प्रारंभिक जांच

विधिवत रूप से गठित प्रारंभिक जांच समिति (आईएससी) आवेदन की पूर्णता, परियोजना के उद्देश्य, प्रौद्योगिकी की स्थिति आदि के दृष्टिकोण से वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक रूप से जांच करती है।

इस जांच समिति में प्रसिद्ध राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के तकनीकी व वित्तीय विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इस समिति के सामने, आवेदक और/या प्रौद्योगिकी प्रदाता प्रस्तुत परियोजना पर अधिक स्पष्टता के लिए विशेषज्ञों द्वारा प्रश्नावली के बाद विस्तृत प्रस्तुती देते हैं। समिति के सुझाव/टिप्पणी के अनुसार यदि मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त जानकारी/विवरण या अनुवर्ती स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, यह कंपनी से मांगी जाती है।

यदि आवेदन टीडीबी की वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो आईएससी लिखित कारणों को प्रस्तुत करने के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए आवेदन की सिफारिश नहीं कर सकता है।

## परियोजना मूल्यांकन समिति (पीईसी)

आईएससी की सिफारिशों के आधार पर, आवेदन को परियोजना स्थल पर जाकर परवर्ती मूल्यांकन और निर्धारण के लिए पीईसी गठित की जाती है। प्रत्येक परियोजना के लिए परियोजना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पीईसी का गठन किया जाता है। पीईसी में परियोजना के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए टीडीबी के बाहर से संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञ (वैज्ञानिक, तकनीकी और वित्तीय) होते हैं। विशेषज्ञ (सेवारत या सेवानिवृत्त) सरकारी विभागों, अनुसंधान एवं विकास संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग, उद्योग संघों, वित्तीय संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित हो सकते हैं। प्रौद्योगिकी प्रदाता के साथ आये

दक को वैज्ञानिक, तकनीकी, विपणन, वाणिज्यिक और वित्तीय पहलुओं पर एक विस्तृत प्रस्तुति देने और परियोजना और कंपनी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर महान जानकारी प्रदान करने का पूरा अवसर दिया जाता है।

## मूल्यांकन मानदंड

आवेदन का मूल्यांकन इसके वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, वाणिज्यिक और वित्तीय गुणों के लिए किया जाता है। मूल्यांकन मानदंडों में शामिल हैं:

- प्रस्ताव की विशिष्टता और नवीन विषय-वस्तु
- सुदृढ़ता, वैज्ञानिक गुणवत्ता और तकनीकी योग्यता
- व्यापक अनुप्रयोग के लिए क्षमता और वाणिज्यीकरण से प्राप्त होने वाले प्रत्याशित लाभ
- प्रस्तावित प्रयास की प्रयाप्तता
- प्रस्तावित कार्रवाई नेटवर्क में आर एंड डी संस्थाओं की क्षमता
- इसकी आंतरिक प्राप्ति सहित उद्यम की संगठनात्मक और व्यावसायिक क्षमता
- प्रस्तावित लागत और वित्तपोषण पैटर्न की युक्तिसंगतता
- मापने योग्य उद्देश्य, लक्ष्य और ध्येय
- उद्यमी की पृष्ठभूमि

## गोपनीयता एवं पारदर्शिता

टीडीबी यह मानता है कि गोपनीयता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक प्रस्ताव एक नये उत्पाद या प्रक्रिया को शामिल करने वाला एक व्यावसायिक प्रस्ताव है। यदि आवेदक यह उल्लेख करता है कि परियोजना प्रस्ताव में दी गई कुछ सूचनाओं को सख्ती से गोपनीय माना जाता है, तो इसे पीईसी के विशेषज्ञों को परिचालित नहीं किया जाता है। पीईसी प्रक्रियाओं पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करने में आवेदक की आंशकाओं की संवेदनशीलता का सम्मान करता है।

आवेदक के साथ एक व्यापक चर्चा/विचार विमर्श के बाद, पीईसी का गठन करने वाले विशेषज्ञों द्वारा टिप्पणियों और सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जाता है।

## वित्तीय सहायता का अनुमोदन

पीईसी की सिफारिशों को अध्यक्ष टीडीबी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। पीईसी द्वारा अनुशंसित सभी परियोजना प्रस्ताव जहां टीडीबी की सहायता ₹10 करोड़ से अधिक है या कुल परियोजना लागत ₹30 करोड़ से अधिक है तो तीसरे पक्ष

की सम्यक सतर्कता के लिए प्रकृतित किया जाता है। तीसरे पक्ष की सम्यक सतर्कता रिपोर्ट के साथ पीईसी की सूचना, बोर्ड को उनकी मंजूरी के लिए रखा जाता है। शेष अनुशसित मामलों को संबंधित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

### निगरानी और समीक्षा

टीडीबी ने लाभार्थियों को स्वीकृत वित्तीय सहायता किरतों में प्रदान की, जो पारस्परिक रूप से सहमत ऋण करार के अनुसार पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुपालन पर आधारित थी।

परियोजना को समय-समय पर परियोजना निगरानी समिति द्वारा अनुवीक्षित किया जाता है। पीएमसी में वैज्ञानिक/तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञ शामिल रहते हैं।

### सक्रिय भूमिका

औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य एजेंसियों से प्राप्त आवेदनों के प्रत्युत्तर अलावा, टीडीबी प्रौद्योगिकी विकास और व्यावसायिकरण के लिए एक व्यापक सहायता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सक्रिय भूमिका निभाता है। अपने अधिदेश के तत्वावधान में टीडीबी ने विभिन्न पहलों के माध्यम से स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और व्यावसायिकरण को प्रोत्साहित किया है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं

#### क) वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) में भागीदारी

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने महसूस किया कि कई प्रौद्योगिकीय परियोजनाएं वित्तीय संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों की पारंपरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। वाणिज्यिकरण के लिए प्रत्यक्ष रूप से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की सहायता करने के अलावा, टीडीबी ने प्रौद्योगिकी केंद्रित जोखिम पूंजी कोष (वीसीएफ) को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य संस्थानों के साथ नेटवर्किंग की आवश्यकता महसूस की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पर्याप्त धन की कमी प्रौद्योगिकी रूप से अच्छी अभिनव व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए बाधा नहीं है।

इस प्रकार टीडीबी ने शुरूआती चरण के उपक्रमों को नवाचार और अभिनव उत्पादों/सेवाओं वाले एसएमई के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए वेंचर कैपिटल फंड में भाग लिया। टीडीबी की प्रेरणा और भागीदारी के फलस्वरूप उद्यमी पूंजीपतियों ने टीडीबी के मिशन के लिए अपनी सहायता प्रदान की है। बोर्ड ने वीसीएफ में टीडीबी की भागीदारी को विशेष रूप से नवाचार और अभिनव उत्पादों/सेवाओं वाले वाले एनएसएमई/एसएमई श्रेणी में प्रौद्योगिकी कंपनियों

की सहायता करने के लिए टीडीबी के अधिदेश के बढ़ते भौगोलिक प्रसार के लिए एक सधन के रूप में माना।

टीडीबी की पहल ने उद्यम पूंजीपतियों/निजी इविवटी कोष को उन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी आधारित परियोजनाओं की सहायता में बड़े पैमाने पर आने का भरोसा दिया है जो उन क्षेत्रों पर स्पष्ट जोर देता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास चालक हैं।

#### ख) इनक्यूबेटर में स्टार्ट-अप के लिए मूल सहायता

2005 में टीडीबी ने युवा उद्यमियों को नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी विचारों के साथ प्रारंभिक चरण/स्टार्ट-अप वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मूल सहायता योजना शुरू की, ताकि वे अपने निर्माणाधीन विचारों को सफल बनाया और बाजार की पहुंच तक सुलभ कराया जा सके। प्रस्तावित सहायता का उपयोग प्रौद्योगिकी के निर्माण एवं वाणिज्यकरण के बीच सोपान के रूप में कार्य करने के लिए किया गया। यह योजना डीएसटी के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड (एनएसटीडीबी) द्वारा प्रशासित इनक्यूबेटर्स/प्रौद्योगिकी कार्य इनक्यूबेटर्स स्केप/टीबीआई में स्टार्ट-अप के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

31 मार्च 2018 तक, टीडीबी ने 35 टीबीआई और स्टेप को सहायित किया जिसमें 4 टीबीआई/एसटीईपी के लिए दो बार वित्तीय सहायता शामिल है एवं प्रत्येक को ₹ 1.00 करोड़ की वित्तीय सहायता के साथ कुल ₹ 35.00 करोड़ प्राप्त हुए। इन इनक्यूबेटर्स ने दूर संचार, संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, कृषि, उपकरणकरण, अभियांत्रिकी, पर्यावरण, फार्मा, खाद्य और सौर, वस्त्र एवं जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में फैले अपने प्रोजेक्ट के लिए कई इनक्यूबेट कंपनियों को सहायता प्रदान की। इस योजना ने अच्छी प्रगति की और कई उद्यमियों को स्तरान्वयन और संबंधित कार्यों में लाभान्वित किया। इससे इनक्यूबेटर्स द्वारा उद्यमन निधि के एक कोष के निर्माण में भी सुविधा प्रदान हुई।

#### ग) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

##### i) बीपीआई फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन

टीडीबी प्रबंध साझेदार के रूप में सीईएफआईपीआरए के साथ टीडीबी और बीपीआई फ्रांस नवीकृत समझौता ज्ञापन (एमओयु) के अनुसार बीपीआई फ्रांस के बीच जो पूर्ववर्ती ओएसईओ फ्रांस है सहयोग जारी है। करार पर 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह पांच साल के लिए वैध है। यह करार भारत और फ्रांस की कंपनियों, संस्थानों और संगठनों के बीच सहयोग से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में तकनीकी आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए

सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान और समन्वित उपायों की स्थापना से संबंधित क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए बाध्य करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैमानिकी स्वचलन एवं जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र विषयक प्रस्तावों का वित्तपोषण करना है।

## ii) अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) के साथ समझौता ज्ञापन

टीडीबी ने अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) के साथ भागीदारी से वित्त वर्ष 2015-16 में इनोवेटिव वेंचर्स एंड टेक्नोलॉजिज फॉर डेवलपमेंट (इन्वेंट) कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम प्रौद्योगिकी और प्रकिया उन्मुख दोनों समावेशी नवाचार समाधानों को सहायित करने की दृष्टि से एक मंच बनाने के लिए अभिकल्पित किया गया था, जिसका निम्न आयवर्ग के लोगों पर सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ा है। यह सहायता भारत के निम्न आय वाले 8 राज्यों (यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड राजस्थान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल) में वित्त पोषण, गहन सलाह, ज्ञान और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों सहायक सेवाओं और प्रारंभिक नेटवर्क तक पहुंच के प्रायधान तक ही सीमित नहीं है।

### अंतिम उद्देश्य

- उपर्युक्त 8 एलआईएस में प्रभावी निवेश के लिए व्यवहार्य सामाजिक उद्यम पाइपलाइन सृजित करना;
- कम आय वाले 8 राज्यों में लाभकारी सामाजिक उद्यमों के लिए 50 निवेश तैयार करना;
- कम आय वाले 8 राज्यों में 160 उद्यमियों को सहायित करना।

### प्रभाव

- एक पारिस्थितिकी तंत्र ऐसे वित्तपोषण अवसरों में विविधता लाने में सक्षम होगा जो 8 एलआईएस में सामाजिक उद्यमों को स्तरोन्नयित करने के लिए उपर्युक्त है।
- सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ने और सामाजिक उद्यमिता में शामिल होने के लिए और अधिक लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी सहायता में वृद्धि।
- मजबूत मान्यताओं के साथ सामाजिक उद्यमक स्थापित किया गया।

वित्त वर्ष 2015-16 में टीडीबी और मेसर्स विल्यो इनोवेशन फाउंडेशन (पीआईएफ) के बीच एक करार को निष्पादित किया गया था, जिसमें भारत के कम आय वाले 8 राज्यों में प्रभाव निवेश के लिए विल्यो को एक व्यवहार्य सामाजिक उद्यम लाभ के लिए बनाने के उद्देश्य से उद्यमन सहायता

कराने की दृष्टि से लीड इनक्यूबेटर के रूप में कार्य करने के लिए चुना गया था। विल्यो वर्तमान में कम आय वाले राज्यों में चार उद्यमकों आईआईएम कलकत्ता इनोवेशन पार्क, (आईआईएमसीआईपी) भुनेश्वर में केआईआईटी टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर केआईआईटीपीआई, आईआईटी कानपुर में एसआईडीबीआई इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर एसआईआईसी आईआईटी के और स्टार्ट-अप ओएसिस सीआईआई, आई आईएम अहमदाबाद, रिकवो की एक पहल को सहायित कर रहा है ताकि, व्यावसायिक रूप से सफल होने के दौरान भारत के एलआईएस में गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले उद्यम विकास के मूल या शुरुआती चरणों में अभिनव व्यवसायों को अपनाया जा सके।

## घ) राष्ट्रीय सहयोग

### क्लाइमेट सॉल्वर पार्टनर के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन

नवाचार में भारत की ताकत को देखते हुए, जिसमें यह ग्लोबल क्लीन टेक इनोवेशनइंडेक्स 2012 में 12 वें स्थान पर रखा गया है, टीडीबी ने 21 मई 2012 में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया द्वारा शुरू किए गए क्लाइमेट सॉल्वर प्लेटफॉर्म में शामिल होने का फैसला किया।

भारत में टीडीबी के अलावा, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) न्यूवेनचर्स इंडिया, सेंटर फॉर इनोवेशन इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (आईआईएम अहमदाबाद) और स्काईक्वेस्ट टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

### टाइफोक के साथ समझौता ज्ञापन

टीडीबी और प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद जो डीएसटी के तहत एक स्वायत्त निकाय है, ने 10 फरवरी, 2018 को नवीन प्रौद्योगिकी खोज करने स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की वाणिज्यीकृत करने और ऐसी प्रौद्योगिकियों को वाणिज्यीकृत करने वाली कंपनियों में निवेश करने के उद्देश्य से परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी नवाचार पर एक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किये। सहयोग के क्षेत्रों एवं दायरों में शामिल हैं

- निवेश के रुझान और उन्हें चलाने वाली ताकतों के साथ उदीयमान (मुख्य प्राथमिकता वाली) प्रौद्योगिकियों/ तकनीकी क्षेत्रों की खोज करना।
- ऐसी तकनीकों की पहचान करना जो सामाजिक और आर्थिक वातावरण को बदलने और साथ ही राष्ट्र के बढ़ते युवाओं के लिए तत्काल, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक आधार पर रोजगार पैदा करने की क्षमता रखते हैं।

- तकनीक को अपनाना आसान बनाने के लिए नीतिगत ढाँचा विकसित करना, पहचान किए गए क्षेत्र के लिए देश में इसके वाणिज्यीकरण के लिए स्तरोन्नयन और विनिर्माण करना।

#### आईसीसीओ के साथ समझौता ज्ञापन

टीडीबी और इनोवेटिव चेंज कोलेबोरेटिव (आईसीसीओ) इंडिया ऑगनाइजेशन जो भारत में काम करने वाला विकास संगठन है ने नवप्रवर्तक कृषि प्रौद्योगिकियों की खोज, स्वदेशी प्रौद्योगिकी को वाणिज्यीकृत करने एवं कंपनियों में निवेश करने के उद्देश्य से परिवर्तनकारी कृषि प्रौद्योगिकी व्यापार ने समाधान विषयक समझौता ज्ञापन पर 6 मार्च, 2018 को हस्ताक्षर किये जो किसानों की आय को दोगुना करने की क्षमता प्रदर्शित करेगा। सहयोग के क्षेत्रों और दायरे में शामिल है:

- कटाई के पहले क्षेत्र संबद्ध कृषि, कटाई के बाद क्षेत्र में प्रांसगिक कृषि प्रौद्योगिकी व्यवसाय समाधानों की खोज करना।
- प्रौद्योगिकीयों और व्यावसायिक समाधानों की पहचान करना, जो ग्रामीण आर्थिक वातावरण को बदलने की क्षमता के साथ-साथ तत्काल, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक आधार पर राष्ट्र के ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार पैदा करते हैं।
- व्यावसायिक और वित्तीय व्यवहार्यता के लिए उनकी प्रौद्योगिकी तत्परता और व्यवसाय मॉडल का मूल्यांकन करके किसानों की आय के स्तर में वास्तविक सुधार करने के लिए पहचान किए गये क्षेत्रों में रोचक कृषि प्रौद्योगिकी व्यवसायों की क्षमता का आकलन करना।

#### पीएचडी उद्योग एवं वाणिज्य संघ के साथ समझौता ज्ञापन

टीडीबी और पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने 25 अप्रैल 2018 को एग्रीबिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग, हेल्थकेयर एंड फार्मास्युटिकल्स इलेक्ट्रि मोबिलिटी, वाटर एंड वेस्ट टु एनर्जी, ऑटोमोबाइल्स जैसे राष्ट्रीय महत्व की उभरती प्रौद्योगिकी/तकनीकी क्षेत्रों की खोज करने और हस्ताक्षर किए। प्रेरक कारकों की पहचान, प्रौद्योगिकी के आसान अभिग्रहण, इसके व्यावसायिकरण के लिए स्तरोन्नयन एवं विनिर्माण हेतु नीतिगत ढाँचे को विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। दोनों संगठन प्रौद्योगिकी संचालित परियोजनाओं के साथ उद्योगों की पहचान करने में सहयोग कर रहे हैं जिनके सामाजिक और आर्थिक निहतार्थ हो सकते हैं और तत्काल मध्यम अवधि और दीर्घकालिक आधार पर राष्ट्र के युवाओं के लिए रोजगार पैदा करते हैं।

#### एसोचैम के साथ समझौता ज्ञापन

टीडीबी और भारतीय संयुक्त वाणिज्य और उद्योग संघ (एसोचैम) ने भेषज, शिकित्सीय उपकरणों एवं नैदानिक साधनों, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा एवं बात अंतरिक्ष एवं वैद्युत गत्यात्मकता और ऑटोमोबाइल्स जैसे राष्ट्रीय महत्व के उदीयमान प्रौद्योगिकियों और प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों की खोज करने एवं उन्हें प्रेरित करने वाले कारकों को अभिज्ञात करने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के सहज अभिग्रहण के लिए नीतिगत ढाँचा विकसित करने, इसके वाणिज्यीकरण के लिए स्तरोन्नयन एवं विनिर्माण करने की दृष्टि से 3 मई 2018 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। दोनों संगठन तत्काल, मध्यम अवधि व दीर्घकालिक अवधि के आधार पर वाणिज्यिक परिणाम वाले आदि रूप प्रौद्योगिकियों/प्रौद्योगिकी चलि परियोजना वाली कंपनियों को अभिज्ञात करने की दृष्टि से गोष्ठी, संवाद और परियोजना लेखन कार्यशालाओं के माध्यम से गहन संपर्क में कार्य कर रहे हैं।

#### बीआईआरएसी के साथ समझौता ज्ञापन

स्वदेश विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यकरण के लिए विभिन्न उद्योग सहायक संगठनों के बीच तालमेल हेतु 7 सितंबर 2018 को बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल (बीआईआरएसी) और टीडीबी के बीच समझौता ज्ञापन पर एक सहज तरीके से जैवशिकित्सी जैव प्रौद्योगिकीय नवप्रवर्तन, अंतरण वाणिज्यीकरण के लिए वैश्विक एवं राष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र को निर्मित एवं संबद्ध करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

#### सहकारिता के क्षेत्र और दायरे में शामिल हैं

- बीआईआरएसी और टीडीबी नवाचार और व्यावसायिकरण के अंतर को समाप्त करने की दृष्टि से संयुक्त प्रयासों के लिए संयुक्त अंतर संगठनात्मक तंत्र को स्क्षम बनाएंगे।
- पारस्परिक रूप से जैव प्रौद्योगिकी परियोजनाओं पर सहमत होते हैं जो एक सुसंगत शासन संरचना की स्थापना के द्वारा निर्बाध मूल्यांकन और वित्त पोषण सहायता के लिए संबंधित संगठनात्मक दायरे में आ सकते हैं।
- पक्षकार प्रभावी धन जुटाने और प्रौद्योगिकी तत्परता अंतः राल को बढ़ाने के लिए अपनी संबंधित संगठनात्मक शक्ति से लाभ लेने के लिए समन्वय करेंगे।
- एमओयू की प्रचालनात्मक अवधि, वित्तीय दायित्वों और सहयोग की सीमा के संबंध में पारस्परिक समझ के लिए परस्पर संदर्भ के लिए परियोजनाएं तय की जाएंगी
- पक्षकारी ने इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से संयुक्त रूप से ज्ञान आधार, आंतरिक प्रक्रियाओं और परियोजना साधनों की संयुक्त पहल को सफल बनाने के लिए साझा करने पर सहमत हुए हैं।

## ड) गठबंधन

### i) ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस (जीआईटीए) 2011

भारत के औद्योगिक अनुसंधान और विकास प्रयासों के त्वरण में सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री व्यापार और उद्योग परिषद् के परिणामस्वरूप, ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस (जीआईटीए) की स्थापना 2011 में भारतीय उद्योग परिषद् (सीआईआई) और प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार के बीच पीपीपी जेबी के रूप में की गई।

जीआईटीए एक अभिनव मंच है जो प्रौद्योगिकी अंतराल मानचित्रित करता है, दुनिया भर में उपलब्ध तकनीकों का मूल्यांकन करता है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी-रणनीतिक सहयोग साझेदारी करता है। (जीआईटीए) औद्योगिक और संस्थागत भागीदारों को प्रभावी समतुल्यकरण और सहयोगी औद्योगिक अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए जोड़ता है, जिससे प्रौद्योगिकी विकास/अधिग्रहण/अनुकूलन/परिनियोजन के लिए वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराती है। आज की तारीख तक, जीआईटीए भारत सरकार की ओर से लगभग 150 मिलियन अमरीकी डॉलर का औद्योगिक आर एंड डी वित्त पोषण के लिए जिम्मेदार है और इसने सरकार द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक डॉलर के लिए आर एंड डी से लगभग दुगुना निजी निवेश को उत्प्रेरित किया है।

इन वर्षों में जीआईटीए सफलतापूर्वक भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों यथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, की विभाग (डीएसटी), इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईटीवाई), भारी उद्योग विभाग (डीएचआई), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई) की साझेदारी के तहत विभिन्न राष्ट्रीय और द्विपक्षीय औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण परियोजना का प्रबंधन कर रहा है। जीआईटीए बहुपक्षीय निकायों यथा यूरोपीय आयोग के साथ नवाचार पारिस्थिति की तंत्र को बढ़ाने के लिए सहयोग किया।

सहयोग में भारत की प्रौद्योगिकीय आकांक्षाओं की राष्ट्रीय प्रांसंगिकता के क्षेत्रों यथा ऊर्जा और परिवहन, उन्नत विनिर्माण, पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, रक्षा एवं वात अंतरिक्ष, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) जल प्रौद्योगिकी, जलशोधन, विलवणीकरण, सिंचाई प्रौद्योगिकी, अपशिष्ट जल शोधन और प्रबंधन

आदि सहित किफायती देखभाल, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

जीआईटीए ने जीआईटीए एडिनोवेशन एक्सचेंज (जीआई-एक्ससी) के साथ भारतीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के साथ अपने जुड़ाव को भी व्यापक और औपचारिक रूप दिया। जीआईएक्ससी एक अनूठा, आभासी मंच है, जो नवाचार वर्णपट के कारकों के लिए साझेदारी, प्रौद्योगिकियों, आईपी सेवाओं और नवाचार के लिए वित्त हेतु विश्वसनीय संपर्क बनाने का प्रयास करता है।

### ii) मिलेनियम अलायंस (एमए)

मिलेनियम अलायंस (एमए) कार्यक्रम 2011 में संयुक्त रूप से टीडीबी युनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएड) और फंडेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिककी) द्वारा संयुक्त रूप से प्रचलित किया गया जो नवाचारों की पहचान जीव एवं स्तरोनयन के लिए मंच के रूप में कार्य करता है, जो अर्थव्यवस्था के निचले पायदान पर सुधार लाता है। यह गठबंधन स्वास्थ्य, बुनियादी शिक्षा, जल और स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा/कृषि और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए वैश्विक विकास के लिए एक नवाचार साझेदारी के रूप में बनाया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नवाचार का लाभ बीओपी आबादी को मिल सके। बाद में, मंच में युके के डीएफआई, डी, आईसीसीओ सहयोग, आईसीआईसीआई फाउंडेशन फॉर इनक्लूसिव ग्रोथ, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और फेसबुक को शामिल किया गया।

प्रत्येक एमए पार्टनर ने सामाजिक उद्यमों को सहायता देने के उद्देश्य से वित्तीय और ज्ञान संसाधनों के साथ लाया गया जो परिवर्तनकारी परिवर्तन ला सकता है। एमए भारत और दुनिया भर में अर्थव्यवस्था के निचले पायदान पर के लोगों को लामान्चित करने वाली विकास की चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत में विकसित और परीक्षण किए जा रहे अभिनव संसाधनों की पहचान और स्तरोनयन करने के लिए भारतीय रचनात्मकता, विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने के लिए एक समावेशी मंच था। एमए एक ऐसा नेटवर्क था जो नवोन्मेषकों को वित्तीय और अन्य सहायता हेतु विभिन्न सामाजिक नवप्रवर्तनकर्ताओं, परोपकारी संगठनों, सामाजिक उद्यम पूंजीपतियों, एंजेल निवेशकों, दाताओं, सेवा प्रदाताओं, और कांफॉरेट संगठन को एक साथ लाने के लिए एक नेटवर्क था। 5 वर्षों की अवधि के लिए 25 मिलियन अमरीकी डॉलर कोष की स्थापना की गई जिसमें टीडीबी ने 25.00 करोड़ रु. (प्रति वर्ष 5 करोड़ रूपये) का अंशदान किया। कार्यक्रम के दौरान, नवप्रवर्तकों को मूल वित्त पोषण, अनुदान उदभवन नेटवर्किंग के अवसर, व्यापार

सहायता, ज्ञान विनिमय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई जो इक्विटी, ऋण एवं अन्य पूंजी तक पहुँच आसान बनाती है।

कार्यक्रम ने वर्ष 2018-19 में अपने 5 दौरे पूरे किए। इन दौरों के माध्यम से, कार्यक्रम ने ₹ 86.7 करोड़ की वित्त पोषण सहायता से 124 नवोन्मेषी परियोजनाओं की प्रत्यक्ष सहायता की। इन परियोजनाओं ने लाखों जीवन को छुआ है, किसान आय में वृद्धि, उन्हें प्रारंभिक कक्षा की शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, उनके घरों के लिए ऊर्जा, सस्ती और डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच प्रदान की। सहायित उद्यम बाहरी निधि जुटाने के लिए एक उत्प्रेरक कोष के रूप में दिए गए अनुदान का लाभ उठाने और साथ ही व्यापक और टिकाऊ परियोजना कार्यान्वयन के लिए साझेदारी विकसित करने में सक्षम थे। एमए द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को भारत के 21 राज्यों में लागू किया जा रहा है। निधि 11 देशों में सहयोग सहायता भी कर रही है। एमए अफ्रीका, (केन्या, रवांडा, युगांडा, इथियोपिया, बुर्किना फ्रांसी और मलावी) और दक्षिण एशिया (अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल) में अपने नवाचारों को दोहराने और स्तरोन्नयित करने को 22 भारतीय कंपनियों को सहायता देने का अपनी तरह का एकमात्र कार्यक्रम है। एमए ने सामाजिक उद्यमियों की नई शैली को एक बड़ी प्रेरणा प्रदान की है जो अंतिम पायदान पर सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ, स्तरोन्नयन योग्य अभिनव मॉडल विकसित कर रहा है। इस कार्यक्रम ने दुनिया भर में सामाजिक क्षेत्र में उद्यमिता विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

### च) प्रौद्योगिकी दिवस और राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति

#### प्रौद्योगिकी दिवस

प्रति वर्ष 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व पर जोर देता है और छात्रों को करियर के विकल्प के रूप में विज्ञान को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। 11 मई, 1998 को राजस्थान के पोखरण में आयोजित किए गए आपरेशन शक्ति (पोखरण-II) के प्रथम पांच परीक्षणों की वर्षगांठ मनाने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जा रहा है। पोखरण परमाणु परीक्षण के अलावा, इस दिन प्रथम स्वदेशी विमान हंसा-3 का बंगलौर में परीक्षण किया गया था और उसी दिन भारत ने त्रिशुल मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इन सभी उपलब्धियों को देखते हुए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने के लिए चुना गया था।

यह दिवस अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भागेदारी प्राप्त करने के लिए उद्योग से

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के साथ सशक्त साझेदारी बनाने और शैक्षिक संस्थानों के साथ ज्ञान नेटवर्क बनाने के लिए प्रेरित करता है।

#### राष्ट्रीय पुरस्कार

इस दिन को मनाने के लिए टीडीबी ने राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की है। यह पुरस्कार विभिन्न उद्योगों को अभिनव स्वदेशी प्रौद्योगिकी के सफल वाणिज्यीकरण के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार 11 मई, 1999 को प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर, मेसर्स शान्ता बायोटेक्नीक्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को भारत के माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा "रिकामिनेंट डीएनए आधारित हेपेटाइटिस-बी वैक्सीन" के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए दिया गया था।

इस पुरस्कार में 10.00 लाख रु. का नकद पुरस्कार और एक ट्रॉफी दिया जाता है। यदि कोई प्रौद्योगिकी अलग-अलग संस्थाओं द्वारा विकसित और वाणिज्यीकृत की गई है, तो दोनों अलग-अलग पुरस्कार प्राप्त करने के योग्य हैं। 2016 में, पुरस्कार की मात्रा बढ़ाकर ₹ 25.00 लाख कर दी गई।

अगस्त 2000 में, टीडीबी ने एसएसआई इकाई को ₹ 2.00 लाख का नकद पुरस्कार और एक ट्रॉफी देने की शुरुआत की जिसने सफलतापूर्वक प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद का वाणिज्यीकरण किया है। पहला एसएसआई पुरस्कार 11 मई 2001 को दिया गया। पुरस्कार की संख्या एवं मात्रा वर्ष 2011 में बढ़ाकर क्रमशः तीन और ₹ 5.00 लाख कर दी गई। 2016 में इस पुरस्कार का नाम बदलकर 'एमएसएमई' पुरस्कार कर दिया गया और मात्रा को बढ़ाकर ₹ 15.00 लाख कर दी गई।

वर्ष 2017-18 के दौरान, टीडीबी ने वाणिज्यीकरण की संभावनाओं वाली नई होनहार प्रौद्योगिकी के लिए ₹ 15 लाख के पुरस्कार की एक नई श्रेणी और स्टार्ट-अप के लिए ट्रॉफी की शुरुआत की।

तब से प्रौद्योगिकी दिवस समारोह के दौरान 11 मई 2018 को पुरस्कार की तीन श्रेणियां दी गई हैं:

- स्वदेशी प्रौद्योगिकी के सफल वाणिज्यीकरण के लिए दो राष्ट्रीय पुरस्कार-₹ 25.00 लाख का नकद पुरस्कार और एक औद्योगिकी प्रतिष्ठान को ट्रॉफी, जिसने स्वदेशी प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास और वाणिज्यीकरण किया है; यदि प्रौद्योगिकी निर्माता और वाणिज्यीकरण करने वाले संगठन अलग-अलग हैं, तो हर कोई नकद पुरस्कार और ट्रॉफी के लिए पात्र होगा।
- प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद के सफल वाणिज्यीकरण के लिए पांच राष्ट्रीय पुरस्कार (एमएसएमई पुरस्कार) ₹ 15.00

लाख के नकद पुरस्कार और प्रत्येक एमएसएमई के लिए ट्रॉफी जिसने स्वदेशी तकनीक पर आधारित उत्पाद का सफलतापूर्वक वाणिज्यीकरण किया है।

- तीन प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप पुरस्कार— ₹ 15.00 लाख का नकद पुरस्कार और वाणिज्यीकरण की क्षमता के साथ प्रगतिशील नई तकनीक के लिए एक ट्रॉफी।

### छ) "प्रस्ताव आमंत्रण" जारी करना

बोर्ड भारत सरकार की नीतियों एवं पहलों यथा "मेक इन इंडिया" "स्टार्ट-अप इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" आदि के अनुसार विभिन्न कार्यनीतिक क्षेत्रों में टीडीबी-सहायक नवप्रवर्तन-चालित प्रौद्योगिकी केंद्रित परियोजनाओं की विषय वस्तु के लिए स्थानीय उद्योग को लोकप्रिय बनाने के प्रयोजनार्थ विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वप्रेरित दृष्टिकोण अपनाता है और समय-समय पर प्रस्ताव आमंत्रण करता है।

### ज) विवाद समाधान समिति (डीआरसी)

टीडीबी की स्थापना के बाद से, कई मामलों को प्रौद्योगिकी विफलता या व्यावसायिकरण विफलता के कारण तनावग्रस्त घोषित किया गया है। इन एनपीए/तनावग्रस्त मामलों, पूर्व-मुकदमेबाजी और मुकदमेबाजी के मामलों के कारण, बोर्ड ने 2015 के अंत में "विवाद समाधान समिति (डीआरसी)" का गठन करके ऐसे मामलों का समाधान करने के लिए एक तंत्र शुरू किया।

डीआरसी का उद्देश्य कंपनियों को टीडीबी को देय राशि के भुगतान से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। तथापि, डीआरसी टीडीबी द्वारा पहले से ही शुरू की गई कानूनी कार्यवाही में कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करता है। डीआरसी की सिफारिशों को बोर्ड के समक्ष मंजूरी के लिए रखा

जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से कई कंपनियों के साथ मुद्दों को सुलझाया गया और वसूली की गई।

### झ) परियोजना प्रस्तावों का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण

टीडीबी ने वर्ष 2017-18 के दौरान अपने "प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम (पीएमएस)" / <http://www.e-techcom.tdb.gov.in/> के माध्यम से "परियोजना प्रस्तावों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण" की सुविधा देकर पारदर्शी और कुशल कार्य प्रक्रिया की दिशा में एक पहल शुरू की।

### ञ) प्रदर्शनी/गोष्ठी

टीडीबी से उपलब्ध वित्तीय सहायता के बारे में उद्योग, उद्यमियों और आरएंडडी संस्थाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए, वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न क्रियाकलाप जैसे कि अन्य संगठनों के सहयोग से सहभागी बैठक/प्रदर्शनियों में भागीदारी की गई।

### ट) सोशल मीडिया प्लेटफार्म का निर्माण

कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और अधिक संपर्कता प्राप्त करने और वर्तमान परिदृश्य में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के महत्व पर विचार करने के लिए, टीडीबी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की आवश्यकता महसूस हुई और विभिन्नानुसार अपने आधिकारिक पृष्ठ बनाए।

फेसबुक: [www.facebook.com/tdbgoi](https://www.facebook.com/tdbgoi)

लिंकडइन: <https://www.linkedin.com/in/technology-development-board/>

ट्विटर: <https://twitter.com/tdbgoi>





टीडीबी-वर्ष  
एक दृष्टि में

# टीडीबी – वर्ष एक दृष्टि में

## टीडीबी- वर्ष एक दृष्टि में

वर्ष 2019-20 में, टीडीबी ने विभिन्न औद्योगिकी प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पांच करार किये। इन करारों के माध्यम से, टीडीबी ने कृषि, इंजिनियरिंग, ऊर्जा और अपशिष्ट उपयोग, स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हुए ₹ 70.32 करोड़ के कुल परियोजना परियध्य में से ₹ 29.87 करोड़ की प्रतिबद्धता व्यक्ति की।

## वर्ष 2019-20 में प्राप्त आवेदन

टीडीबी को ₹ 391.80 करोड़ की कुल परियोजना लागत और टीडीबी की ₹ 116.87 करोड़ की सहायता के साथ विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों से वित्तीय सहायता के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान 23 आवेदन प्राप्त हुए।

23 आवेदनों का राज्य-वार आवंटन नीचे दिए अनुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवेदनों की संख्या	कुल अनुमानित लागत	टीडीबी से मांगी गई सहायता
1	आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	5	161.18	26.65
2	कर्नाटक	5	68.83	29.35
3	महाराष्ट्र	1	2.27	2.27
4	तमिलनाडु	3	24.13	6.50
5	दिल्ली	1	4.97	2.48
6	उत्तर प्रदेश	4	49.56	20.61
7	हरियाणा	3	77.26	27.00
8	चंडीगढ़	1	3.60	1.80
	<b>कुल</b>	<b>23</b>	<b>391.80</b>	<b>116.66</b>

आवेदनों का क्षेत्र-वार वितरण निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	क्षेत्र	आवेदनों की संख्या	कुल अनुमानित लागत	टीडीबी से मांगी गई सहायता
1	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	6	176.20	33.02
2	अभियांत्रिकी	5	77.09	28.00
3	सूचना प्रौद्योगिकी	5	44.31	21.07
4	कृषि	2	3.50	1.50
5	सड़क परिवहन	2	24.28	11.27
6	ऊर्जा एवं अपशिष्ट उपयोग	2	40.18	11.80
7	रक्षा एवं नागर विमानन	1	26.24	10.00
	<b>कुल</b>	<b>23</b>	<b>391.80</b>	<b>116.66</b>

प्राइवेट लिमिटेड एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियों इत्यादि से प्राप्त आवेदनों का विवरण निम्न प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

क्रम सं०	आवेदनों की संख्या	कुल अनुमानित लागत	टीडीबी से मांगी गई सहायता
1	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	23	391.80
2	पब्लिक लिमिटेड कंपनी	-	-
3	अन्य	-	-
	<b>कुल</b>	<b>23</b>	<b>391.80</b>

## वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान हस्ताक्षर किए गए करार

वर्ष के दौरान, टीडीबी ने नवप्रवर्तक प्रौद्योगिकियों के निर्माण एवं वाणिज्यीकरण के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को सहायित करने की दृष्टि से वित्तीय सहायता के लिए 5 नये करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	परियोजना का नाम	क्षेत्र
1.	मेसर्स आईमिनिंग बिट टेक इंडिया प्रा. इवेट लिमिटेड, हरियाणा	"जल बचतकारी आर ओ आधारित शुद्धीकरण प्रौद्योगिकी का निर्माण एवं वाणिज्यीकरण"	ऊर्जा एवं अपशिष्ट उपयोग
2.	मेसर्स एनारोबिक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, बिजनौर	"मल जल शोधन संयंत्र जगजीतपुर हरिद्वार स्थित मल जल अर्थात् बायो गैस संयंत्र से बायो सीएनजी का निर्माण एवं वाणिज्यीकरण"	ऊर्जा एवं अपशिष्ट उपयोग
3.	मेसर्स अगस्ता सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा	"संकेत लाईफ"	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
4.	मेसर्स अर्पण न्यूट्रीशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	"मानव स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए जीरो इरुकिक मसटर्ड टेक्नोलॉजी का वाणिज्यीकरण"	कृषि
5.	मेसर्स यशराज बायो टेक्नोलॉजी लि. मिटेड, मुंबई	"रोग प्रतिरूपण जैव निर्धारक अन्वेषण एवं औषध विषेलापन जॉब के लिए सर्वशक्तिमान स्टेमकोशिका प्रौद्योगिकी के माध्यम से बने उत्पादों एवं सेवाओं का निर्माण एवं वाणिज्यीकरण"	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

## संवितरण

टीडीबी ने वित्त वर्ष 2019-20 में कार्यशील एवं नई परियोजनाओं और अन्य योजनाओं के लिए ₹ 128.74 करोड़ की राशि संवितरित की। इसमें ऋण के रूप में ₹ 128.37 करोड़, अनुदान के रूप में ₹ 0.11 करोड़ और निवेश के लिए वीसीएफ को ₹ 0.26 करोड़ शामिल हैं।

## पूरी की गई परियोजनाएं

टीडीबी द्वारा सहायित निम्नलिखित कंपनियों ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पूरी की गई अपनी परियोजनाओं की घोषणा की।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	परियोजना का नाम	क्षेत्र
1.	मेसर्स ग्रॉसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई	"बिरला एक्सेल सोल्वेंट स्पन सेल्यूलोजिक फाइबर प्लांट"	वस्त्र
2.	मेसर्स इधोरवेक्स मीडियाटेक प्राइवेट लिमिटेड, बंगलोर	"स्काईनेट प्रोद्योगिकी टी वी प्लेटफॉर्म का निर्माण एवं वाणिज्यीकरण"	सूचना प्रौद्योगिकी
3.	मेसर्स केन बायोसिस प्राइवेट लिमिटेड, पुणे	"पराली उपयोग प्रौद्योगिकी का निर्माण एवं वाणिज्यीकरण: स्वस्थानेत्तरित एवं संभारणीय पराली अपघटन (एसआरएसडी)"	कृषि
4.	मेसर्स बिटकैम अस्पॉल्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड गुवाहाटी असम	"सड़क निर्माण एवं अनुरक्षण में कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी"	रासायनिक
5.	मेसर्स इन्फोडिबल डिवाइस प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ एवं नोएडा	"केथेटर पुनः प्रक्रमण तंत्र का निर्माण एवं वाणिज्यीकरण"	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
6.	मेसर्स आईटोम इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कोयम्बटूर	"पोर्टेबल एक्स-रे मशीन का निर्माण एवं वाणिज्यीकरण"	सूचना प्रौद्योगिकी
7.	मेसर्स वैम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	"आरएफ सीकर्स का विकास एवं वाणिज्यीकरण"	अभियांत्रिकी

## ऋण अदायगी का निपटान

वर्ष के दौरान, टीडीबी द्वारा वित्त पोषित निम्नलिखित कंपनियों ने अपने ऋण की अदायगी और करार के अनुसार ऋण लेख का निपटान किया है:-

- मेसर्स एक्वाएग्री प्रोसेसिंग प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली
- मेसर्स एम्पीयर वीहिकल प्रा. लिमिटेड कोयंबटूर
- मेसर्स यशराज बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड, नवी, मुंबई
- मेसर्स सिलवान इनोवेशन लैब्स प्रा. लि. बैंगलोर
- मेसर्स इनक्रेडिबल डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़
- मेसर्स जैन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, हैदराबाद
- मेसर्स केबीवी एग्री फार्म प्राइवेट लिमिटेड, कश्मीर (जम्मू एवं कश्मीर)
- मेसर्स वायवा लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, बेलगाम
- मेसर्स सांख्या टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, चैन्नई
- मेसर्स सुदर्शन बायोटेक लिमिटेड, हैदराबाद

## प्रौद्योगिकी दिवस

निम्नलिखित विजेताओं को निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अंतर्गत राष्ट्रीय पुरस्कार – 2019 के लिए पुरस्कार घोषित किया गया है:

पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कार विजेता (कंपनी का नाम)
स्वदेशी प्रौद्योगिकी के सफल वाणिज्यीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार	<ul style="list-style-type: none"> <li>• कंपनी: मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई के साथ, (प्रौद्योगिकी प्रदाता: सीएसआईआर – भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून पेट्रोकार्बाइड युक्त अप्रसंस्कृत भजित गैसोलिन भंजन से अधिक शुद्धता वाले बेजिन प्राप्ति द्वारा बेजिन लीन गैसोलिन के उत्पादन के लिए)</li> </ul>
स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद के सफल वाणिज्यीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (एमएसएमई पुरस्कार)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मेसर्स निम्ना सरग्लास टेक्नीक्स प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद को "गलित सिलिका रेडोम्स के निर्माण एवं आपूर्ति" के लिए</li> <li>• मेसर्स तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड, बेंगलुरु को तेजस जी पी ओ एन प्रोडक्ट फेमिली (टी जे 1400 ओ एल टी एंड टी जे 2100 एन ओ एन टी)</li> <li>• मेसर्स मेटल पावर एनालिटिकल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को प्रकाशीय उत्सर्जन वर्णमित (ओ ई एस) एवं प्रौद्योगिकी के लिए</li> </ul>
वाणिज्यीकरण के लिए क्षमतायुक्त उद्दीयमान नई प्रौद्योगिकी हेतु प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मेसर्स प्रतिमेश लेब प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु को "रक्त कोशिका गणन के लिए गृह जॉय साधन" के लिए</li> <li>• मेसर्स कोयो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु को "सान ए न्योनेटल ब्रेथिंग सर्पेट डिवाइस के लिए"</li> <li>• मेसर्स त्वस्त मेन्चूफेक्चरिंग सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु को "3डी प्रिंटर्स के निर्माण प्रक्रिया के स्वचालन के लिए"</li> <li>• मेसर्स इन्फीकोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा को "कृषि/मंडी स्तरीय सौर शीत भंडारण को सक्षम करने के लिए रेट्रोफिटिबल थर्मल स्टोरेज"</li> <li>• मेसर्स इनोवेशन इमेजिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु को "चिकित्सीय प्रतिबिम्बन – अनुकूलित विकिरण के लिए कंथलीब"</li> </ul>

तथापि, दिल्ली में दिनांक 12 मई, 2019 को लोकसभा चुनाव के कारण राष्ट्रीय पुरस्कार के प्रस्तुतीकरण हेतु पुरस्कार समारोह इस वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकी दिवस आयोजित नहीं किया जा सका।

### वेंचर कैपिटल फंडस (वीसीएफ) में भागीदारी

इस वर्ष प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 8.48 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। वीसी प्रबंधक, निधियों की मात्रा और टीडीबी के अंशदान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(₹. करोड़ में)

क्र. सं.	फंड का नाम	निवेश प्रबंधक	कुल निधि	टीडीबी की प्रतिबद्धता	प्रतिपूर्ति के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्ति
1.	एसेंट इंडिया फंड	यूटीआई वेंचर फंडस मैनेजमेंट फंडस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बंगलूर	739.25	75.00	1.46
2.	बायो टेक्नोलॉजी वेंचर फंड (बीवीएफ)	एपीआईबीसी वेंचर कैपिटल लिमिटेड, हैदराबाद	155.00	30.00	2.50
3.	वेंचरेस्ट टी इंएनईटी फंड-II	वेंचरेस्ट फंडस एडवाइजर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, चैन्नई	54.45	15.00	--
4.	एसएमई टेक्नोलॉजी वेंचर फंड	गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड (जीवीएफएल), अहमदाबाद	89.32	15.00	--
5.	एसएमई टेक फंड आरबीसीएफ-II	राजस्थान एसेंट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान	150.00	15.00	0.34
6.	इंडिया ओपर्टयूनिटीज फंड (आईओएफ)	सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड, मुंबई	421.30	25.00	1.44
7.	सीफ इंडिया एग्री बिजनेस फंड	सीफ इंडिया इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई	106.25	25.00	1.87
8.	मल्टी सेक्टर सीड कैपिटल फंड	ब्लूम वेंचर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई	100.00	25.00	0.77
9.	आईटी कंप वेंचर ट्रस्ट-फंड-I	आईटीकेप वेंचर्स एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई	238.20	25.00	0.10
10.	इंडियन फंड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी	सीआईआईई, आईआईएम, अहमदाबाद	125.00	10.00	--

### इनोवेटिव वेंचर्स एवं टेक्नोलॉजीस फॉर डेवलपमेंट (इंवेंट) कार्यक्रम

टीडीबी ने अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) यू के की साझेदारी से वित्त वर्ष 2015-18 में इनोवेटिव वेंचर्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट (इंवेंट) कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम को प्रौद्योगिकीय एवं प्रक्रियोन्मुख दोनों समावेशी नवप्रवर्तक समाधान को सहायित करने की दृष्टि से मंच बनाने हेतु बनाया गया था जिसका निम्न आय वाले वर्गों अर्थात् अर्थव्यवस्था के निचले पायदान पर रहने वाले लोगों पर सकारात्मक सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पड़ता है।

इन्वेंट कार्यक्रम मुख्य रूप से समावेशी नवप्रवर्तकों के बारे में है और यह भारत के निम्न आय वाले 8 राज्यों (एल आई एस) (उ० प्र० म० प्र०, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल) में अर्थव्यवस्था के निचले पायदान पर रहने वाले एक मिलियन लोगों के लाभ के लिए समावेशी नवप्रवर्तक जीवन चक्र में चुनौतियों एवं बाधाओं को दूर करेगा।

इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय परिव्यय अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) यूके की सहायता से 05 वर्षों की अवधि के लिए तकनीकी सहायता के रूप में £5 मिलियन है। कार्यक्रम का अधिदेश कार्यक्रम की अवधि में निम्न आय वाले 08 राज्यों में कम से कम 50 निवेश सुलभ व्यापार विकसित करना और 160 उद्यमिताओं को उद्भवित करना है। वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत से लेकर आज तक कार्यक्रम के अंतर्गत 150 उपक्रमों को उद्भवित किया गया है जिनमें से 48 कंपनियों ने लगभग ₹ 118 करोड़ की अनुवर्ती निधि जुटाई है। अनुवर्ती निधीयन साझेदारों में अब तक सरकारी और गैर-सरकारी निकाय दोनों यथा इन्टेलकैप, आमनीवोर, एजीकंडर, जोमेटो, टाटा ट्रस्ट, इन्कोएज, अंकुर केपिटल, ग्रे मेटर्स केपिटल, गुगल यस बैंक एचडीएफसी, एस बी आई और एंजेल इन्वेस्टर्स सम्मिलित हैं।

यह उल्लेखनीय है कि 150 उद्भवित उपक्रमों में 33.3% कृषि एवं संबद्ध व्यापार 20.2 %, स्वास्थ्य एवं देखभाल 14.7% शिक्षा, 5.4 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र, 19.4 % आजीविका एवं कौशल विकास से संबंधित है। इसके अतिरिक्त 150 उपक्रमों में से आईआईटी कानपुर ने 36 उपक्रमों, आईआईएम-सीआईपी ने 40 उपक्रमों, केआईआईटी टीबीआई ने 34 और स्टार्ट-अप ओएसिस ने अन्य 33 उपक्रमों को उद्भवित किया है वास्तविक रूप से सृजित प्रभाव की दृष्टि से अनुमान है कि निम्न आय वाले राज्यों में इन इवेंट कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित 5000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के साथ लगभग 6.2 लाख लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है।

### प्रस्ताव आमंत्रण-“फाइटिंग कोविड-19”

टीडीबी ने दिनांक 20.03.2020 को “कोविड-19 से लड़ाई” हेतु प्रौद्योगिकीय रूप से नवप्रवर्तक समाधानों के लिए भारतीय कंपनियों और उपक्रमों से आवेदन आमंत्रित करते हुए प्रस्ताव आमंत्रण जारी किया है। इस प्रस्ताव आमंत्रण का उद्देश्य जॉब, प्रयोगशाला सहायता, संक्रमण नियंत्रण एवं नियंत्रण, संभारतंत्र, जोखिम संचार और विशेषकर कोविड-19 के प्रसार को रोकने, निवारित करने के लिए गंभीर रूप से बीमार रोगियों के अलगाव और वेंटिलेटर प्रबंधन की दृष्टि से तैयारी में राष्ट्र की मुख्य क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित ऐसी प्रौद्योगिकी वैश्विक स्तर पर इस महामारी के अधानक प्रसार की वजह से विश्वस्तर

पर अल्प मात्रा में उपलब्ध थी। इस प्रकार, टीडीबी ने निम्न लिखित श्रेणियों के अंतर्गत समाधान निर्माण के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

- किफायती मास्क जो हवा से विषाणु को अभिग्रहित कर सकता है और सांस के साथ आने वाले छोटे-छोटे कणों को अवशोषित कर सकता है।
- किफायती थर्मल स्केनिंग
- वृहत क्षेत्र में सफाई एवं किटाणु विनाश (कॉच, सिरामिक, लकड़ी, वस्त्र आदि जैसी उपलब्ध सतहों के लिए स्थिर वैद्युत छिड़काव एवं पराबैंगनी उपचार सहित)
- जैव सूचना विज्ञान एवं जॉब
- त्वरित एवं यथार्थ नैदानिक किट (कागज-आधारित और अन्य देखभाल उपकरण)
- संपर्करहित प्रविष्टि के लिए एआई और आईओटी आधारित समाधान
- ऑक्सीजेनेटर्स एंड वेंटिलेटर्स (किफायती एवं वहनीय)
- अथवा कोई अन्य संबंधित प्रौद्योगिकी

भारतीय उद्योग और स्टार्ट-अप पारितंत्र ने प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) द्वारा आमंत्रण का उत्साहपूर्वक प्रत्युत्तर दिया। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल, 2020 थी।

### सोशल मीडिया आउटरीच

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड विश्व भर के सभी कार्यशील सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अद्यतित रहने के लिए प्रयासरत है। फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, के माध्यम से वृहत पहुँच एवं नेटवर्किंग हासिल करने के लिए टीडीबी ने इस वर्ष इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया। इससे टीडीबी वैज्ञानिक नवप्रवर्तकों के क्षेत्र में अवसरों की तलाश करने के लिए कंपनियों, शिक्षा जगत उद्योगपतियों एवं अन्य संबंधित संगठनों के साथ जोड़ने में समर्थ हो जाएगा।

इंस्टाग्राम: [www.instagram.com/technologydevelopmentboard/](http://www.instagram.com/technologydevelopmentboard/)

### आभार

टीडीबी, अपने बोर्ड के सदस्यों के समय, प्रायासों, मार्गदर्शन एवं योगदान के लिए आभारी है।



हस्ताक्षरित करार

## ‘जल बचतकारी आर ओ आधारित शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी का विनिर्माण एवं वाणिज्यीकरण’



मेसर्स आईमिनविट टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा

क्षेत्र: उर्जा एवं अपशिष्ट उपयोग

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने ₹ 341.60 लाख की कुल परियोजना लागत में से ₹ 148.00 लाख की ऋण सहायता के लिए “जल बचतकारी आर ओ आधारित शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी का विनिर्माण एवं वाणिज्यीकरण” शीर्षक वाली अपनी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मेसर्स आईमिनविट टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा के साथ दिनांक 24 जून, 2019 को करार किया है। करार के अनुसार यह परियोजना 30 जून, 2020 को या उसके पहले पूरी कर ली जाएगी।

यह कंपनी स्टार्ट अप इंडिया और स्टेड अप इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त तथा मालवीय नवप्रवर्तन, उद्भवन एवं उद्यमिता केन्द्र (एमसीआईआईई – टीबीआई, आईआईटी – बीएचयू, वाराणसी) द्वारा मूल सहायता प्राप्त आईआईटीबीएचयू, एलमनस इनिशिएटिव स्टार्ट-अप है। इसे इन्वेंट कार्यक्रम, एसआई आईसी, आईआईटी कानपुर द्वारा सहायित एवं निर्धारित किया गया है।

### परियोजना और उत्पाद के बारे में

कंपनी का इरादा व्युत्क्रम पराशरण (आर ओ) आधारित वाटर प्यूरीफायर बनाने का है जो जल की बचत करेगा और यह लागत एवं उर्जा क्षम है। इनकी नवप्रवर्तक प्रौद्योगिकी लगभग 70 प्रतिशत उत्पाद जल प्रदान करना है। कंपनी ने प्रक्रिया और विभिन्न प्रकार के फिल्टर विकसित किए हैं जो मानदंड को नियंत्रित कर सकता है और किफायती रूप में प्रक्रम को स्थिरीकृत कर सकता है। ऐसी दाबकृत तंत्र को संस्थापन एवं स्थिरीकरण इस जल शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी का मुख्य नवप्रवर्तन



है। प्रतिस्पष्टी लाम यह है कि इस प्रौद्योगिकी ने जल की बर्बादी एवं उर्जा उपभोग को 50 प्रतिशत कम कर दिया है। उनके उत्पाद का ब्रांड का नाम “एक्यूविओ” है।

एक्यूविओ वाटर प्यूरीफायर दो रूपों: 100 एल पी एच एवं 50 एलपीएच में निर्मित किया गया है। इस उत्पाद के मुख्य लक्ष्य समूह शैक्षिक संस्थान, संगठन, कार्यालय आदि हैं।

परियोजना लागत  
**341.60** लाख रुपये  
ऋण सहायता  
**148.00** लाख रुपये



## “मल जल उपचार संयंत्र जगजीतपुर, हरिद्वार स्थित मल जल आधारित बायोगैस संयंत्र से बायो सीएनजी का निर्माण एवं वाणिज्यीकरण”



मेसर्स एनारोबिक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, बिजनौर

क्षेत्र: उर्जा एवं अपशिष्ट उपयोग

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने ₹ 431.70 लाख की कुल परियोजना लागत में से ₹ 215.00 लाख की ऋण सहायता के लिए “मल जल उपचार संयंत्र जगजीतपुर, हरिद्वार स्थित मल जल आधारित बायोगैस संयंत्र से बायो सीएनजी का निर्माण एवं वाणिज्यीकरण” शीर्षक वाली अपनी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मेसर्स एनारोबिक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, बिजनौर के साथ दिनांक 8 जुलाई, 2019 को करार किया है। करार के अनुसार, यह परियोजना दिनांक 30 जून, 2020 को अथवा उसके पहले पूरी कर ली जाएगी।

यह औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (बीआईपीपी) द्वारा प्रमाणित नव प्रवर्तित स्टार्ट अप कंपनी है।



### परियोजना और उत्पाद के बारे में

इस परियोजना में, कंपनी जगजीतपुर, हरिद्वार स्थित मल जल उपचार संयंत्र में उपलब्ध मल जल कीचड़ पर आधारित बायो सी एन जी बनाने की दृष्टि से हरिद्वार में अपना पहला बायो गैस संयंत्र स्थापित करना चाहती है। कंपनी का प्रस्ताव बायो गैस बनाने, बायो सी एन जी बनाने एवं बायो सीएनजी की बिक्री से राजस्व अर्जित करने हेतु बायो गैस को शोधित करने का है। बायो सी एन जी निर्माण के लिए दो अलग-अलग प्रक्रमों अर्थात् पाचन के जरिए आधान से बायो गैस का निर्माण और (II) बायो गैस का बायोसीएन जी में शुद्धिकरण/उन्नयन की आवश्यकता होती है। अपेक्षित प्रौद्योगिकी एटमॉस पावर प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद और भारतीय तेल अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, फरीदाबाद से प्राप्त की जा रही है।

कंपनी वाहन ईंधन के उपयोग के लिए बायो सीएनजी के उत्पादन के माध्यम से राजस्व अर्जित करेगी और इसके लिए वे बायो सीएनजी भराई केन्द्र स्थापित कर रही हैं। राजस्व सृजन का अन्य घटक डाइजेस्टर इफ्लुएट से जैविक उर्वरक का उत्पादन है और उसके लिए शीर्ष उर्वरक कंपनियों अर्थात् इफको एवं कृष्को के साथ संबद्ध हो रही हैं।

परियोजना लागत  
**431.70 लाख रुपये**  
ऋण सहायता  
**215.00 लाख रुपये**



## संकेत लाइफ



मेसर्स अगत्सा साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा

क्षेत्र: स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने ₹ 1148.00 लाख की कुल परियोजना लागत में से ₹ 391.00 लाख की ऋण सहायता के लिए "संकेत लाइफ" नामक अपनी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मेसर्स अगत्सा साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड नोएडा के साथ दिनांक 20 सितम्बर, 2019 को करार किया है। करार के अनुसार, यह परियोजना दिनांक 31 मार्च, 2021 को पूरी कर ली जाएगी।

मेसर्स अगत्सा साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड मार्च, 2010 में स्थापित स्टार्ट-अप कंपनी है।



### परियोजना और उत्पाद के बारे में।

कंपनी ने माक्सि के आकार वाला "संकेत लाइफ" नामक नवप्रवर्तक उपकरण का स्वदेशी अभिकल्पन एवं निर्माण किया है जो कमिक 12 लेडईसीजी जॉच कर सकता है। इस उपकरण को ब्लूटूथ के जरिए स्मार्टफोन से जोड़ा जा सकता है तथा इसीजी को कंपनी के अंतः निर्मित मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मोबाइल के स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। तैयार की गई इसीजी रिपोर्ट को अगत्सा के समेकित क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से समीक्षा के लिए हृदयरोग चिकित्सक के पास भी भेजा जा सकता है। यह अपने लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है और इसके लिए पेशेंट केवल्स अथवा जेल की आवश्यकता नहीं होती है। संकेत लाइफ एन्ड्रोयड/आईओएस प्लेटफॉर्म के लिए क्लाउड एवं एसडीके आधारित समेकन उपलब्ध कराने की दृष्टि से अगत्सा की स्वदेशी विकसित साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। प्रोटोटाइप "संकेत लाइफ" का निर्माण जेएसएसएटीई नोएडा स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के उद्भवक में वर्ष

2015-16 के दौरान किया गया था। उस समय से, कंपनी बेहतर विशिष्टता वाले अपने उत्पाद को वाणिज्यीकृत करने के लिए अपने आर एंड डी और व्यापार विस्तार पर व्यापक रूप से कार्य कर रहा है। टीडीबी को प्रस्तुत की गई अपनी परियोजना में कंपनी की योजना "संकेत लाइफ 2.0" को वाणिज्यीकृत करने और विनिर्माण प्रक्रियाओं में स्वचलन प्रवर्तित कर अपनी विनिर्माण क्षमताओं को मौजूदा 200 यूनिट प्रतिमाह से बढ़ाकर 10000 यूनिट प्रति माह करने की है।

परियोजना लागत

**1148.00** लाख रुपये

ऋण सहायता

**391.00** लाख रुपये



## 'मानव स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए जीरो इरुकिक मस्टर्ड प्रौद्योगिकी का वाणिज्यीकरण'



मेसर्स अर्पण न्यूट्रीशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली

क्षेत्र: कृषि

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने ₹ 495.00 लाख की कुल परियोजना लागत में से ₹ 233.00 लाख की ऋण सहायता के लिए 'मानव स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए जीरो इरुकिक मस्टर्ड प्रौद्योगिकी का वाणिज्यीकरण' शीर्षक वाली अपनी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मेसर्स अर्पण न्यूट्रीशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ दिनांक 4 अक्टूबर, 2019 को करार किया है। करार के अनुसार परियोजना 31 जुलाई 2021 को या उसके पहले पूरी कर ली जाएगी।

यह कंपनी उन कृषि उद्यमियों द्वारा एक पहल है जो पोषण सुरक्षा के लिए कृषि और खाद्य में नवप्रवर्तन विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह वंशानुगतिकी प्रभाग द्वारा सहायित और आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली के जेड. टीएम-बीपीडी द्वारा उद्भवित है। इसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा भी सहायित किया गया। करार के अनुसार परियोजना 31 जुलाई 2021 को या उसके पहले पूरी कर ली जाएगी।

### परियोजना और उत्पाद के बारे में

कंपनी अभिज्ञात परिरक्षित उत्पाद तंत्र विकसित करेगी, संविदा कृषि को बढ़ावा देगी और आयातित केनोला तेल से बेहतर सरसों तेल प्रदान करते हुए अपना तीखापन प्रतिधारित करके केनोला गुणवत्तायुक्त सरसों तेल के उत्पादन के लिए समेकित 'बीज से तेल' स्थापित की। जेडईएम सरसों तेल ओलेइक, लेनोलीक ओमेगा 8 और लिनोलेनिक ओमेगा-3 वसीय अम्लों जो मानव स्वास्थ्य के



लिए आवश्यक वसीय अम्ल (ईएफए) है, में दुगुनी मात्रा में रहेगा। जेडईएम सरसों तेल में अन्य बांछनीय वसीय अम्लों का उत्तम संयोजन है जो मानव कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल और एचडीएल का संतुलन बनाए रखने में एमयूएफए और पीयूएफए का उल्लेखनीय रूप से उच्चतर स्वास्थ्य विषयक लाभ प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि यह वयस्कों में मायोकार्डियल फाइब्रोसिस और बच्चों में लिपिडोसिस जैसे रोगों की संभावना को काफी कम कर देता है जिससे मानव स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन सुनिश्चित होता है।

परियोजना लागत  
**495.00** लाख रुपये  
ऋण सहायता  
**233.00** लाख रुपये



## ‘रोग अभिकल्पक जैव निर्धारक अन्वेषण एवं औषध विधेलापन जाँच के लिए सर्वशक्तिमान स्टेम कोशिका प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्युत्पन्न उत्पादों एवं सेवाओं का निर्माणाधीन एवं वाणिज्यीकरण’

मेसर्स यशराज बायो टेक्नोलॉजी लिमिटेड, मुम्बई



क्षेत्र: स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने ₹ 4615.36 लाख की कुल परियोजना लागत में से ₹ 2000.00 लाख की ऋण सहायता के लिए ‘रोग अभिकल्पक जैव निर्धारक अन्वेषण एवं औषध विधेलापन जाँच के लिए सर्वशक्तिमान स्टेम कोशिका प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्युत्पन्न उत्पादों एवं सेवाओं का निर्माण एवं वाणिज्यीकरण’ शीर्षक वाली अपनी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मेसर्स यशराज बायो टेक्नोलॉजी लिमिटेड, मुम्बई के साथ दिनांक 26 फरवरी, 2020 को करार किया है। करार के अनुसार यह परियोजना दिनांक 31 मार्च, 2021 को अथवा उसके पहले पूरी कर ली जाएगी।

मेसर्स यशराज बायो टेक्नोलॉजी लिमिटेड स्वदेशी स्रोत से निदान शास्त्रीय महत्व वाले एंटीजन एवं प्रोटीन के विनिर्माण के लिए कार्य कर रहा है।

### परियोजना और उत्पाद के बारे में

कंपनी का लक्ष्य इस सहायता से स्टेम कोशिकाओं, स्टेम कोशिकाओं के व्युत्पादों, शुद्धीकृत प्रोटीन एंटीजन और संवृद्धि कारकों के निर्माण के लिए अवसंरचना एवं सुविधाओं की स्थापना करना है। इनका उपयोग निदान-पूर्व औषध अन्वेषण, नैदानिकी और चिकित्सा के लिए किया जाएगा। इससे कैंसर उत्तक, भारत के सोमोटिक अथवा स्टेम कोशिकाओं से रोग और वंशविशिष्ट कोशिकीय व्युत्पन्नो का निर्माण हो सकेगा। इनका उपयोग कैंसर के अंतः पात्र रोग प्रतिरूपण के लिए किया जाएगा जो भारतीय आबादी में इस रोग के प्रगमन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त,



कंपनी वक्ष कैंसर वाले रोगियों से नैदानिक प्रतिदर्शों का जैव बैंक भी बनाएगी जो भारतीय महिलाओं और विश्व भर में रुग्णता और मृत्यु का सर्वाधिक प्रचलित कारण है। साथ ही, इन सुविधाओं का उपयोग उच्च स्तरीय औषध अन्वेषण एवं विधेलापन जाँच के लिए भी किया जाएगा। औषध अन्वेषण से कैंसर के लिए अभिनव एवं वैकल्पिक औषधि का निर्धारण हो पाएगा। विधेलापन जाँच से चिकित्सीय अभिक्रिया और रोगियों को दी गई दवाई के बाहरी प्रभाव का पूर्वानुमान करने में मदद मिलेगी। इस जानकारी से उनके रोग की संभावित अवधि के आधार पर प्रत्येक रोगी के लिए व्यक्तिगत उपचार हेतु इसे संभव बनाने में सहायता मिलेगी।

परियोजना लागत

**4615.36 लाख रुपये**

ऋण सहायता

**2000.00 लाख रुपये**





पूर्ण की गई परियोजनाएं

# ‘बिरला एक्सेल सॉल्वेंट स्पन सेल्यूलोज फाइबर संयंत्र’

मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई

वस्त्र

मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ने स्वदेश निर्मित प्रौद्योगिकी पर आधारित ‘बिरला’ एक्सेल ब्रांड नाम के अंतर्गत वाणिज्यीकरण के लिए बिरला सेल्यूलोजिक कैंम्स, खराच, जिला-मरुछ, गुजरात स्थित सॉल्वेंट स्पन तृतीय पीढ़ी वाले सेल्यूलोजिक फाइबर लायोसेल के लिए 50 टीपीडी क्षमता वाली उत्पादन लाइन स्थापित की है।

बिरला एक्सेल सूती के साथ मिलाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तृतीय पीढ़ी वाला फाइबर लायोसेल है क्योंकि यह पुनःप्रक्षालन पर वर्ण संबद्ध चमक एवं मृदुपन प्रदान कर सूती रेशे का निष्पादन संवर्द्धित करता है। इसका उपयोग इसकी उच्च शुष्क एवं आद्र प्रबलता के कारण बॉटम वीवर एवं घरेलू वस्त्र जैसे कई अनुप्रयोगों में शत प्रतिशत मिश्रण में भी किया जाता है।

तीसरी पीढ़ी का यह सेल्यूलोजिक रेशा, ‘बिरला’ एक्सेल का विनिर्माण बहुलक विलयन बनाने की दृष्टि से कार्बनिक विलायक में सेल्यूलोज (पल्प शीट) को विलयित करके किया जाता है जिसे सेल्यूलोज रेशा बनाने हेतु जलीय पुनर्सृजन में वायु अंतराल के माध्यम से बुनाई की जाती है। मेसर्स ग्रासिम ने सतत रूप से अपने लायोसेल प्रक्रिया समझ में वृद्धि की है जिससे विशेषकर डोप निर्माण, कटाई एवं विलायक पुनःप्राप्ति तंत्र के क्षेत्रों में डिजाइन एवं अभियंत्रण में सुधार हुआ है। विलायक को वाणिज्यिक संयंत्रों में 99.7 प्रतिशत स्तर से अधिक हद तक पुनः प्राप्त एवं पुनःचक्रित किया जाता है। लायोसेल प्रक्रिया अन्य पुनर्सृजित सेल्यूलोज रेशों की विनिर्माण प्रक्रिया की तुलना में सर्वाधिक पर्यावरण हितैषी एवं हरित प्रक्रिया है। इस प्रौद्योगिकीय नवप्रवर्तन से पर्यावरण हितैषी मानव निर्मित रेशों की बढ़ती मांग को पूरा करने वाले अनुप्रवाहगामी वस्त्र एवं बुनाई वाले उद्योग को उल्लेखनीय लाभ होगा तथा एक्सेल रेशा आयात निर्भरता में कमी के साथ-साथ देश में तकनीकी वस्त्रों की बढ़ती मांग के लिए संधारणीय कच्चा माल उपलब्ध होगा। उपभोग



की दृष्टि से एशिया प्रशांत वर्ष 2018 में वैश्विक लायोसेल बाजार में अभिभावी रहा। चीन और भारत जैसी उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में वस्त्र उद्योग की अनुकूल संवृद्धि से क्षेत्र में लायोसेल सूत बाजार के विकास के लिए अत्यंत उपयुक्त वातावरण पैदा हुआ है। हाल ही में, इसकी अधिक नमनीय प्रकृति के कारण स्वास्थ्य देखभाल अनुप्रयोग में लायोसेल सूत की मांग बढ़ रही है। लक्ष्य प्रमुख बाजारों में भारतीय उपमहाद्वीप और मध्यपूर्व सम्मिलित हैं।

यद्यपि यह संयंत्र 50 टीपीडी क्षमता के लिए बनाया गया है, फिर भी प्रस्तावित संयंत्र से इष्टतम उत्पादन को 45 टीपीडी तक निर्धारित रखा गया है। यह वाणिज्यिक रेशा भारतीय बाजारों के लिए खींची गई है।

‘बिरला’ एक्सेल सॉल्वेंट स्पन सेल्यूलोजिक फाइबर प्लांट नामक परियोजना स्थापित करने पर कुल निवेश ₹ 689.00 करोड़ निर्धारित किया गया और टीडीबी ने कुल ₹ 250.00 करोड़ का अवधि ऋण स्वीकृत किया। मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने परियोजना पूरी कर ली है और दिनांक 01.05.2019 से वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ कर दिया है। ऋण की अदायगी अप्रैल 2020 से शुरू होगी।

# 'स्काईनेट प्रोग्राममैटिक टीवी प्लेटफॉर्म का विकास एवं वाणिज्यीकरण'

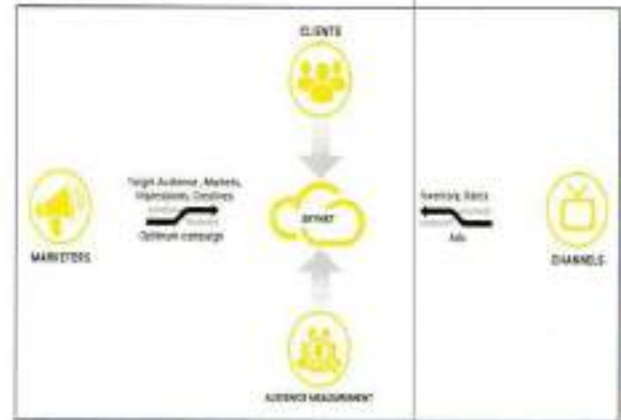
मेसर्स श्योरवेक्स मीडियाटेक प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलौर

आईटी

मेसर्स श्योरवेक्स जो एक मीडिया कन्वर्जेंस पायनियर है ने स्काईनेट को इन-हाउस आरएंडडी के माध्यम से विकसित किया है। यह एक पहले प्रकार का प्रोग्राम टेलीविजन विज्ञापन है। यह दोनों विज्ञापन दाताओं/एजेंसियों और प्रसारकों के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करके, एक दूसरे को खोजने और प्रसारण चैनलों पर अभियानों को सरल, व्यवस्थित और जवाबदेह तरीके से निष्पादित करने के लिए मुख्यधारा के टेलीविजन विज्ञापन के लिए पूरी प्रक्रिया को स्वचालित बनाता है।

श्योरवेक्स की नई पेशकश टेलीविजन विज्ञापन की दुनिया में प्रतिमान बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। प्रोग्रामेटिक विज्ञापन डिजिटल मीडिया में प्रमुख रहा है और यह अत्यधिक कुशल और जवाबदेह साबित हुआ है, लेकिन इसे अभी भी पहले टीवी पर एंड-टू-एंड सफलतापूर्वक लागू किया जाना है। स्काईनेट पहली बार, पारंपरिक टेलीविजन विज्ञापन की आयोजना, खरीद, माप और अनुकूलन विषयों के लिए एक ऑकड़ा संचालित, प्रीदयोगिकी आधारित सशक्तिकरण को सक्षम बनाता है। जो कि टेलीविजन विज्ञापन को सरल बनाने में इसके अनुप्रयोग से परे है।

परंपरागत रूप से टेलीविजन विज्ञापन योजना एक जटिल, समय लेने वाली प्रक्रिया रही है। इसके अलावा, योजनाकारों के लिए अपने अभियानों पर त्वरित आकड़ा प्राप्त करना भी मुश्किल होता है जिससे समय भी अधिक लगता है। स्काईनेट यह परिवर्तन करना चाहता है जिसमें परिष्कृत योजना एल्गोरिदम का उपयोग करके मजबूत



तकनीक के साथ ब्रांड टेलीविजन अभियान के पूर्ण और औसत दर्जे के कार्यान्वयन की गारंटी हो।

अपने नए जमाने की प्रीदयोगिकी और दूरगामी प्रभाव के साथ स्काईनेट ने, भारत में प्रमुख प्रसारकों और मीडिया एजेंसियों से पहले ही व्यापक रुचि प्राप्त की है और कंपनी ने पहले ही चुनिंदा ग्राहकों और भागीदारों के साथ प्रायोगिक सहभागिता शुरू कर दी है, जो पूर्ण पैमाने पर मंच के व्यावसायीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है।

परियोजना के कुल निवेश का मूल्यांकन ₹ 4709.00 लाख और टीडीबी ने ₹ 980.00 लाख का अवधि ऋण स्वीकृत किया। मेसर्स श्योरवेक्स ने परियोजना को पूरा कर लिया है और 23 अगस्त, 2019 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। ऋण की अदायगी 23 अगस्त 2020 से शुरू होगी।

# 'पराली उपयोग प्रौद्योगिकी का निर्माण एवं वाणिज्यीकरण: स्वस्थाने त्वरित एवं संधारणीय धान की पराली का अपघटन (एसएसआरएसडी)'

मेसर्स केनबायोसिस प्राइवेट लिमिटेड, पुणे



कृषि

मेसर्स केनबायोसिस प्राइवेट लिमिटेड, पुणे एक कृषि बायोटेक आधारित कंपनी है जो कृषि के लिए माइक्रोबियल आदानों के उत्पादन में लगी हुई है। इन हाउस आरएंडी के माध्यम से उन्होंने एक उत्पाद 'स्पीड कोम्पोस्ट' विकसित किया है जो एक जैविक खाद आधारित माइक्रोबियल कंसोर्टिया है जिसमें लिग्नी-सेल्यूलोज अपघटक कवक और जीवाणु होते हैं और एक वर्ष का शैलक जीवन काल है।

कवक ठोस अवस्था किण्वन द्वारा उत्पादित किया जाता है, जबकि जीवाणु को जलमग्न किण्वन की स्थिति में उगाया जाता है और इन रोगाणुओं के निष्क्रिय रूपों को जैविक रूपों को जैविक खाद वाहक के साथ मिलाया जाता है। उन्होंने माइक्रोब भोजन भी विकसित किया है जो चावल की भूसी पर प्रारंभिक उपनिवेशीकरण सुनिश्चित करने के लिए रोगाणुओं की प्रारंभिक वृद्धि को बढ़ाता है।

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली ज्वलन को अगली फसल (खरीफ/रबी) के लिए अपने खेत को तैयार करने के लिए एक पारंपरिक पद्धति में से एक माना जाता है। तथापि, यह पद्धति खराब वायु गुणवत्ता, खराब मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाता है और इसलिए भविष्य की फसल की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला उत्पाद अधिक महत्व का है क्योंकि यह सूक्ष्मजीव संस्कृतियों और अन्य तकनीकी आदानों आदि के उपयोग में चावल के भूसे के स्वस्थाने अपघटन दृष्टिकोण के उपयोग पर केंद्रित है। इस प्रौद्योगिकी का एक बड़ा लाभ यह है कि माइक्रोबियल कल्चर को सीधे मिट्टी में मिलाया जाता है, जहाँ वे सेल्यूलोज, स्टार्च और सिलिका रूपांतरण में सहायता करते हैं। इस प्रौद्योगिकी में मशीनरी और पानी का कम से कम उपयोग होता है। यह धान के पुआल के प्रबंधन के लिए किसानों के लिए एक आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प है और साथ ही जैविक अपशिष्ट वाता स्थिर खाद जो कि सड़न मुक्त और गैर विषैले है, को पुनःचक्रित करने के लिए



कड़ी मेहनत के पुनर्चक्रण द्वारा अधिक उपज और प्रदूषण उन्मूलन के उपायों के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखता है।

कंपनी ने वेस्ट टू वेल्थ पर भारत के कदम की मिस्तल प्रस्तुत की है। परियोजना के कुल निवेश का आंकलन ₹ 518.00 लाख किया गया था और टीडीबी ने ₹ 174.00 लाख के लिए सावधि ऋण एकत्रीकरण को मंजूरी दी थी। मेसर्स केनबायोसिस प्राइवेट लिमिटेड, पुणे ने परियोजना को पूरा कर लिया है और 31 अगस्त, 2019 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। ऋण की अदायगी 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगी।

# ‘सड़क निर्माण एवं अनुरक्षण में कोल्ड मिक्स प्रौद्योगिकी’



मेसर्स बिटकैम अस्फाल्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, गुवाहाटी

रसायन



घर के साथ कोल्ड मिक्स का प्रस्तुतीकरण



कोल्ड मिक्स का संघनन



कोल्ड मिक्स सड़क निर्माण सतह

मेसर्स बिटकैम अस्फाल्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (बीएटीएल) एक नई पीढ़ी की सड़क विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम है। यह सड़क निर्माण और रखरखाव में पर्यावरण के अनुकूल कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ग्रीन रोड दर्शन को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। मेसर्स बिटकैम ने सभी अनुप्रयोगों के लिए सड़कों के निर्माण एवं रख रखाव के लिए विशेष आधार पर केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआईआई) से इस कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी को अपनाया। कंपनी ने विभिन्न समय गुणवत्ता, समय पदार्थों के पूर्व-आदीकरण की आवश्यकता और पारंपरिक हॉट मिक्स प्रक्रिया आदि के लिए उपयोग किए गए विभिन्न मौजूदा सम्मिश्रक उपकरणों का उपयोग करना जैसे स्थल अनुप्रयोगों में क्षेत्र विषयक

घुनीतियों का समाधान करने की दृष्टि से अंतः प्रतिष्ठान अनुसंधान एवं विकास करके इस प्रौद्योगिकी में अनुवर्ती सुधार किए हैं जिससे समय की बचत हुई है और पर्यावरणीय प्रदूषण में काफी कमी आई है। कंपनी द्वारा तैयार कोल्ड बाइंडर विषयक पेटेंट प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना का कुल निवेश ₹ 1831.03 लाख निर्धारित किया गया और टीडीबी ने कुल ₹ 820.00 लाख का अवधि ऋण स्वीकृत किया। मेसर्स बिटकैम ने परियोजना पूरी कर ली है और दिनांक 30 सितम्बर, 2019 से वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ कर दिया है। ऋण की अदायगी 1 जुलाई 2020 से शुरू होगी।

# ‘कैथेटर रिप्रोसेसिंग सिस्टम का विकास एवं वाणिज्यीकरण’



मेसर्स इनक्रेडिबल डिवाइसिस प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

मेसर्स इनक्रेडिबल डिवाइसिस प्राइवेट लिमिटेड (आईडीपीएल) ने लागत प्रभावी कैथेटर रिप्रोसेसिंग सिस्टम सीआरएस प्रणाली विकसित की है, जो एक स्वचालित कंप्यूटर निर्देशित कैथेटर सफाई मशीन है जिसमें इनविल्ट सेल्फ टेरिस्टिंग और अंशशोधन होता है जो कैथेटर की सफाई सुनिश्चित करता है। (सीआरएस) इनविल्ट कंप्यूटर हर प्रक्रिया पर नजर रखता है और परिशुद्धता और सटीकता के साथ कैथेटर को प्रभावी ढंग से साफ करता है। यह कार्डिएक, न्यूरो, गैस्ट्रो और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले सभी प्रकार के कैथेटर को पुनः प्रक्रमित कर सकता है। कैथेटर विभिन्न आकार और प्रकार में आता है। इसलिए, उन्हें अलग-अलग सफाई मापदंडों जैसे कि पानी का दबाव, प्रवाह, मात्रा, बहु एंजाइम तनुकरण आदि की आवश्यकता होती है।

सीआरएस 1 चक्र में 12 कैथेटर तक पुनरावृत्ति कर सकता है। प्रत्येक कैथेटर इनविल्ट सेंसर के साथ एक समर्पित पोर्ट से जुड़ा होता है जो कैथेटर के प्रकार की पहचान करता है और तदनुसार सबसे अच्छी सफाई सुनिश्चित करने के लिए पूर्व उल्लिखित कैथेटरों को जांचता है। सीआरएस एक पेटेंट सफाई प्रक्रिया का उपयोग करता है जिसे डीएफसी (डायनामिक) प्ल्यूड फ्लोनिंग कहा जाता है। यह बायो फिल्म को तोड़ने के लिए लामिनायर, अशांत, महत्वपूर्ण संक्रमण कालीन और अशांत प्रवाह उत्पन्न करता है, एंजाइम को बांधने में मदद करता है, टूटने वाले फाइब्रिन के लिए महत्वपूर्ण दबाव उत्पन्न करता है और बहुत कुछ कैथेटर को पहले डीएफसी तकनीकी का उपयोग करके रासायनिक समाधान के साथ प्रवाहित किया जाता है जो प्रदूषण को



समाप्त करता है। एक बार जब, सीआरएस रासायनिक निशान हटाने के लिए पानी के साथ कैथेटर बंद कर देता है। यह फिर सूखी स्वच्छ हवा के साथ कैथेटर को सूखता है और उन्हें स्ट्रैलाइजेशन के लिए तैयार करता है।

अतुल्य उपकरणों ने 2.5 लाख से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों को लाभान्वित किया है। यह उत्पाद, सीआरएस (कैथेटर रिप्रोसेसिंग सिस्टम) का उपयोग भारत के 9 राज्यों के 14 अग्रणी अस्पतालों में किया जा रहा है। परियोजना के कुल निवेश का मूल्यांकन ₹ 104.80 लाख और टीडीबी ने ₹ 46.61 लाख स्वीकृत किया। मेसर्स इनक्रेडिबल डिवाइसिस प्राइवेट लिमिटेड ने परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया और नवंबर 2019 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया।



# ‘पोर्टेबल एक्स-रे मशीन का विकास एवं वाणिज्यीकरण’



मैसर्स आइटोम इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोयंबटूर

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

आइटोम एक्स-रे और उच्च वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स विषयक प्रोफाइल के साथ एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कंपनी है। कंपनी ने जीई मेडिकल सिस्टम और बीपीएल मेडिकल सिस्टम के लिए उत्पाद विकसित किए हैं। इसके अलावा, उन्होंने एक्स-रे पीढ़ी के लिए अपनी स्वदेशी तकनीकी का अनुसंधान और विकास किया है, जिसमें विद्युत, यांत्रिक, उच्च वोल्टेज, सामग्री और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उन्नत पद्धतियां शामिल हैं। कंपनी टीडीबी की सहायता से अभिनव एक्स-रे उत्पादों जैसे कि एक हाथ से संचालित बैटरी संचालित एक्स-रे मशीन आदि का उत्पादन करती है और बाजार में बिक्री करने के लिए सक्षम है।

सहायित परियोजना चार प्रकार के एक्स-रे इमेजिंग उपकरण के निर्माण और व्यावसायीकरण के लिए है, जिसमें शामिल है:

- पोर्टेबल हैंड हेल्ड एक्स-रे-यह एक बैटरी संचालित कॉम्पैक्ट एक्स रे मशीन है जिसे हाथ से संचालित और प्रचालित किया जा सकता है। यह उपकरण विशेष रूप से हेंटल इंट्राओरल रेडियोग्राफी के लिए डिजाइन किया गया है।
- हेंटल एक्स-रे के लिए डिजिटल इमेजिंग- पहले उत्पाद के पूरक के लिए कंपनी डिजिटल एक्स-रे सेंसर पर काम करती है। इसका उपयोग करके एक्स-रे इमेजिंग फिल्म बिहीन हो सकती है और स्वनिर्मित सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है।
- पोर्टेबल जनरल एक्स-रे- यह बहुउद्देशीय एक्स-रे उपकरण है। उपकरण को अत्यधिक गतिशील/वहनीय, सरल, संचालित करने के लिए, विश्वसनीय और बैटरी



Battery powered handheld portable Dental X-Ray

बैक-अप के साथ उपयोग करने के लिए बनाया गया है ताकि बिजली के बिना भी उपयोग किया जा सके है।

- फ्लोरोस्कोपी के लिए एक्स-रे-जनरेटर यह ओईएम उप-घटक उत्पाद है जो देश में कई सी-आर्म सिस्टम बिल्डरों द्वारा उपयोग किया जाता है।

परियोजना के कुल निवेश का मूल्यांकन ₹ 536.00 लाख और टीडीबी ने ₹ 203.00 लाख के कुल ऋण एकत्रीकरण को मंजूरी दी थी। कंपनी ने परियोजना को पूरा कर लिया है और 31 दिसम्बर, 2019 से वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ कर दिया है। ऋण की अदायगी 1 जनवरी 2021 से शुरू होगी।

# 'आरएफ सीकर्स का विकास एवं वाणिज्यीकरण'



मेसर्स वैम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद

अभियांत्रिकी

आधुनिक वायुजनित प्रणालियों में लक्ष्य को अन्वेषित एवं निर्धारित करने में बारहमासी फायर एवं फॉरगेट क्षमता की आवश्यकता होती है। इन कार्यों का निष्पादन आरएफ संवेदक द्वारा किया जाता है जिसका व्यापारिक नाम आरएफ सीकर्स है। यह सीकर्स अनिवार्य रूप से इन्हें पर्यावरण संरक्षण प्रदान करने वाला राडॉम युक्त वायुजनित प्रणाली के शीर्ष पर संस्थापित उच्च प्रौद्योगिकी वाला माइक्रोवेव है।

ये आकार में छोटा और कम वजन वाले होते हैं। ये सीकर्स विभिन्न वायु जनित प्रणालियों की सख्त स्थिति, वजन एवं परिवर्तनशील बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से जटिल स्वरूप वाला और अत्यधिक अनुकूलित होते हैं।

कंपनी द्वारा निर्मित आरएफ सीकर बहुल पीआरएफ प्लेटफॉर्म की क्षमता वाला स्पंदित डॉप्लर रडार है। इस एनटीना को प्रक्षेपास्त्र की पिंड गति के बायजूद लक्ष्य की दृष्टि रेखा अनुरक्षित रखने की दृष्टि से संस्थापित किया जाता है।

आरएफ सीकर कोण, वेग और परास की दृष्टि से लक्ष्य का पता लगा सकता है। कोण, वेग और परास में दिए गए नाम के आधार पर, यह सीकर लक्ष्य का पता लगता है। बाद में इस पर केन्द्रित हो जाता है और बाद में अन्वेषक मोड में कार्य करने

लगता है। प्रेषण संकेत का सृजन एक्साइटर द्वारा परिशुद्ध स्थानीय दोलक और प्रणाली के पीआरएफ स्पेक्ट्रम का उपयोग करके समनुगत रूप से किया जाता है।

जब सीकर का निर्माण किया जा रहा था, उसी समय सहायताकारी प्रौद्योगिकी यथा मोटर, इनकोडर्स, गाइरोस, स्लॉटेड एरे एन्टीना डिजाइन, विरचन एवं ब्रेजिंग, एमएमआईसी वर्णक संचालन, बॉडिंग आदि जैसी सर्वो-नियंत्रण स्थिरीकरण प्रणाली का भी निर्माण किया गया। वीईएम ने आरएफ सीकर्स, एन्टीना, सिग्नल प्रोसेसिंग बोर्ड, रडार एंड कंट्रोल एसओसी, सर्कुलेटर, 4 चैनल यूब्ल्यू आईएफ रिसेवर्स, एक्साइटर्स, 4 वाट का बेड ट्रांसमिटर डब्ल्यू जी रोटेरी ज्वाइंट, इएल/एजेड ड्राइव्स, डवेल सर्वो एम्पलीमेंस के उप तंत्रों का सफलतापूर्वक निर्माण किया।



वाईएम टेक्नोलॉजी के प्रतिदिन न्यूनतम दो सीकर, पीसीबीए के लिए अनन्य एसएमटी लाइन, उच्च परिशुद्धता वाला सीएनसी यंत्र 8000 वर्गफीट, स्वच्छ कक्ष सुविधा, माइक्रोवेव विरचन, आरएफ एवं एम डब्ल्यू उपकरण (40 गीगा हर्टज तक), एचवी एवं पीवी सामग्री, जाँच के लिए इंएसएस सुविधाओं के अतिरिक्त सघन परास और एचआईएलएस के लिए एनाकोइफ चेम्बर्स बनाने की दृष्टि से आरएफ सीकर्स उत्पादन के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया।

परियोजना का कुल निवेश ₹ 5900.00 लाख निर्धारित किया गया और टीडीबी ने कुल ₹ 2500.00 लाख का अवधि ऋण स्वीकृत किया था। मेसर्स वीईएम टेक्नोलॉजीज ने परियोजना पूरी कर ली है और दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 से प्रचालन आरंभ कर दिया है। कंपनी 1 जुलाई 2018 से ही ऋण की अदायगी कर रही है।





प्रोत्साहक क्रियाकलाप

### ग्लोबल बायो-इंडिया समिट 2019 (21-23 नवंबर, 2019)

टीडीबी ने ग्लोबल बायो-इंडिया समिट 2019 में भाग लिया, जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और एयरोसिटी, नई दिल्ली स्थित इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) द्वारा आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन जैव प्रौद्योगिकी हितधारकों, विनियामक निकायों, केन्द्रीय और राज्य मंत्रालयों, एसएमई, बड़े उद्योगों, जैव समूहों, अनुसंधान संस्थानों, निवेशकों, और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था।



शिखर सम्मेलन का उद्घाटन माननीय केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा किया गया। सम्मेलन करने के दौरान टीडीबी के प्रतिनिधियों ने नवप्रवर्तक स्टार्ट-अप मालिकों और उद्योगपतियों के साथ विचार-विमर्श किया और उन्हें टीडीबी द्वारा प्रदान की जाने वाली निधीयन व्यवस्था के बारे में बताया।

### 8वां जीआईटीए स्थापना दिवस (28 नवंबर, 2019)

टीडीसी ने 28 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एलायंस (जीआईटीए) के 8वें स्थापना दिवस में भाग लिया था। स्थापना दिवस को 'मेकिंग इंडिया फ्यूचर रेडी' में प्रदर्शित किया गया था। डॉ. हर्षवर्धन, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान मंत्री, मुख्य अतिथि थे और ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एलायंस (जीआईटीए) द्वारा समर्थित 15 सफल परियोजनाओं को सम्मानित किया गया। ये परियोजनाएं स्मार्ट परिवहन प्रबंधन से लेकर जैव चिकित्सा प्रौद्योगिकियों और स्मार्ट जल गुणवत्ता निगरानी समाधान सहित अन्य क्षेत्रों से संबंधित थीं।



स्पेन, इजराइल और कनाडा को समर्पित तीन विशिष्ट सत्रों का आयोजन द्विपक्षीय प्रौद्योगिकी सहयोग और उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए भी किया गया था। जीआईटीए स्थापना दिवस को प्रो. के. विजयराघवन, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रो. आशुतोष शर्मा, सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डॉ. नीरज शर्मा, सचिव, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, श्री एस. के. बार्बेराय, प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय सहयोग, डीएसटी और विभिन्न अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ उद्योग अग्रणी द्वारा भी संबोधित किया गया। इसके अलावा, ब्राजील फिनलैंड, इटली, स्वीडन, ताइवान और यूके की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के साथ-साथ कनाडा, इजरायल, कोरिया और स्पेन के प्रतिनिधिमंडल थे।

### भारत बायोटेक रोटारिक्स 5डी® 2019 (3 दिसम्बर, 2019)

टीडीबी ने रोटारिक्स वैक्सीन रोटारिक्स 5डी® के एक नए संस्करण के प्रवर्तन में भाग लिया, जो इसके पहले के मौखिक टीकाकरण खंड का एक छोटा खुराक रूप है जिसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर संग्रहित किया जा सकता है। इस प्रवर्तन का उद्घाटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने किया।



मेसर्स भारत बायोटेक, टीडीबी द्वारा विलत पोषित की जाने वाली प्रारम्भिक कंपनियों में से एक थी। हेपेटाइटिस बी के लिए पुनः संयोजक टीका उत्पादन के लिए कंपनी को टीडीबी से वित्तीय सहायता मिली, जिसे वर्ष 1998 में सफलतापूर्वक प्रवर्तित किया गया था।

### नैसकॉम-डीएससीआई वार्षिक सूचना सुरक्षा सम्मेलन में दक्षता संबंधी कार्यशाला (3 दिसम्बर, 2019)

टीडीबी ने नैसकॉम-डीएससीआई द्वारा आयोजित वार्षिक सूचना सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2019 में भाग लिया। इस कार्यशाला ने मंथन और सुरक्षित स्वचालित और एआई समर्थित नेटवर्क के आगामी संस्करण का मुकाबला करने के लिए सुझावों की एक सूची तैयार करने सहित गतिविधियों की एक श्रृंखला को उजागर किया।



श्री मनीष चौधरी, वैज्ञानिक डी, टीडीबी ने श्रोताओं को संबोधित किया और एआईएसएस कार्यशाला के दौरान सुरक्षित स्वचालित और एआई सक्षम नेटवर्क निर्माण करने के बारे में बात की। टीडीबी के प्रतिनिधियों ने साइबर सुरक्षा क्षेत्र में विभिन्न उद्यमियों के साथ बातचीत की और टीडीबी की वित्तपोषण प्रक्रिया विषयक जानकारी का आदान-प्रदान किया।

### भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 को आयोजित भारतीय आर एंड डी पारिस्थितिकी कौन्क्लेव

टीडीबी ने (सीआईआई) द्वारा आयोजित इंडियन आर एंड डी इकोस्टिम कौन्क्लेव में भाग लिया। इस कौन्क्लेव का उद्देश्य भारत के आर एंड डी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और आंकड़ा विषयक कमियों को दूर करके ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) 2020 में भारत की अंतरराष्ट्रीय श्रेणी में सुधार करना था। टीडीबी ने विभिन्न उद्यमियों के साथ बातचीत की और टीडीबी के वित्त पोषण तंत्र के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान किया।



### भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां सत्र (3 जनवरी, 2020)

टीडीबी ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107 वें सत्र में भाग लिया, जिसे 3 से 7 जनवरी, 2020 के दौरान कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जीकेवीके कैम्पस, बेंगलूर, कर्नाटक में आयोजित किया गया और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास पर केन्द्रित था।



माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 3 जनवरी, 2020 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। टीडीबी ने टीडीबी के विभिन्न वित्त पोषण मॉडल के बारे में प्रतिनिधियों को सूचित करने की दृष्टि से इस मंच का उपयोग किया।

## मेसर्स सिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड 2020 द्वारा विकसित ग्रेडिंग और सॉर्टिंग मशीन का उद्घाटन (28 जनवरी, 2020)

टीडीबी ने मेसर्स सिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित ग्रेडिंग और सॉर्टिंग मशीन के उद्घाटन समारोह में 28 जनवरी, 2020 को भाग लिया। मेसर्स सिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद को फलों और सब्जियों के लिए ग्रेडिंग और सॉर्टिंग मशीन नामक परियोजना के लिए टीडीबी द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है।



कंपनी ने हरियाणा के माननीय कृषि मंत्री श्री जे. पी. दलाल और भारत में इजरायल के राजदूत डॉ. रॉन मलका की अनुग्रहपूर्ण उपस्थिति में, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, घरींडा, हरियाणा में एक एकीकृत पैक हाउस के लिए अपनी ग्रेडिंग मशीन को सफलतापूर्वक स्थापित किया है।





प्रशासन

## वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित

प्रीद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा 12 में यह निर्धारित किया गया है कि बोर्ड पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का पूरा ब्यौरा देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। प्रीद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम की धारा 13 (4) के अनुसार, बोर्ड को केन्द्र सरकार को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ अपने लेखा की लेखा परीक्षित प्रति प्रस्तुत करना होता है।

वर्ष 2018-19 के लिए प्रीद्योगिकी विकास बोर्ड के वार्षिक लेखों की अंकेक्षित प्रति सहित वार्षिक रिपोर्ट, क्रमशः 10.12.2019 और 10.02.2020 को राज्य सभा और लोकसभा के समक्ष रखी गई।

## नया पदधारक

भारतीय सेना के कर्नल राजेश जैन (सेवानिवृत्त) ने 1 सितंबर, 2019 को प्रीद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) में निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। कर्नल राजेश जैन (सेवानिवृत्त) ने सेना में 33 साल तक ज्यादातर प्रशासन, तकनीकी और वित्तीय क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर काम किया है।

## राजभाषा का कार्यान्वयन

राजभाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, टीडीबी आधिकारिक पत्र में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित कर रहा है। टीडीबी में सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि राजपत्र अधिसूचना, वार्षिक रिपोर्ट, रिक्ति सूचना, और परियोजना वित्त पोषण दिशानिर्देश आदि हिंदी और अंग्रेजी में मुद्रित होते हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान, हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन नियमित आधार पर किया गया। हिंदी परखवाड़ा/हिंदी दिवस भी सितंबर, 2019 के महीने में मनाया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिता जैसे कि श्रुतिलेख, निबंध लेखन, कविता, भाषण, अनुवाद आदि का आयोजन किया गया।





वर्ष 2019–20 के लिए लेखा  
परीक्षित वार्षिक विवरण

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2020 की स्थितिनुसार तुलन-पत्र

(राशि रु. में)

	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
<b>कॉरपस / कैपिटल फंड और दायित्व</b>			
कॉरपस / कैपिटल फंड	1	146852,37,882	134695,57,301
रिजर्व और सरप्लस	2	-	-
निर्धारित / इनडॉवमेंट फंड	3	463,51,775	1432,13,644
सुरक्षित ऋण और लेनदारी	4	-	-
असुरक्षित ऋण और लेनदारी	5	-	-
आस्थगित क्रेडिट दायित्व	6	-	-
वर्तमान दायित्व और प्राक्धान	7	7734,99,891	582,58,593
<b>कुल</b>		<b>155050,89,548</b>	<b>136710,29,538</b>
<b>परिसम्पत्तियाँ</b>			
निर्धारित परिसम्पत्तियाँ	8	66,77,633	68,68,735
निर्धारित इनडॉवमेंट फंड में निवेश	9	65,99,000	65,99,000
निवेश – अन्य	10	14019,52,366	18359,96,145
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि	11	140898,60,549	118215,65,658
विविध खर्च (छूट न दिए जाने अथवा समायोजित न किए जाने की सीमा तक)			
<b>कुल</b>		<b>155050,89,548</b>	<b>136710,29,538</b>
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24	-	-
आकस्मिक दायित्व और लेखों पर टिप्पणियाँ	25	-	-

-४-  
(राजेश जैन)  
निदेशक  
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

-४-  
(डॉ. नीरज शर्मा)  
सचिव  
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

-४-  
(प्रो. आशुतोष शर्मा)  
अध्यक्ष  
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

(राशि रु. में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्री / सेवाओं से आय	12		
अनुदान / सस्किडी	13	9838,34,331	10380,31,997
फीस / अंशदान	14	-	-
निवेश से आय (ईयरमावर्ड/इनडॉवमेंट में निवेश पर आय)	15	-	-
राजस्व, प्रकाशन आदि से आय	16	44,87,232	62,82,547
अर्जित ब्याज	17	6360,54,565	5879,02,506
अन्य आय	18	3,03,563	598,34,725
निर्मित वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और कार्य प्रगति पर	19		
<b>कुल (क)</b>		<b>16246,79,691</b>	<b>16920,51,775</b>
<b>व्यय</b>			
स्थापना व्यय	20	335,32,639	274,93,743
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	3521,08,711	605,82,807
अनुदान, सस्किडी आदि पर व्यय	22	10,84,242	11,08,267
ब्याज	23	209,24,330	-
मूल्यहास (अनुसूची 8 के अनुरूप वर्ष के अंत में सकल जोड़)		11,03,455	12,28,970
<b>कुल (ख)</b>		<b>4087,53,377</b>	<b>904,13,787</b>
<b>व्यय पर आय में अधिकता (क-ख)</b>		<b>12159,26,314</b>	<b>16016,37,988</b>
पूर्व अवधि समायोजन		(2,45,734)	(185,86,680)
निवेश के हानि के लिए प्रावधान			
सामान्य आरक्षित कोष में अंतरण		-	-
कॉरपस फंड में दिया गया अतिरिक्त शेष		<b>12156,80,580</b>	<b>15830,51,308</b>
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक दायित्व और लेखा टिप्पणियां	25		

-ह-  
(राजेश जैन)  
निदेशक  
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

-ह-  
(डॉ. नीरज शर्मा)  
सचिव  
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

-ह-  
(प्रो. आशुतोष शर्मा)  
अध्यक्ष  
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

(राशि रु. में)

प्राप्तियाँ		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
<b>आरम्भिक शेष:</b>			
i)	अल्पावधि जमा में निवेश	4995,00,000	2000,00,000
ii)	सुलभ नकद	23,520	36,408
	<b>बैंक में रोकड़</b>		
क)	बैंक में शेष	759,89,345	2449,90,971
ख)	बैंक में शेष-डीएफआईडी इन्वेंट	1366,14,643	1162,09,187
<b>प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग निधि</b>			
i)	टी डी फंड	9800,00,000	10000,00,000
ii)	फाइटिंग कोविड-19 के लिए निधि	7500,00,000	-
iii)	अल्पावधि जमा पर ब्याज	334,75,287	209,24,330
iv)	ऋण पर ब्याज	764,94,764	642,59,498
v)	राजस्व पर ब्याज	2,95,247	8,03,520
vi)	ऋण वसूली के खिलाफ लंबित समायोजन	-	537,79,000
vii)	ऋण की अदायगी	6333,72,600	3285,40,326
viii)	राजस्व	44,87,232	63,25,887
ix)	दान	3,00,000	1,00,100
x)	अव्ययित अनुदान वापिस आया	38,34,331	380,31,997
xi)	बचत खातों पर ब्याज (ईपीएफ खाते सहित)	86,65,931	152,86,632
xii)	वीसीएफ फंड से प्राप्त आय	-	595,66,726
xiii)	विविध प्राप्तियाँ	3,563	1,67,899
xiv)	सुरक्षा जमा / अग्रिम धन प्राप्त / अन्य	1,64,231	21,14,625
xv)	मल्टी सेक्टर सीड फंड	76,55,900	960,00,000
xvi)	यूटीआई एसैंट इंडिया फंड	146,31,293	-
xvii)	आरवीसीएफ	34,34,150	147,17,787
xviii)	जीवीएफएल	-	-
xix)	इक्विटी प्राप्ति	656,68,800	-
xx)	सिडबी वैचर फंड	144,18,678	137,96,582
xxi)	वैचर ईस्ट टीनेट फंड	-	696,18,695
xxii)	इंडियन फंड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी (सी आई आई ई)	-	321,54,028
xxiii)	आईवी केप वैचर ट्रस्ट फंड-1	10,34,438	142,16,626
xxiv)	एपीआईडीसी वैचर फंड	250,00,000	652,14,000
xxv)	सीफ-इंडिया फंड	186,63,888	58,47,619
xxvi)	डीएफआईडी इन्वेंट परियोजना के लिए प्राप्ति	-	1823,46,693
xxvii)	डी एफ आई डी इन्वेंट बचत ब्याज	31,38,224	30,80,455
	<b>कुल</b>	<b>33568,66,065</b>	<b>26481,29,591</b>

-ह-  
(राजेश जैन)  
निदेशक  
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

-ह-  
(डॉ. नीरज शर्मा)  
सचिव  
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

-ह-  
(प्रो. आशुतोष शर्मा)  
अध्यक्ष  
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियाँ एवं भुगतान का लेखा

(राशि रु. में)

भुगतान		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
<b>स्थापना व्यय</b>			
i)	वेतन	316,67,445	265,03,428
ii)	यात्रा व्यय (घरेलू)	17,73,934	30,23,147
iii)	यात्रा व्यय (अंतर्राष्ट्रीय)	-	1,41,983
iv)	कर्मचारी कल्याण खर्च	77,000	67,000
v)	चिकित्सा व्यय	2,23,558	5,09,718
vi)	प्रतिनियुक्ति के लिए पेंशन अंशदान	-	11,60,124
<b>कार्यालय व्यय</b>			
i)	टेलीफोन/टैलेक्स	20,66,491	19,80,122
ii)	डाक टिकट	55,443	54,927
iii)	पेट्रोल, तेल एवं लूब्रीकेन्ट्स	41,422	1,88,344
iv)	मरम्मत कार्य एवं अनुरक्षण	12,80,715	10,56,179
v)	उपभोज्य स्टोर्स एवं मुद्रण	12,09,624	7,76,731
vi)	समाचार पत्र एवं पत्रिका	36,123	25,797
vii)	मनोरंजन एवं अतिथि सत्कार	1,90,132	1,66,083
viii)	बैठकों पर व्यय	15,33,468	19,52,570
ix)	विज्ञापन एवं प्रचार	63,26,171	55,82,603
x)	प्रौद्योगिकी दिवस पर खर्च	6,96,212	20,86,809
xi)	विविध खर्च	6,59,475	7,61,270
xii)	राष्ट्रीय पुरस्कार	-	170,00,000
xiii)	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	885	6,116
xiv)	दिविधिक प्रभार	44,78,038	52,55,524
xv)	परिसम्पत्ति प्रबंधन प्रभार	71,96,785	47,29,272
xvi)	विशेषज्ञों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	26,04,299	33,71,869
xvii)	विशेषज्ञों एवं सदस्यों को मानदेय	55,00,880	30,19,900
xviii)	सदस्यता शुल्क	23,600	23,600
xix)	लेखा परीक्षा शुल्क	77,850	2,15,056
xx)	किराया	85,36,700	73,60,017
xxi)	अन्य विभागों को पुनर्वसूली का प्रेषण	-	-
xxii)	सुरक्षा जमा एवं कर्मचारी को अग्रिम राशि	46,505	3,48,000
xxiii)	शुल्क एवं कर	4,60,031	4,19,091
xxiv)	नवीनीकरण एवं पुनर्संज्जा	-	14,75,348
<b>बोर्ड खर्च</b>			
i)	सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	24,457	1,24,076

ii)	शुल्क एवं बोर्ड की बैठक पर खर्च	1,43,645	78,571
<b>पूँजीगत व्यय</b>			
i)	अचल संपत्तियां	9,12,353	3,43,428
<b>संवितरण</b>			
i)	ऋण	12837,12,000	16372,50,000
ii)	अनुदान	10,84,242	11,08,267
iii)	दिए गए अनुदान पर ब्याज	209,24,330	-
iv)	सिडबी वीसीएफ	-	362,62,758
v)	सीफ इंडिया एग्री बिजनस फंड	5,77,473	49,38,761
vi)	इंडियन फंड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी (सीआईआईई)	20,15,756	16,13,902
vii)	डीएफआईडी इन्वेंट परियोजना व्यय	1000,00,000	1650,00,000
viii)	डीएफआईडी इन्वेंट बैंक प्रभार	91	21,691
<b>अंतरोध</b>			
i)	अल्पावधि जमा में निवेश	5699,00,000	4995,00,000
ii)	सुलभ रोकड	34,976	23,520
<b>बैंक में नकदी</b>			
क)	बैंक में जमा (ईपीएफ खाते सहित)	126,10,21,180	759,89,345
ख)	बैंक में जमा-डीएफआईडी इन्वेंट	397,52,776	1366,14,643
	<b>कुल</b>	<b>335,68,66,065</b>	<b>26481,29,591</b>

-४-  
(राजेश जैन)  
निदेशक  
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

-४-  
(डॉ. नीरज शर्मा)  
सचिव  
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

-४-  
(प्रो. आशुतोष शर्मा)  
अध्यक्ष  
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को तुलना पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
<b>अनुसूची -1 कॉरपस/कैपिटल फंड:</b>		
वर्ष के प्रारंभ की स्थिति के अनुसार शेष	134695,57,302	118865,05,993
जोड़: कॉरपस/कैपिटल फंड के लिए अंशदान	-	-
जोड़: आय और व्यय लेखों से स्थानांतरित सकल आय का शेष (नोट न. 25(11) देखें)	12156,80,580	15830,51,309
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार शेष	<b>146852,37,882</b>	<b>134695,57,302</b>

(राशि रु. में)

<b>अनुसूची 2- आरक्षित एवं अधिशेष राशि</b>			
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	
<b>1. कैपिटल रिजर्व:</b>			
अंतिम लेखा के अनुसार			
वर्ष के दौरान जोड़			
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	
<b>2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व:</b>			
अंतिम लेखा के अनुसार			
वर्ष के दौरान जोड़			
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	
<b>3. विशेष रिजर्व:</b>			
अंतिम लेखा के अनुसार			
वर्ष के दौरान जोड़			
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	
<b>4. सामान्य रिजर्व:</b>			
अंतिम लेखा के अनुसार			
वर्ष के दौरान जमा			
घटा: वर्ष के दौरान कटौती			
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को तुलना पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 3- अलग से निर्धारित/इनबोवमेंट निधि			
व्ययित्व	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
<b>क. आईडीबीआई का वीसीएफ</b>			
1. भारत सरकार से आई डी बी आई द्वारा प्राप्त अंशदान		2884,00,000	2884,00,000
<b>निवेश से आय</b>			
(क) ब्याज	1331,47,041		1308,52,144
(ख) राजस्व	551,97,900		551,97,900
(ग) लाभांश	86,23,794		86,23,794
(घ) उपार्जित आय घटा घूट	23880,81,913		23903,76,810
	<b>25850,50,648</b>		<b>25850,50,648</b>
घटा : टीडीबी को दी गई राशि	2125,00,000		2125,00,000
	<b>26609,50,648</b>		<b>23725,50,648</b>
घटा : मूलधन में समायोजित पूर्व प्राप्त अधिशेष राजस्व	112,50,000		112,50,000
	<b>26497,00,648</b>		<b>23613,00,648</b>
घटा : बढ़े खातों में डाला गया ऋण	436,36,450		436,36,450
घटा : निवेश की बिक्री पर हानि	26,76,250		26,76,250
	<b>26033,87,948</b>		<b>23149,87,948</b>
घटा : ऋण विषयक प्रावधान	832,79,357		810,04,357
घटा : ब्याज विषयक प्रावधान एवं एफआईएलडी	23880,81,913		23903,76,810
घटा : लेखा परीक्षा शुल्क एवं अन्य व्यय	18,32,324		17,52,075
घटा : आईडीबीआई को प्रबंधन शुल्क	1571,80,000		1432,60,000
घटा : निवेश के मूल्य में कमी	26,26,000	(296,11,646)	26,26,000
		(296,11,646)	(3040,31,294)
*टी डी बी से प्राप्त होने योग्य धनराशि (दिनांक 31.03.2019)		362,10,646	222,30,294
		<b>65,99,000</b>	<b>65,99,000</b>
<b>ख. प्रौद्योगिकी विकास के लिए नवप्रवर्तक उद्यम (इन्वेंट) - डीएफआईडी</b>		<b>397,52,775</b>	<b>1366,14,643</b>
<b>कुल</b>		<b>463,51,775</b>	<b>1432,13,643</b>

\*नोट:

1. निधि के गैर- निष्पादन की वजह से आई डी बी आई द्वारा दावा किए गए प्रबंधन खर्च की राशि को टी डी बी द्वारा विवादित कर दिया गया है।
2. आई डी बी आई द्वारा 3,82,10,846/- रूपए की राशि का दावा किया गया है जो दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के उनके अंतिम लेखा परीक्षित तुलना-पत्र के अनुसार टी डी बी द्वारा देय है। उक्त राशि आई डी बी आई द्वारा प्रसारित उच्च प्रबंधन शुल्क के कारण प्राप्त हुई है। टी डी बी उक्त राशि के समाधान को लंबित रखते हुए उक्त राशि का भुगतान स्वीकार नहीं करता है।

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को तुलना पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 4- प्रतिभूत ऋण एवं उधार				
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	1. केन्द्र सरकार	-	-	-
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं				
(क) आवधिक ऋण				
(ख) अर्जित ब्याज एवं देय	-	-	-	-
4. बैंक				
(क) अवधि ऋण				
- अर्जित ब्याज एवं देय				
(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)				
- अर्जित ब्याज एवं देय	-	-	-	-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	-	-	-	-
6. डिबेंचर्स एवं बॉन्ड्स				
<b>कुल</b>	-	-	-	-
नोट: एक वर्ष के भीतर बकाया राशि				

(राशि रु. में)

अनुसूची 5- अप्रतिभूत ऋण एवं उधार				
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	1. केन्द्र सरकार	-	-	-
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)				
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-	-	-
4. बैंक (क) आवधिक ऋण				
(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	-	-	-	-
6. डिबेंचर्स एवं बॉन्ड्स	-	-	-	-
7. अजल जमा	-	-	-	-
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
<b>कुल</b>	-	-	-	-
नोट: एक वर्ष के भीतर बकाया राशि				

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को तुलना पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 6- प्रास्थगित ऋण देयताएं				
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. कैपिटल उपकरणों एवं अन्य परिसंपत्तियों के ऋण भार द्वारा सुरक्षित सहमति	-	-	-	-
ख. अन्य				
	कुल			
नोट: एक वर्ष के भीतर देय				

अनुसूची 7- चालू देयताएं एवं प्रावधान				
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
<b>क. चालू देयताएं</b>				
1. "कोविड-19 से लड़ने" के लिए सहायता अनुदान का अप्रयुक्त शेष		7500,00,000		-
2. विविध लेनदार				
क. माल के लिए	-			
ख. अन्य	-	-		
3. प्राप्त प्रतिभूति		-		-
4. अर्जित ब्याज जो निम्नलिखित पर देय नहीं है:				
क. प्रतिभूत ऋण/उधार				
ख. अप्रतिभूत ऋण/उधार	-	-		-
5. सांविधिक देयताएं				
क. टीडीएस	3,60,502		4,12,429	
ख. जीएसटी	48,961		40,342	-
ग. जीपीएफ देय				
घ. इंडीएफ देय	3,33,797	7,43,260	3,04,906	7,57,677
6. अन्य चालू देयताएं				
क. प्रतिनियुक्ति के लिए पेंशन अंशदान				
ख. देय लेखा परीक्षा शुल्क	3,89,839			3,87,689
ग. लंबित समायोजन	-			537,79,000
घ. अन्य	-	3,89,839		7,260
<b>कुल (क)</b>		<b>7511,33,099</b>		<b>549,31,626</b>
<b>ख. प्रावधान</b>				
1. ग्रेच्युटी	17,08,387			13,52,473
2. देय वेतन	18,05,917			16,14,494
3. देय विधिक प्रभार	-			3,60,000
4. देय राष्ट्रीय पुरस्कार	170,00,000			-
5. देय अन्य खर्च	18,52,488	223,66,792		-
<b>कुल (ख)</b>		<b>223,66,792</b>		<b>33,26,967</b>
<b>कुल (क+ख)</b>		<b>7734,99,891</b>		<b>582,58,593</b>

# प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को तुलना पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची B- विचारित परिसंपत्ति :	सकल खर्च				अवशुल्क				निवल खर्च		
	वर्ष के प्रारंभ में शिथिली के अनुसार लागत / मूल्य	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्य	वर्ष के प्रारंभ में शिथिली के अनुसार	वर्ष के दौरान जोड़ के उपरांत	वर्ष के दौरान कटौती के उपरांत	वर्ष के अंत तक जोड़	शिथिली / समाप्तोत्पन्न	31.03.2020 की शिथिली के अनुसार	31.03.2019 की शिथिली के अनुसार
<b>क. स्थायी परिसंपत्ति</b>											
1. भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. बिल्डिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. सीजरोल्ड जमीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. स्थापितकारी परॉट / परिवार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. जमीन पर अधिरचना क्लसिफिकेशन से संबंध नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. जॉइंट एवं भतीनी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	674,375	-	-	674,375	260,224	62,123	-	322,347	-	352,028	414,151
5. कर्फीलर / फिक्साचर	5,084,975	-	-	5,084,975	2,042,760	304,220	-	2,346,985	-	2,737,987	3,092,202
6. कर्पोरेशन सार्वजनिक उपकरण	5,038,367	444,205	-	5,482,572	2,447,231	425,077	-	2,872,308	-	2,610,264	2,591,136
7. कंप्यूटर उपकरण	2,607,170	299,700	-	2,906,870	2,336,485	168,254	-	2,504,639	-	402,231	270,785
8. इलेक्ट्रिक अधिष्ठापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. सुरक्षात्मक की सुरक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. साफ्टवेयर (पीएचएस) (40%)	-	718,904	-	718,904	-	143,781	-	143,781	-	375,121	-
11. अन्य अचल परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आवृ वर्ष का कुल जोड़	13,404,807	1,462,009	-	14,866,696	7,086,608	1,103,455	-	8,190,063	-	6,677,633	6,318,279
ख. पूंजीगत कार्ग प्रगति बर्ष (सॉफ्टवेयर)	550,456	-	-	550,456	-	-	-	-	-	-	550,456
कुल	13,955,343	1,462,009	-	14,867,696	7,086,608	1,103,455	-	8,190,063	-	6,677,633	6,868,735
<b>(अवशुल्क सहित निवल खर्च पर कुल आकार पर परिसंपत्तियों की लागत पर ही जाने वाली डिप्लिमेंट)</b>											
विगत वर्ष	13,611,915	343,428	-	13,955,343	5,857,638	1,228,976	-	7,086,608	-	6,868,735	7,754,277

सॉफ्टवेयर पूरा होने पर वर्ष के दौरान पूंजी में पलित किए जा रहे सॉफ्टवेयर डब्ल्यू आई पी

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को तुलना पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 9— अलग से निर्धारित / अक्षय निधियों से निवेश			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		-	-
3. शेयर		-	-
4. डिबेंचर और बॉन्ड्स		-	-
5. सक्षिडियरिज एवं संयुक्त उद्यम		-	-
6. आई डी बी आई का वीसीएफ (परिसम्पत्ति)		-	-
<b>निवेश</b>			
(i) ऋण	810,04,357		810,04,357
घटा : प्रावधान	810,04,357	-	810,04,357
(ii) इक्विटी	92,25,000		92,25,000
घटा : निवेश के मूल्य में कमी	26,26,000	65,99,000	26,26,000
<b>वसूली योग्य</b>			
(i) ब्याज	2997,69,021		2997,69,021
(ii) एफआईएलडी	20906,07,789		20906,07,789
	<b>23903,76,810</b>		<b>23903,76,810</b>
घटा : प्रावधान	23903,76,810	-	23903,76,810
<b>कुल</b>		<b>65,99,000</b>	<b>65,99,000</b>

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को तुलना पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 10 - निवेश - अन्य:			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में			
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों			
3. शेयर- इक्विटी/अधिमान भागीदारी	2846,72,726		2846,72,726
घटा : शेयर की तुलना में प्राप्ति	765,09,759	2081,62,967	
4. डिबेंचर्स और बॉन्ड्स			
5. सहायक उद्यम एवं संयुक्त उद्यम			
6. वेंचर फंड			
क. यूटीआई एंसेंट इंडिया फंड	2899,20,195		2899,20,195
घटा : विमोचन	146,31,293		
घटा : जोखिम निधि समाप्त पर हानि	2752,88,902	-	
ख. एपीआईडीसी वेंचर निधि	2347,86,000		
घटा : विमोचन	250,00,000	2097,86,000	2347,86,000
ग. वेंचर ईस्ट टीनेट फंड	441,43,882		
घटा : विमोचन	-	441,43,882	441,43,882
घ. जीवीएफएल	1,50,000		
घटा : विमोचन	-	1,50,000	1,50,000
ड. आरवीसीएफ	1178,74,724		
घटा : विमोचन	34,34,150	1144,40,574	1178,74,724
च. सिडबी वीसीएफ	1887,26,863		
जोड़ : वितरण	-		
घटा : विमोचन	144,18,678	1743,08,185	1887,26,863
छ. आईपी केप वेंचर ट्रस्ट फंड-1	2168,92,238		
जोड़ : वितरण	-		
घटा : विमोचन	10,34,438	2158,57,800	2168,92,238
ज. मल्टी सेक्टर सीड कैपिटल फंड	1040,00,000		
घटा : विमोचन	76,55,900	963,44,100	1040,00,000
झ. सीफ इंडिया एपी बिजनेस फंड	2281,35,470		
जोड़ : सवितरण	5,77,473		
घटा : विमोचन	186,63,888	2100,49,055	2281,35,470
ञ. इंडियन फंड फॉर सरस्टेनेबल एनर्जी (सीआईआईई)	546,44,047		
जोड़ : सवितरण	20,15,756		
घटा : विमोचन	-	566,59,803	546,44,047
7. जी आई टी ए	720,50,000		
जोड़ : वितरण	-	720,50,000	720,50,000
<b>कुल</b>		<b>14019,52,366</b>	<b>18359,96,145</b>

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को तुलना पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 11 – चालू परिसम्पत्ति, ऋण एवं अग्रिम आदि			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
क. चालू परिसम्पत्तियां:			
1. सूची :			
क) भंडार एवं समान			
ख) अनिश्चित साधन (लूज टूल्स)			
ग) स्टॉक इन ट्रेड			
i) निर्मित वस्तुएं			
ii) कार्य प्रगति पर			
iii) कच्चा माल	-	-	-
2. विविध देनदार			
क) छ: माह से अधिक की अवधि से लंबित ऋण			
ख) अन्य		-	1,278
3. हाथ में शेष शेकड (चेक / ड्राफ्ट एवं बयाना सहित)		34,976	23,520
4. बैंक में जमा			
क) सूचीगत बैंकों के साथ			
- चालू खाते पर			
- बचत खाते में – टी डी बी (ई पी एफ खाता सहित)	12610,21,180		759,89,345
- बचत खाता-इन्वेंट-डीएफआईडी	397,52,776	13007,73,956	1366,14,643
ख) सूचीगत बैंकों के साथ लघु अवधि जमा			
- जमा खाते पर	5699,00,000	5699,00,000	4995,00,000
- जमा खाते पर इन्वेंट पर डीएफआईडी			
	<b>कुल (क)</b>	<b>18707,08,932</b>	<b>7121,28,786</b>

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को तुलना पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 11 – चालू परिसम्पत्ति, ऋण, अग्रिम इत्यादि (जारी है)		
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
<b>ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्ति :</b>		
<b>1. ऋण:</b>		
(क) कर्मचारी		
(ख) अन्य सत्ताएं जो उनसे मिलती जुलती सत्ताओं की गतिविधियों / उद्देश्यों में सम्मिलित	-	-
(ग) ऋण- औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सहायता		
आरम्भिक शेष	73099,65,366	59929,81,284
जोड़ : वर्ष के दौरान	12837,12,000	16372,50,000
घटा : ऋण की अदायगी/समायोजन	6763,10,641	3285,40,326
घटा : खातों के निपटारे के कारण से बड़े खातों में डाला गया	111,54,978	-
घटा : अर्जित ब्याज में अंतरण	18,89,347	-
जोड़ : अर्जित ब्याज से अंतरित	-	82,50,000
जोड़ : अवधि पूर्व समायोजन	-	24,408
	79043,22,401	73099,65,366
घटा : संदेहपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान	-	89,05,867
प्रावधान के बाद अंतिम ऋण कोष	79043,22,401	73010,59,499
<b>2. नकद अथवा वस्तु में अदायगी करने योग्य अग्रिम एवं अन्य राशि अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य</b>		
क) स्टाफ सदस्यों को अग्रिम	8,71,280	8,24,775
ख) पुनः प्राप्ति करने योग्य आयकर	11,38,824	10,36,673
ग) अन्य-प्रतिभूति जमा	9,90,280	11,06,280
घ) विक्रेताओं के पास अग्रिम धनराशि	-	-
ड) अन्य	24,056	30,24,440
	30,24,440	71,009
<b>3. अर्जित आय :</b>		
क) निर्धारित/इनडोवमेंट फंड से निवेश पर		
ख) निवेश पर – अल्पावधि जमा	36,83,794	80,36,475
अल्पावधि जमा – इन्वेंट-डीएफआईडी	-	-
ग) ब्याज एवं अग्रिम राशि पर	45625,70,377	41259,02,361
घटा : वर्ष के दौरान वसूली नहीं करने योग्य ब्याज को बड़े खातों में डाला गया	228,56,713	129,35,285
घटा : ऋण में अंतरण	-	82,50,000
घटा : वर्ष के दौरान पूर्व अवधि समायोजन	6,45,734	635,20,564
जोड़ : ऋण से अंतरण	18,89,347	-
	45409,57,277	40411,96,512
घटा : ऋण ब्याज प्रावधान :	2328,36,294	2438,94,352
	43081,20,983	37973,02,160
<b>कुल (ख)</b>	<b>122191,51,618</b>	<b>111094,36,871</b>
<b>कुल (क+ख)</b>	<b>140898,60,549</b>	<b>118215,65,658</b>

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 12 - बिक्री / सेवाओं से आय :			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
<b>1. बिक्री से आय</b>			
क) निर्मित वस्तुओं की बिक्री			
ख) कच्चे माल की बिक्री			
ग) स्क्रेप की बिक्री	-	-	-
<b>2. सेवाओं से आय</b>			
क) भ्रम एवं संसाधित प्रभार			
ख) व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएं			
ग) एजेंसी कमीशन और दलाली			
घ) रखरखाव सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)			
ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें)			-
<b>कुल</b>	-	-	-

राशि रु. में

अनुसूची 13 - अनुदान / सन्निधि :			
(गैर-वसूली योग्य अनुदान एवं वसूली गई सन्निधि)			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार		9800,00,000	10000,00,000
2. राज्य सरकार (रु)			
3. संस्थान/कल्याण बोर्ड		-	-
4. अंतर्राष्ट्रीय संगठन			
5. अन्य - अथयित अनुदान वापिस आया		38,34,331	380,31,997
<b>कुल</b>		<b>9838,34,331</b>	<b>10380,31,997</b>

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को तुलना पत्र के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 11 – चालू परिसम्पत्ति, ऋण, अग्रिम इत्यादि (जारी है)		
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
<b>ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्ति :</b>		
<b>1. ऋण:</b>		
(क) कर्मचारी		
(ख) अन्य सत्ताएं जो उनसे मिलती जुलती सत्ताओं की गतिविधियों / उद्देश्यों में सम्मिलित	-	-
(ग) ऋण- औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सहायता		
आरम्भिक शेष	73099,65,366	59929,81,284
जोड़ : वर्ष के दौरान	12837,12,000	16372,50,000
घटा : ऋण की अदायगी / समायोजन	6763,10,641	3285,40,326
घटा : खातों के निपटारे के कारण से बड़े खातों में डाला गया	111,54,978	-
घटा : अर्जित ब्याज में अंतरण	18,89,347	-
जोड़ : अर्जित ब्याज से अंतरित	-	82,50,000
जोड़ : अवधि पूर्व समायोजन	-	24,408
	79043,22,401	73099,65,366
घटा : संदेहपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान	-	89,05,867
प्रावधान के बाद अंतिम ऋण कोष	79043,22,401	73010,59,499
<b>2. नकद अथवा वस्तु में अदायगी करने योग्य अग्रिम एवं अन्य राशि अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य</b>		
क) स्टाफ सदस्यों को अग्रिम	8,71,280	8,24,775
ख) पुनः प्राप्ति करने योग्य आयकर	11,38,824	10,36,673
ग) अन्य-प्रतिभूति जमा	9,90,280	11,06,280
घ) विक्रेताओं के पास अग्रिम धनराशि	-	-
ङ) अन्य	24,056	30,24,440
	34,24,360	71,009
<b>3. अर्जित आय :</b>		
क) निर्धारित / इनवोल्वमेंट फंड से निवेश पर		
ख) निवेश पर - अल्पावधि जमा	36,83,794	80,36,475
अल्पावधि जमा- इन्वेस्ट-डीएफआईडी	-	-
ग) ब्याज एवं अग्रिम राशि पर	45625,70,377	41259,02,361
घटा : वर्ष के दौरान वसूली नहीं करने योग्य ब्याज को बड़े खातों में डाला गया	228,56,713	129,35,285
घटा : ऋण में अंतरण	-	82,50,000
घटा : वर्ष के दौरान पूर्व अवधि समायोजन	6,45,734	635,20,564
जोड़ : ऋण से अंतरण	18,89,347	-
	45409,57,277	40411,96,512
घटा : ऋण ब्याज प्रावधान :	2328,36,294	2438,94,352
	43081,20,983	37973,02,160
<b>कुल (ख)</b>	<b>122191,51,618</b>	<b>111094,36,871</b>
<b>कुल (क+ख)</b>	<b>140898,60,549</b>	<b>118215,65,658</b>

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 12 – बिक्री / सेवाओं से आय :			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
<b>1. बिक्री से आय</b>			
क) निर्मित वस्तुओं की बिक्री			
ख) कच्चे माल की बिक्री			
ग) स्टॉक की बिक्री	-	-	-
<b>2. सेवाओं से आय</b>			
क) भ्रम एवं संसाधित प्रचार			
ख) व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएं			
ग) एजेंसी कमीशन और दलाली			
घ) रखरखाव सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)			
ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें)			-
<b>कुल</b>	-	-	-

राशि रु. में

अनुसूची 13 – अनुदान / सस्मिडी :			
(गैर-वसूली योग्य अनुदान एवं वसूली गई सस्मिडी)			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार		9800,00,000	10000,00,000
2. राज्य सरकार (रु)			
3. संस्थान/कल्याण बोर्ड		-	-
4. अंतर्राष्ट्रीय संगठन			
5. अन्य – अव्ययित अनुदान वापिस आया		38,34,331	380,31,997
<b>कुल</b>		<b>9838,34,331</b>	<b>10380,31,997</b>

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 14 - शुल्क/अंशदान			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
	1) प्रवेश शुल्क	-	-
2) वार्षिक शुल्क/अंशदान			
3) गोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-	-
4) परामर्शी शुल्क	-	-	-
	<b>कुल</b>		-
टिप्पणी : प्रत्येक मद की बताई जाने वाली लेखा नीतियों का निर्धारित फंड से निवेश			

(राशि रु. में)

अनुसूची 15 - निवेश से आय: (फंड में हस्तांतरित किया गया निर्धारित/इनडोवमेंट फंड से निवेश पर आय)			
	निर्धारित फंड से निवेश		अन्य निवेश
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष
1) व्याज			
क) सरकारी प्रतिभूति पर			
ख) अन्य बॉन्ड्स पत्र/डिबेंचर			
2) लाभांश			
क) शेयर पर			
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर			
3) किराए	-	-	-
4) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-
	<b>कुल</b>		
निर्धारित/इनडोवमेंट फंड में हस्तांतरित			

(राशि रु. में)

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
	1) राजस्व से आय		44,87,232
2) उपाजित राजस्व			
घटा: राजस्व माफी		-	-
3) अन्य (निर्दिष्ट करें)			
	<b>कुल</b>		<b>62,82,547</b>

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज		
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
<b>1) आवधिक जमा पर:</b>		
क) सूचीगत बैंकों के साथ	291,22,606	282,48,477
ख) गैर-सूचीगत बैंकों के साथ		-
ग) संस्थाओं के साथ		-
<b>2) बचत खातों पर:</b>		
क) सूचीगत बैंकों के साथ (ईपीएफ खाता सहित)	86,65,931	152,86,632
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में		-
ग) डाक घर बचत खाता		-
घ) अन्य		-
<b>3) ऋण पर:</b>		
क) कर्मचारी/स्टाफ		
ख) औद्योगिक इकाई को ऋण सहायता	5979,70,781	5435,63,877
<b>4) राजस्व पर ब्याज</b>	2,95,247	8,03,520
<b>5) अनुदान पर ब्याज</b>	-	-
<b>कुल</b>	<b>6360,54,565</b>	<b>5879,02,506</b>

नोट: स्रोत पर कर कटौती को दर्शाया जाएगा।

(राशि रु. में)

अनुसूची 18 - अन्य आय		
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
<b>1) संपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:</b>		
क) प्राप्त संपत्ति-यूटीआई		
ख) अनुदान से अधिग्रहित अथवा निःशुल्क प्राप्त संपत्ति		
<b>2) यूनिटों के विमोचन से लाभ</b>		
<b>3) लाभान्श</b>		-
<b>4) विविध आय</b>	3,563	1,67,899
<b>5) बैठक शुल्क</b>		-
<b>6) दान</b>	3,00,000	1,00,100
<b>7) वेन्चर फंड से आय</b>		595,66,726
<b>कुल</b>	<b>3,03,563</b>	<b>598,34,725</b>

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को आय और व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 19 – निर्मित वस्तुओं के भंडार में वृद्धि/ह्रास और कार्य प्रगति पर			
	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
क) बंद स्टॉक			
– तैयार माल			
– चल रहा कार्य	-	-	-
ख) घटा : ओपनिंग स्टॉक			
– तैयार माल			
– चल रहा कार्य	-	-	-
निवल वृद्धि/(घटाव) (क-ख)	-	-	-

(राशि रु. में)

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय			
		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क.	वेतन एवं मजूदरी	309,94,096	243,59,716
ख.	भत्ता	4,32,759	1,54,237
ग.	भविष्य निधि में नियोजता का अंशदान	14,49,312	16,27,938
घ.	यूनिफॉर्म	-	20,000
ङ.	कर्मचारी कल्याण खर्च	77,000	67,000
च.	कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभों पर व्यय	-	4,03,306
छ.	चिकित्सा प्रभासों की प्रतिपूर्ति	2,23,558	5,27,058
ज.	ग्रेष्पूटी	3,55,914	3,34,488
	कुल	335,32,639	274,93,743

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की आय एवं व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) राष्ट्रीय पुरस्कार	170,00,000	170,00,000
ख) विधि प्रभार	45,81,332	53,46,695
ग) संपत्ति प्रबंधन शुल्क	71,96,785	47,88,432
घ) सदस्यता शुल्क	23,600	23,600
ङ) टी.डी.एस एवं ब्याज	-	7,296
च) परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि	-	-
छ) मरम्मत एवं रख-रखाव	12,80,715	10,55,507
ज) डाक एवं टिकट	55,443	54,927
झ) प्रौद्योगिकी दिवस व्यय	6,96,212	20,86,809
ण) वाहन चालन और रखरखाव	41,422	1,88,344
ट) टेलीफोन एवं संचार प्रभार	21,25,374	19,98,322
ठ) प्रिटिंग, स्टेशनरी एवं उपभोग्य	12,34,404	7,76,971
ड) घरेलू यात्रा खर्च	20,31,298	-
विदेशी यात्रा खर्च	-	-
विशेषज्ञों की यात्रा पर खर्च	28,61,788	48,93,086
ड) पुस्तकालय की पुस्तकें एवं आवधिक पत्रिका	885	6,116
ण) बोर्ड के सदस्यों को टीए/डीए	24,457	1,24,076
प) लेखा परीक्षा शुल्क	80,000	80,000
फ) आवभगत व्यय	1,90,132	1,66,083
ब) बैठकों पर व्यय	15,85,545	19,52,570
भ) व्यवसायिक प्रभार	55,12,480	30,31,100
म) क) वर्ष के दौरान अप्राप्य ब्याज को बढ़ते खाते में डाला गया	228,56,713	129,35,285
ख) ऋण के मूल मूल्य को बढ़ते खाते में डाला गया	111,54,978	-
ग) ऋण का प्रावधान	(89,05,867)	-
घ) वर्ष का ऋण प्रावधान	(110,58,058)	(129,35,285)
य) बैंक प्रभार	-	250
र) विविध व्यय	6,74,975	7,61,019
ल) समाचार पत्र एवं पत्रिका	36,123	25,797
व) विज्ञापन एवं प्रचार	63,26,171	55,93,351
श) बोर्ड के व्यय एवं शुल्क	1,43,645	78,571
ष) किराया	90,69,257	74,20,555
स) नवीनीकरण एवं पुनर्संज्जा	-	14,75,348
ह) वेंचर फंड समापन के कारण हानि (अनुसूची 25 नोट 5 का संदर्भ लें)	2752,88,902	-
कुल	3521,08,711	605,82,806

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की आय एवं व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 22 – अनुदान पर व्यय		
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) संस्थाओं एवं संगठनों को दिया गया अनुदान		
(i) इन्व्यूटर्स	10,84,242	11,08,267
(ii) अन्य एजेंसियां		-
2) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सख्तिडी		
	<b>कुल</b>	<b>कुल</b>
	<b>10,84,242</b>	<b>11,08,267</b>

नोट: संस्थाओं के नाम, उनकी गतिविधियों के साथ अनुदान/सख्तिडी का खुलासा।

(राशि रु. में)

अनुसूची 23 – ब्याज		
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) अचल ऋण पर		
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)		
ग) अन्य-डीएसटी से प्राप्त अनुदान	209,24,330	-
	<b>कुल</b>	<b>कुल</b>
	<b>209,24,330</b>	<b>-</b>

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

लेखा: 2019-20 पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और टिप्पणियाँ

### क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. प्राप्ति और भुगतान खाते नकद रसीद प्राप्ति जर्नल से तैयार किए जाते हैं और विभिन्न शीर्षों के तहत नकद लेनदेन का एक सारांश है। यह पूंजी और राजस्व प्रकृति दोनों की प्राप्ति और भुगतान अभिलेखित करता है।
2. आय और व्यय खाता वर्ष की आय और व्यय का सारांश है। यह प्रोद्भव आधार पर तैयार किया जाता है। यह केवल राजस्व प्रकृति की आय और व्यय को अभिलेखित करता है। संवितरित ऋण राशि पर अर्जित उपाजित ब्याज का हिसाब उस वर्ष में दिया जाता है जिसमें ऋण की किस्त जारी की जाती है, तथापि ब्याज संबंधित ऋण समझौतों के नियमों और शर्तों के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करने के बाद वास्तव में प्राप्त होता है। वर्ष के दौरान देय और अनुमोदित खर्चों का प्रावधान है।
3. निर्धारित परिसम्पत्तियों पर अवमूल्यन हासशील संतुलन विधि पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित दरों के आधार पर प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान बेचे/हस्तांतरित/छोड़े गए निर्धारित आस्तियों पर कोई मूल्यहास प्रदान नहीं किया जाता है। निर्धारित संपत्तियों में संयोजन अधिग्रहण की लागत पर लेखांकित किया जाता है।
4. प्राप्ति और भुगतान खाते और आय और व्यय खाते में प्राप्ति के आधार पर रॉयल्टी भुगतान लिया जाता है।
5. सरकारी अनुदान प्राप्ति के आधार पर मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार को अप्रयुक्त शेष राशि वापस नहीं की जानी चाहिए क्योंकि सरकार द्वारा जारी अनुदान को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा 9(1)(क) के अनुसार प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग कोष में जमा किया जाता है और वापस करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए,

कोई भी राशि भारत सरकार को वापिस और इस प्रकार निधि वापस करने के लिए नहीं है।

6. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा 9(1) के संदर्भ में, प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग कोष से दी गई राशि की वसूली, ऋण पर ब्याज की प्राप्ति, रॉयल्टी, दान और किसी अन्य स्रोत से प्राप्त रकम को कोष में जमा किया जाता है। इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए तुलन-पत्र तैयार किया गया है।
7. आईडीबीआई द्वारा बनाए गए अलग से निर्धारित/संदाय फंड्स (वेंचर कैपिटल फंड्स) की तुलन-पत्र में निम्नलिखित संकेत दिए गए हैं:-
  - क) तुलन पत्र को रॉयल्टी, प्रबंधन शुल्क और उस पर प्राप्त दांडिक ब्याज के संबंध में आय/व्यय को छोड़कर, जो वास्तविक प्राप्ति/भुगतान पर मान्यता प्राप्त है के आधार पर अर्जित किया जाता है।
  - ख) संपत्ति/ऋण/निवेश का मूल्यांकन आईडीबीआई कोष प्रबंधक द्वारा मूल्यांकन मूल्य पर किया गया है और परिसंपत्तियों के खाता मूल्य को कम करने का प्रावधान वित्तीय विवरणों में प्रदान किए गए टिप्पणियों के अनुसार दर्ज किया गया है।
  - ग) आईडीबीआई (वीसीएफ) के वित्तीय विवरणों को आईडीबीआई द्वारा प्रदान किए गए तुलन-पत्र टिप्पणियों के साथ संलग्न अन्य टिप्पणियों और स्पष्टीकरण के साथ पढ़ना होता है। वित्तीय विवरण और खातों के लिए टिप्पणियों को आईडीबीआई द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रमाणित और उसके बाद लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार लिया जाता है।
8. राष्ट्रीयकृत बैंकों में अल्पावधि जमा में निधियों का शेष रखा जाता है। अल्पावधि जमा पर ब्याज प्राप्तियों और भुगतान खाते और तुलन-पत्र में दर्शाया जाता है।

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की आय एवं व्यय के एक भाग को बनाने वाली अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 22 – अनुदान पर व्यय		
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) संस्थाओं एवं संगठनों को दिया गया अनुदान		
(i) इन्क्यूबेटर्स	10,84,242	11,08,267
(ii) अन्य एजेंसियां		-
2) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सखिडी		
	<b>कुल</b>	<b>11,08,267</b>
	<b>10,84,242</b>	<b>11,08,267</b>

नोट: संस्थाओं के नाम, उनकी गतिविधियों के साथ अनुदान/सखिडी का खुलासा।

(राशि रु. में)

अनुसूची 23 – ब्याज		
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) अचल ऋण पर		
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)		
ग) अन्य-डीएस्सी से प्राप्त अनुदान	209,24,330	-
	<b>कुल</b>	<b>-</b>
	<b>209,24,330</b>	<b>-</b>

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

लेखा: 2019-20 पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और टिप्पणियाँ

### क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. प्राप्ति और भुगतान खाते नकद रसीद प्राप्ति जर्नल से तैयार किए जाते हैं और विभिन्न शीर्षों के तहत नकद लेनदेन का एक सारांश है। यह पूंजी और राजस्व प्रकृति दोनों की प्राप्ति और भुगतान अभिलेखित करता है।
2. आय और व्यय खाता वर्ष की आय और व्यय का सारांश है। यह प्रोद्भवन आधार पर तैयार किया जाता है। यह केवल राजस्व प्रकृति की आय और व्यय को अभिलेखित करता है। संवितरित ऋण राशि पर अर्जित उपार्जित ब्याज का हिसाब उस वर्ष में दिया जाता है जिसमें ऋण की किस्त जारी की जाती है, तथापि ब्याज संबंधित ऋण समझौतों के नियमों और शर्तों के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करने के बाद वास्तव में प्राप्त होता है। वर्ष के दौरान देय और अनुमोदित खर्चों का प्रावधान है।
3. निर्धारित परिसम्पत्तियों पर अवमूल्यन हासशील संतुलन विधि पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित दरों के आधार पर प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान बेचे/हस्तांतरित/छोड़े गए निर्धारित आस्तियों पर कोई मूल्यहास प्रदान नहीं किया जाता है। निर्धारित संपत्तियों में संयोजन अधिग्रहण की लागत पर लेखांकित किया जाता है।
4. प्राप्ति और भुगतान खाते और आय और व्यय खाते में प्राप्ति के आधार पर रॉयल्टी भुगतान लिया जाता है।
5. सरकारी अनुदान प्राप्ति के आधार पर मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार को अप्रयुक्त शेष राशि वापस नहीं की जानी चाहिए क्योंकि सरकार द्वारा जारी अनुदान को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा 9(1)(क) के अनुसार प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग कोष में जमा किया जाता है और वापस करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए,

कोई भी राशि भारत सरकार को वापस और इस प्रकार निधि वापस करने के लिए नहीं है।

6. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा 9(1) के संदर्भ में, प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग कोष से दी गई राशि की वसूली, ऋण पर ब्याज की प्राप्ति, रॉयल्टी, दान और किसी अन्य स्रोत से प्राप्त रकम को कोष में जमा किया जाता है। इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए तुलन-पत्र तैयार किया गया है।
7. आईडीबीआई द्वारा बनाए गए अलग से निर्धारित/संदाय फंड्स (वेंचर कैपिटल फंड्स) की तुलन-पत्र में निम्नलिखित संकेत दिए गए हैं-
  - क) तुलन पत्र को रॉयल्टी, प्रबंधन शुल्क और उस पर प्राप्त दांडिक ब्याज के संबंध में आय/व्यय को छोड़कर, जो वास्तविक प्राप्ति/भुगतान पर मान्यता प्राप्त है के आधार पर अर्जित किया जाता है।
  - ख) संपत्ति/ऋण/निवेश का मूल्यांकन आईडीबीआई कोष प्रबंधक द्वारा मूल्यांकन मूल्य पर किया गया है और परिसंपत्तियों के खाता मूल्य को कम करने का प्रावधान वित्तीय विवरणों में प्रदान किए गए टिप्पणियों के अनुसार दर्ज किया गया है।
  - ग) आईडीबीआई (वीसीएफ) के वित्तीय विवरणों को आईडीबीआई द्वारा प्रदान किए गए तुलन-पत्र टिप्पणियों के साथ संलग्न अन्य टिप्पणियों और स्पष्टीकरण के साथ पढ़ना होता है। वित्तीय विवरण और खातों के लिए टिप्पणियों को आईडीबीआई द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रमाणित और उसके बाद लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार लिया जाता है।
8. राष्ट्रीयकृत बैंकों में अल्पावधि जमा में निधियों का शेष रखा जाता है। अल्पावधि जमा पर ब्याज प्राप्तियों और भुगतान खाते और तुलन-पत्र में दर्शाया जाता है।

9. कंपनियों में निवेश लागत मूल्य पर बताया जाता है। टीडीबी के अधिदेश के अनुसार, निवेश पूंजी अधिमूल्यन के लिए कड़े अर्थों में या टीडीबी को किसी अन्य लाभ के लिए आयोजित नहीं किए जाते हैं, शेयरों को अधिग्रहण की कीमत पर तब तक आयोजित किया जाता है, जब तक कि वे अंतिम रूप से कार्यान्वित नहीं हो जाते हैं। तथापि, संबंधित कंपनी के समापन या विघटन या किसी अन्य कारण से किए गए निवेश के उचित मूल्य में कोई स्थायी गिरावट आय और व्यय खाते में गिरावट के मूल्य पर प्रभारित किया जाता है।
10. चूक के मामले में, पुनर्निर्धारित समझौता को जो भी किया जाता है, वह ऋण समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार अलग-अलग निर्धारित होता है और खाते में शेष राशि को मूल समझौते के अनुसार बहाल किया जाता है। इससे मूल समझौते पर वापस लौटने के कारण उधारकर्ता की बकाया राशि में वृद्धि हो सकती है।
11. ऐसे मामले में जहाँ ऋणकर्ता ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार ऋण/ब्याज राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है और जब ऋण समझौते के गैर-अनुपालन से उत्पन्न विवाद और परिणामस्वरूप मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाता है। ऐसे उदाहरण में ऋण और ब्याज की बकाया राशि मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा सकता है। ऐसे उदाहरण में ऋण और ब्याज की

बकाया राशि मध्यस्थ को भेजने की तारीख तक स्थगित की जाती है। पंचाट की शर्तों के अनुसार पारित होने के बाद ही बकाया ब्याज में आगे प्रावधान या समायोजन किया जाता है।

12. ऐसे मामले में जहाँ ऋणकर्ता ने ऋण समझौते के अनुसार अपने ऋण और ब्याज की अदायगी में चूक की है और तब से परिसमापन में चला गया है, ब्याज का लेखांकन परिसमापन की तारीख तक सीमित कर दिया गया है। अंतिम भुगतान की प्राप्ति के बाद मूलधन और ब्याज के बट्टे खाते में डालने के लिए अंतिम प्रावधान किया गया है, जब से पुनर्प्राप्ति की तिथि तक ब्याज का दावा करने का अधिकार टीडीबी द्वारा बनाए रखा गया है, तब से आधिकारिक परिसमापक बनता है।
13. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी (ओआरसी) के अदि-लेख के अनुसार पंजीकृत कंपनियों की सूची से कंपनी के रूतबे की पहचान की जा रही है, जो परिसमापन के दौर से गुजर रही है जहाँ ऋण राशि और ब्याज अतिदेय/अद्वैतनिक बना हुआ है, इसे विधिक अनुभाग में भेजा गया है। तथापि चूक की उच्च सीयना और शेष राशि की पुष्टि नहीं होने के कारण, चालू वर्ष के लिए कोई ब्याज लेखांकित नहीं किया जाता है। संदिग्ध बसूली या बट्टे खाते में डालने के लिए अंतिम प्रावधान प्रत्येक कंपनी के मामले में मामले को कानूनी रूप से बंद करने के अधीन है। अतिदेय कंपनियों की सूची निम्नलिखित है:

(आंकड़े लाखों में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	आरजोसी के अनुसार स्थिति	अधिदेय मूलधन	मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार अधिदेय ब्याज
1.	मेसर्स हवाईट सर्कल ऑक्साइड	परिसमापन किया जा रहा है	190.00	323.96
2.	मेसर्स साई पापैन	हटा दिया गया है	165.00	436.36
3.	मेसर्स समुद्र बायोफार्मा	हटा दिया गया है/परिसमापन किया जा रहा है	247.77	465.46
4.	मेसर्स जावेशी एग्रो	हटा दिया गया	35.00	87.60
5.	मेसर्स वरदान एग्रो	विधि के अनुसार परिसमापन	495.00	1607.47
6.	मेसर्स आर्डिन टेक्नोलॉजी	परिसमापन किया जा रहा है	426.64	883.21
7.	मेसर्स कावेरा सिस्टम	परिसमापन	440.00	385.36
8.	मेसर्स हाइड्रोतिना बायोटेक	परिसमापन	430.00	157.73

14. उधारकर्ता द्वारा चूक और बाद में मध्यस्थता पंचाट जारी होने के मामले में ऋण और ब्याज का पुनर्विवरण और साथ ही ब्याज का प्रभारण पंचाट के अनुसार किया जाता है। इससे उधारकर्ता से देय ब्याज की बकाया धनराशि में कमी/वृद्धि हो सकती है।
15. मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू होने के मामले में ब्याज के प्रभार को पंचाट पारित होने तक कार्यवाही शुरू करने की तारीख से बंद कर दिया जाता है। पंचाट के बाद अन्य शर्तें स्थिर रहने पर ऋण और उस पर ब्याज का लेखांकन पंचाट के अनुसार किया जाता है।
16. यदि पूर्ण सहमति राशि के लिए धनराशि जारी नहीं की गई है और समयबद्ध पुनर्भुगतान अनुसूची कार्यशील है, तो ब्याज की गणना समझौते के अनुसार लागू दर पर जारी की गई राशि के आधार पर की जाती है।
17. वेंचर फंड्स के साथ अन्य सीड फंड्स में निवेश किया जाता है। चूंकि निधि अपनी गतिविधियों के संदर्भ में

लगातार विकसित हो रही है और एक निरंतर धिता का विषय है, इसलिए निवेश के मूल्य में कोई स्थायी परिवर्तन की परिकल्पना या प्रावधान नहीं किया गया है। वेंचर फंड इन्वेस्टमेंट में वृद्धि या कमी को मान्यता दी जाती है या तो निधि के बंद होने पर या निधि के कार्यकाल के दौरान आय संवितरण किया जाता है।

18. जब तक टीडीबी द्वारा सहमति नहीं दी जाती है, तब तक उधारकर्ता से प्राप्त भुगतान का लेखा जोखा निम्नलिखित क्रम में, अर्थात् अतिरिक्त ब्याज सहित ब्याज अनुवर्ती एवं चूक की गई धनराशि पर परिनिर्धारित नुकसानी देय और भुगतान करने योग्य मूलधन के किस्तों की अदायगी अथवा बोर्ड द्वारा यथा निर्णीत एवं अनुमोदित तरीके से ऐसी बकाया राशि को लेखांकित किया जाएगा।
19. भंडार का सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाता है।
20. आंकड़ों को निकटतम रूप में निरूपित किया जाता है।

**लेखा टिप्पणी**

1. टीडीबी ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अनुदान के रूप में 9800 लाख रूपए (पिछले वर्ष 10000 लाख रूपए) प्राप्त किए।
2. टीडीबी ने वित्त वर्ष के दौरान 'फाइटिंग कोविड-19' के लिए सहायता अनुदान के रूप में 7500 लाख रूपए प्राप्त किए। अव्ययित धनराशि को अगले वर्ष में लक्षित व्यय में अग्रनयित कर दिया गया है।
3. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के पास बकाया ऋण चुकौती (देय राशि प्राप्त नहीं हुई) 31 मार्च, 2020 तक 21765.44 लाख रूपये (पिछले वर्ष 22087.91 लाख रूपये) की राशि है। इसके अलावा, साधारण ब्याज 10810.20 लाख रु. (पिछले वर्ष 10695.16 लाख रूपये), ऋण पर अतिरिक्त ब्याज 21751.21 लाख रूपये (पिछले वर्ष 21283.99 लाख रूपये) एवं साधारण

4. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) और दिवाला और दिवालियापन नीति 2016 पर सरकार की नीति में बदलाव के साथ, टीडीबी को अतिदेय खातों के प्रयाप्त प्रतिशत की वसूली की उम्मीद है संदिग्ध ऋणों का प्रावधान उधारकर्ताओं के साथ निपटान के लिए अभ्यावेदन ऋण समाधान समितियों (डीआरसी) की सिफारिश या अन्य जानकारी के आधार पर किया जाता है जैसे कि कानूनी विभाग द्वारा ऐसे मामलों में उपलब्ध कराई जाती है, और स्थायी हानि दावा राशि के अंतिम निपटान के बाद निर्धारित की जाती है।
5. वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) में निवेश और मूल्यांकन:

दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार वेंचर कैपिटल फंड में निवेश और मूल्यांकन (वीसीएफ)

क्र. सं.	विवरण	इकाई का एक मूल्य	निर्दिष्ट एवं सटिफ़िड की गई राशि						अति इकाई एनपी			
			31.03.2019 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि		वर्ष के दौरान जमा		वर्ष के दौरान सटिफ़िड / हानि		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार अंत राशि		31.03.19 की स्थिति के अनुसार एनपी	31.03.20 की स्थिति के अनुसार एनपी
			राशि (रुपये में)	इकाई की संख्या	राशि (रुपये में)	इकाई की संख्या	राशि (रुपये में)	इकाई की संख्या	राशि (रुपये में)	इकाई की संख्या		
1	एनआईसीटी वेंचर कैपिटल फंड प्राइवेट लिमिटेड (*)	1,00,000	23,47,86,000	2,348	-	-	2,50,00,000	250	20,97,86,000	2,098	2,984	1,239
2	जीपीएनएल लिमिटेड (अवकाशकर्मचारी)	1,00,000	1,50,000	2	-	-	-	-	1,50,000	-	6,25,24,141	1,62,77,994
3	आईडिया वेल कंजर्न	1,00,000	21,68,92,238	2,169	-	-	10,34,438	10	21,58,57,800	2,159	1,43,138	79,099
4	ब्लू वेंचर कैपिटल फंड / व्हाट्सएप वेंचर कैपिटल	10,000	10,40,00,000	10,400	-	-	76,55,900	766	9,63,44,100	9,634	27,120	28,383
5	एनएचटीएल फंड-व्यवसायिक इकाई	300	11,78,74,724	11,78,747	-	-	34,34,150	34,342	11,44,40,574	11,44,406	107	708
6	सीए इंडिया एडी किराना फंड	3,00,000	22,81,35,470	456	5,77,473	1,86,53,888	37	21,00,49,055	420,10	2,51,346	48,754	
7	फ़्लैग वेंचर कैपिटल लिमिटेड इंडिया ऑपरेटिव्स प्राइवेट फंड	1,000	16,87,26,863	1,68,727	-	-	1,44,18,678	14,419	17,41,08,185	1,74,308	750	677
8	एसेंट इंडिया फंड (**)	100	28,99,20,195	28,99,202	-	-	28,99,20,195	-	-	28,99,202	17	-
9	डिजिटल इंडिया फंड II (**)	758	4,41,43,882	1,50,000	-	-	-	-	4,41,43,882	1,50,000	1,003	1,050
10	सीआईआई-इंडिया फंड वॉर एंटरप्रेनर एनपी (आईआई इकाई) (*)	100	5,46,44,047	5,46,440	20,15,754	20,158	-	-	5,66,59,803	5,66,598	141	123
			1,47,92,73,419	49,78,491	25,93,225	20,159	36,09,27,249	49,823	1,12,17,39,399			

(\*) लेखा परीक्षा नहीं किए गए परिवर्तनों के अनुसार अंतिम एनपी  
 (\*\*) लेखा टिप्पणियों की अनुसूची 25 में संख्या 6 से संबंध में है

	एनपी मूल्य (रुपये में)	निवेश की संख्या	अमूल्यांकित (हानि) / लाभ
संभलत है	96,95,58,550	1,12,17,39,399	-15,21,85,849
घटाना है	1,35,09,15,364	1,47,92,73,419	-12,83,57,855

नोट

- 1) उपरोक्त अनुसूची 24 के पैरा 17 के अनुसार निधि द्वारा वितरण के आधार पर पहचाने गए वेंचर फंड से छूटकारा।
- 2) "यूटीआई इंडिया एसेंट फंड" वर्ष के दौरान परिपक्व हुआ और 2752.89 लाख रूपये के मौचन पर होने वाली हानि फंड को बंद करने पर मान्यता दी गई है।

6. टीडीबी ने मेसर्स ग्लोबल इनोवेशन टेक्नोलॉजी अलायंस (जीआईटीए), सीआईआई के साथ संयुक्त उपक्रम में क्रमशः 51:49 के इक्विटी योगदान में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के सभी प्रमुख तत्वों को समावेशित करने के लिए एक अधिदेश के साथ समझौता किया है जो उद्योग और प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप को डीएसटी और अन्य संगठनों के साथ लाभान्वित करते हैं। जीआईटीए में टीडीबी की इक्विटी भागीदारी 7.35 करोड़ रुपये है। टीडीबी ने 31 मार्च 2020 तक 7.21 करोड़ रुपये वितरित किया।
7. वित्त वर्ष के दौरान वितरित निम्नलिखित सहायता अनुदान

क्र. सं.	कंपनी का नाम	उद्देश्य	धनराशि (लाख रुपये में)
1	इंफो प्रेंच सेन्टर फॉर प्रोमोशन ऑफ एडवांस्ड रिसर्च (सेफीप्रा)	कार्यक्रम प्रबंधन	10.84
	कुल		10.84

#### 8. निर्धारित/संदाय निधि: (अनुसूची 3)

(क) भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान से संबंधित वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) लेनदेन के आधार पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) के खातों में बकाया धन प्राप्ति और देनदारियों का हस्तांतरण बोर्ड को 1 सितम्बर 1996 को हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित होता है। आईडीबीआई ने 31.3.2020 को समाप्त वर्ष के खातों का लेखा परीक्षित विवरण प्रदान नहीं किया है। आईडीबीआई द्वारा पिछले कई वर्षों से उनके द्वारा रखे गए पोर्टफोलियो में मौजूदा निवेशों के लिए कोई और निवेश या वसूली नहीं हुई है। 31.3.2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा किए गए वित्तीय विवरण जो कि (आईडीबीआई की जिम्मेदारी थी) प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार वित्तीय मूल्य शामिल किए गए हैं।

(ख) उधारकर्ता बकाया/वसूली में कोई बदलाव नहीं है अर्थात् उधारकर्ता से वसूली की गई राशि जिसमें ज्ञापन की पुस्तकों में अर्जित ब्याज/अतिरिक्त ब्याज की राशि शामिल है। बकाया उपार्जित ब्याज सहित

खराब ऋणों को बट्टे खाते में डाला जाएगा, जहाँ वसूली प्रक्रिया बंद हो गई है और ऋण खातों से आगे कोई पुनर्मुग्तान की उम्मीद नहीं है और बोर्ड द्वारा बट्टे खाते में डालने के लिए मंजूरी दे दी गई है।

(ग) एसेंट पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिए आईडीबीआई द्वारा लिया गया प्रबंधन शुल्क टीडीबी द्वारा देय नहीं है और इसे निपटाने के लिए आईडीबीआई के सामने प्रस्तुत किया गया है टीडीबी द्वारा आईडीबीआई को 3,62,10,646/- रुपये की धनराशि के भुगतान करने का दावा अंतिम निपटान पर निर्भर है।

9. आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के माध्यम से भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी), यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन सरकार के साथ-साथ टीडीबी के बीच दिनांक 29.8.2013 के समझौता ज्ञापन के माध्यम से करार के अनुसार इस पर सहमति हुई कि "इनोवेटिव वेंचर्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट (इन्वेंट)" कार्यक्रम के उद्भवन घटक को टीडीबी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, और भारत सरकार के साथ कार्यान्वित एवं अनुवीक्षित किया जाएगा। टीडीबी की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होगी कि निधियां परियोजना की समग्र उपलब्धियां और परिणामों को हासिल करने के लिए अपेक्षित अनुमोदित क्रियाकलापों पर खर्च की जाएगी। टीडीबी इस निधि को अलग बैंक खाते में रखने के लिए आभारी है और बैंक जमा राशि पर उपार्जित ब्याज को कार्यक्रम के लिए उपलब्ध और समय-समय पर जारी परियोजना दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्मुक्त की जाने वाली अतिरिक्त निधियों के हिस्से निधि प्रबंधक के रूप में डीएफआईडी को प्रगति रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा प्रस्तुत करना होता है।

10. टीडीबी ने अपने ऋण की वसूली और निष्को कॉर्पोरेशन (प्रा.) लिमिटेड में इक्विटी में इसके निवेश से पहले एनसीएलटी के समक्ष आवेदन दिया था। एनसीएलटी ने इक्विटी में निवेश को टीडीबी द्वारा दिए गए ऋण का हिस्सा माना है। कंपनी की परिसमापन कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली सभी प्राप्तियों को पहली बार बकाया ऋण राशि और इक्विटी के तहत रखे गए निवेश की लागत के शेष के लिए समायोजित किया गया है।

11. वसूली और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किए जाने के कारण निम्नलिखित राशि वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई है।

(रुपये लाखों में)

कंपनी का नाम	मूलधन	व्याज + अतिरिक्त व्याज
मेसर्स बेसिक हेल्थ केयर	-	17.26
मेसर्स सुदर्शन	7.21	152.04
मेसर्स केवीबी एग्री	89.06	16.64
मेसर्स संख्या टेक्नोलॉजी	15.28	41.34
<b>कुल</b>	<b>111.55</b>	<b>228.57</b>

12. ऋणों के कारण संदिग्ध व्याज और अतिरिक्त व्याज का प्रावधान और निम्नलिखित कंपनियों के

कंपनियों के नाम	व्याज और अतिरिक्त व्याज का प्रावधान (लाख रुपये में)			
	2016-17	2017-18	2019-20	कुल
मेसर्स मेडीरेड	705.40	408.81	-	1114.21
मेसर्स कोरल टेलीकॉम	100.04	23.29	-	123.33
मेसर्स वाटर लाइफ	-	1.01	-	1.01
मेसर्स एमालगम लेदर	-	880.78	-	880.78
मेसर्स एक्सपोजेशियल	-	92.88	-	92.88
मेसर्स डॉरवन एग्री	-	-	116.16	116.16
<b>कुल</b>	<b>805.44</b>	<b>1,406.77</b>	<b>116.16</b>	<b>2,328.37</b>

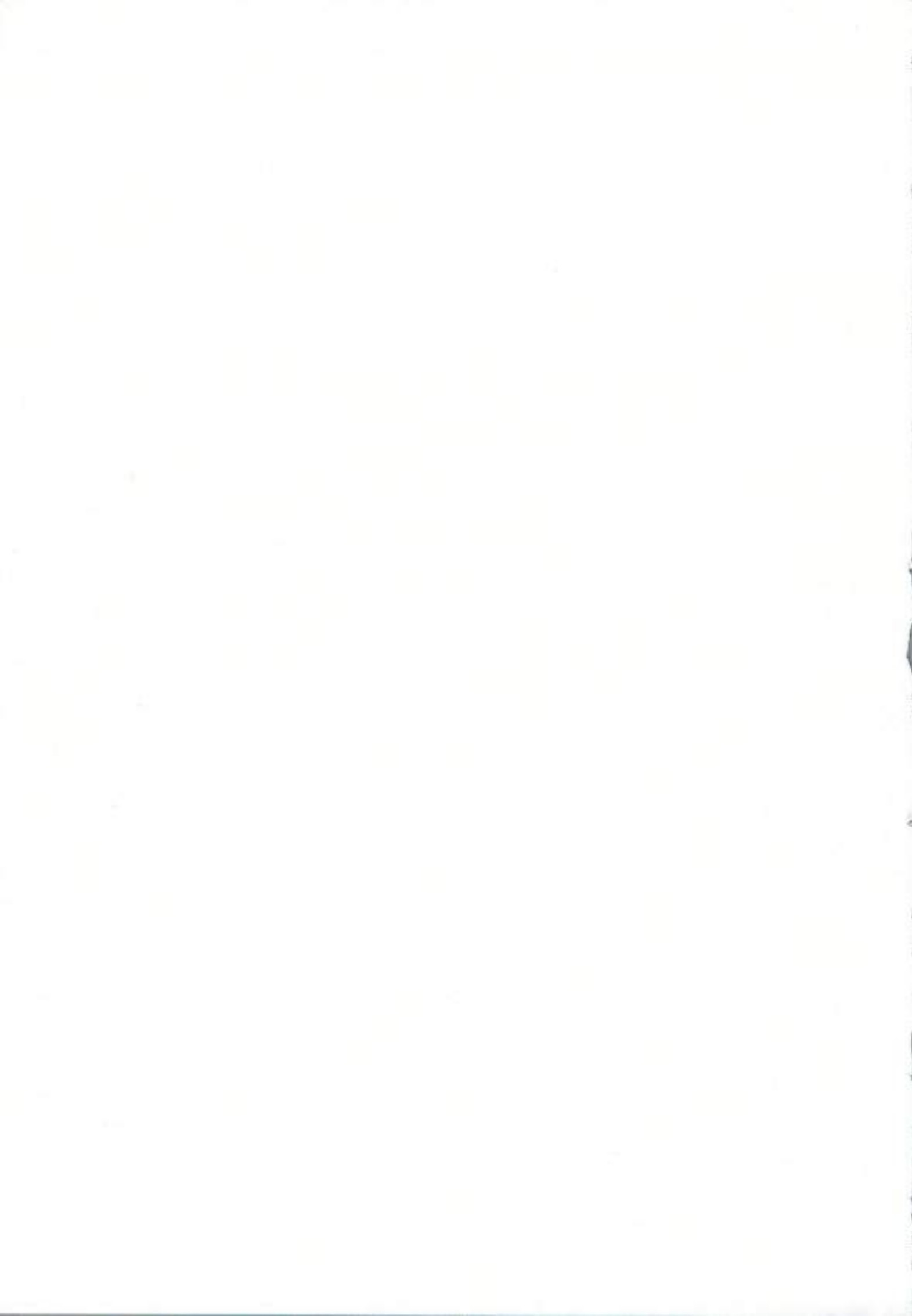
लिए खिलाफ मूल धन का प्रावधान किया गया है, जिन्होंने ऋण वसूली समिति (डीआरसी) की प्रस्तावित सिफारिश के अनुसार अपने देय/बकाया को निपटाने के लिए सहमति दी है और बोर्ड की उप समिति द्वारा अनुमोदित है या जहाँ इस मामले को ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में मंजूर कर लिया गया है और वसूली को संशयपूर्ण बताई जाती है।

14. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए पुनर्संगठित और पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

-इ-  
(राजेश जैन)  
निदेशक  
प्रीद्योगिकी विकास बोर्ड

-इ-  
(डॉ. नीरज शर्मा)  
सचिव  
प्रीद्योगिकी विकास बोर्ड

-ए-  
(प्रो. आशुतोष शर्मा)  
अध्यक्ष  
प्रीद्योगिकी विकास बोर्ड





वर्ष 2019–20 की पृथक  
सी एंड एजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट

## प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-20 के लेखा के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (वर्ष 1995 की सं. 44) की धारा 13 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार प्रौद्योगिकी बोर्ड (टीडीबी) के संलग्न तुलन पत्र और उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण बोर्ड के प्रबंधन के उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, उत्तम लेखांकन पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों, आदि के संबंध में लेखांकन व्यवहार के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां निहित हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमबद्धता) और दक्षता- सह निष्पादन पहलुओं यदि कोई हो, के अनुपालन संबंधी वित्तीय संव्यवहार विषयक 'लेखा परीक्षा' टिप्पणियों को निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से प्रतिवेदित किया जाता है।
3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन मानदंडों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के लिए अपेक्षित है कि हम उस बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा आयोजित एवं निष्पादन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण तथ्यगत अशुद्धियों से मुक्त है। लेखा परीक्षा में नमूना आधार पर जांच करना, धन राशि को समुचित करने वाले साक्ष्य तथा वित्तीय में प्रकटीकरण सम्मिलित है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा अपनी राय के लिए युक्तिसंगत आधार पर उपलब्ध कराता है।
4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम प्रतिवेदित करते हैं कि:
  - i) हमने उन सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण को प्राप्त कर लिया है जो हमारे ज्ञान एवं विश्वास की बेहतर समझ से हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थीं।
  - ii) इस रिपोर्ट में जिस तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखे और प्राप्ति एवं भुगतान लेखे पर कार्रवाई का उल्लेख किया गया है, उन्हें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में तैयार किया गया है,
  - iii) जैसा कि ऐसी बहियों की जांच से प्रतीत होता है, हमारे मत में, बोर्ड द्वारा, अपेक्षानुसार, उपयुक्त लेखा बहियों और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्डों का रखरखाव किया गया है।
  - iv) हमें आगे प्रतिवेदित करते हैं कि:

### क. तुलन पत्र

परिसम्पत्तियां

अचल परिसम्पत्तियां : ₹ 66.77 लाख (अनुसूची B)

बोर्ड ने वेबसाइट मोड्यूल के निर्माण के लिए वर्ष के दौरान संयोजन के रूप में "सॉफ्टवेयर (पीएमएस)" शीर्ष के अंतर्गत ₹ 7.19 लाख की धनराशि को पूंजी के रूप में परिणत किया जिसमें उसका बिना अयमूल्यन किए विगत वर्ष (अर्थात् 2018-19) के दौरान पहले से ही पूंजी में परिणत ₹ 5.50 लाख शामिल है। इस कुटि को विगत वर्ष में भी स्वीकार किया गया था। पुनः चालू वर्ष के दौरान, ₹ 1.44

लाख का अवमूल्यन ₹ 3.80 लाख (विगत वर्ष के लिए ₹ 2.10 लाख और चालू वर्ष के दौरान ₹ 1.70 लाख) के बजाय केवल छमाही (अर्थात् 20% की दर से) के लिए प्रभारित किए गए। इस प्रकार, टीडीबी द्वारा अनुपयुक्त लेखांकन व्यवहार के कारण परिसम्पत्तियों को निर्धारित तरीके से नहीं किए गए अवमूल्यन के लिए व्यय/पूर्वावधि व्यय के अल्प विवरण के अतिरिक्त ₹ 2.36 लाख अतिरिक्त की गई है।

## ख. सामान्य

### ख. 1 निर्धारित/संदाय निधि से निवेश— ₹ 65.99 लाख (अनुसूची 9)

इससे पहले ही विगत वर्ष की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से टीडीबी के ध्यान में लाया गया था कि 'इक्विटी' के रूप में कंपनियों में किए गए निवेश को उचित बाजार मूल्य पर दर्शाया जाना होता है।

तथापि, टीडीबी ने इक्विटी में किए गए निवेश के मूल्य के ₹ 65.99 लाख के विगत वर्ष के आंकड़े (इसके मूल्य में अवमूल्यन के बाद) को अपनाया/समाविष्ट किया गया। चूंकि, चालू वर्ष में इक्विटी के वास्तविक/लेखा परीक्षित आंकड़े को वर्ष 2019-20 की खारा वही में प्रतिवेदित नहीं किया गया था, इसलिए लेखा परीक्षक यह आश्वस्त करने में असमर्थ है कि उक्त वर्ष के दौरान इक्विटी के मूल्य में कोई अनुवर्ती अवमूल्यन नहीं हुआ है और दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार निवेश के रूप में प्रतिवेदित ₹ 65.99 लाख का आंकड़ा सही और प्रामाणिक है।

### ख. 2 निवेश—अन्य ₹ 14019.52 लाख (अनुसूची 10)

(₹ 14019.52 – ₹ 2081.63 लाख = ₹ 11937.89 लाख)

'इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ)' के रूप में विभिन्न कम्पनियों में किए गए निवेशों के रूप में 2019-20 के लिए टीडीबी के तुलन पत्रा के साथ संलग्न अनुसूची 10 : निवेश – अन्य में ₹ 14019.52 लाख रु. की राशि का सूचना दी गई थी।

यह पाया गया कि विगत पाँच वर्षों से चार वीसीएफ के निवल परिसम्पत्ति मूल्य में सतत कमी आई है अग्रनयन राशि में कमी और ऐसी कमी की प्रत्यावर्तन राशि को लाभ और हानि विवरण पर प्रभारित अथवा संयोजित करना होता है। तथापि, विगत वर्ष की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित किए जाने के बावजूद टीडीबी उचित बाजार मूल्य (अनुलग्नक-क) पर उन्हें पुनर्मूल्यन नहीं किया, अतः लेखा परीक्षक यह आश्वासन देने में असमर्थ है कि पहले और इस वर्ष के दौरान इक्विटी के मूल्य में कोई अनुवर्ती अवमूल्यन नहीं हुआ है और दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार निवेश-अन्य के रूप में प्रतिवेदित ₹ 140.20 करोड़ का आंकड़ा सही और प्रामाणिक है।

## ग. सहायता अनुदान

टीडीबी को प्रौद्योगिकी के आयात के लिए किए गए भुगतान पर पाँच प्रतिशत की दर से सरकार द्वारा भारित एवं संकलित अनुसंधान एवं विकास उपकरण में से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभा से अनुदान प्राप्त होता है। 2019-20 के दौरान टीडीबी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से ₹ 98.00 करोड़ का अनुदान मिला।

वर्ष 2019-20 के दौरान, ₹ 71.21 करोड़ के रोकड़/बैंक शेष के अथ शेष के अतिरिक्त ₹ 166.47 करोड़ की धनराशि टीडीबी को अल्पावधि जमा/ऋण/रॉयल्टी/अनुदान/ऋण की अदायगी, रॉयल्टी, वेंचर फंड से आय, दान आदि से प्राप्त हुई। निवेश, स्थापना/कार्यालय खर्च और ऋण/अनुदान आदि के संवितरण के लिए ₹ 148.62 करोड़ का कुल भुगतान करने के बाद ₹ 187.07 करोड़ की धनराशि को दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार अव्ययित दर्शाया गया।

#### घ. प्रबंधन पत्र

कमियाँ जिन्हें पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उपघातात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली को ध्यान में लाई गई है।

- i) पूर्ववर्ती पैरा में हमारी टिप्पणियों के अध्यक्षीय हम प्रतिवेदित करते हैं कि इस रिपोर्ट के जरिए उल्लिखित तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्त एवं भुगतान लेखा खाता बही के अनुरूप हैं।
- ii) हमारी राय में और हमें प्राप्त उत्तम जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखांकन नीतियां एवं लेखा टिप्पणियों के साथ-साथ पठित वित्तीय विवरण और टिप्पणी क्रम सं. 1 और 2 में कथित उल्लेखनीय मुद्दों और अन्य कथित मुद्दे, और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मुद्दों के अध्यक्षीय भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित हैं।
- iii) यहाँ तक कि यह दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार टीडीबी के सरकारी कार्यों के तुलन पत्र से संबंधित है।  
(ख) यहाँ तक कि यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष की आय और अधिशेष के व्यय लेखा से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (निरीक्षण) की ओर से

-६-

लेखा परीक्षा महानिदेशक  
(वैज्ञानिक विभाग)

दिनांक:

स्थान: नई दिल्ली

## आंतरिक नियंत्रण तंत्र

### 1. आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र की पर्याप्तता

टीडीबी की वर्ष 2016-18 की आंतरिक लेखा परीक्षा कराई गई है।

### 2. आंतरिक नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कमियां पाई गई:

#### 2.2 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 238 के अनुसार प्रत्येक अनुदानग्राही संस्थान को यह दर्शाते हुए कि अनुदान का उपयोग उस प्रयोजनार्थ किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था, वित्त वर्ष समाप्त होने के 12 माह के भीतर उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है। तथापि, पूर्व लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित किए जाने के बावजूद टीडीबी ने कुल ₹ 229.08 लाख के 12 मामलों के संबंध में अनुदानग्राही संस्थान से उपयोग प्रमाण-पत्र समय पर प्राप्त नहीं किया।

#### 2.3 मंत्रालय द्वारा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली की समकक्ष समीक्षा न किया जाना

जीएफआर 2017 के नियम 299 (ix) में क्रियाकलाप के आकार और स्वरूप के अनुसार प्रत्येक तीन अथवा पाँच वर्ष में स्वायत्त संगठनों की बाहरी अथवा समकक्ष समीक्षा तंत्र की मौजूदगी का उपबंध है। ऐसी समीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ उस उद्देश्य पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए जिसके लिए स्वायत्त संगठन गठित किया गया था और क्या ये उद्देश्य पूरे कर लिए गए हैं या पूरे किए जा रहे हैं, संगठन के क्रियाकलाप जारी हैं अथवा उनके अब प्रासंगिक नहीं रहने अथवा पूरा कर लिए जाने अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति में बड़ी विफलता की वजह से बंद कर दिए गए हैं, क्या प्रदत्त सेवाओं के लिए प्रयोक्ता प्रभार उचित दर पर लगाए जाते हैं, आंतरिक संसाधन सृजन बढ़ाने की गुंजाईश ताकि सरकारी बजट सहायता पर निर्भरता को कम किया जा सके, आदि।

तथापि सितम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार बोर्ड की समकक्ष समीक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं कराई गई जो उपर्युक्त नियमावली के अनुसार अपेक्षित थी।

#### 2.4 बकाया बैंक प्रभार

जाच से पता चला कि केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने खाता सं. 1484101021952 और खाता सं. 349902010043607 31 मार्च, 2020 तक बाहरी प्रभार और बैंक प्रभार के लिए क्रमशः ₹ 184851.99 और ₹ 66704.40 की कटौती की जो 31 अगस्त, 2020 की स्थिति के अनुसार बिना निपटान किया हुआ रखा गया था। इस मामले को अभिज्ञात एवं निपटान करने के लिए इस मुद्दे को बैंक प्राधिकारी के समक्ष उठाया जा सकता है।

### 3. अचल परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2019-20 के लिए अचल परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया और कोई विसंगति प्रतिवेदित नहीं की गई।

### 4. सामानों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2019-20 के लिए सामानों का भौतिक सत्यापन किया गया और कोई विसंगति प्रतिवेदित नहीं की गई।

### 5. सांविधिक बकाया राशि के भुगतान में नियमितता:

कोई सांविधिक बकाया राशि नहीं थी।

-8-

उपनिदेशक  
(निरीक्षण)

क्र. सं.	फर्म का नाम	इक्विटी का प्रति इकाई अंकित मूल्य (रु.में)	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार एनएवी	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार एनएवी	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार एनएवी	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार एनएवी	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार एनएवी
1	आईवी जॉय वेयर ट्रस्ट फंड*	1,00,000.00	1,28,297.83	1,60,512.17	1,57,348.94	1,43,138.00	79,099.00
2	सीफ इंडिया एपी बिजनेस फंड	5,00,000.00	3,60,559.00	3,94,294.00	4,29,827.00	2,51,346.00	48,754.00
3	सिडबी वेयर कैपिटल ओपॉरट्यूनिटी फंड	1,000.00	881.63	800.35	793.86	750.00	677.00
4	एसेंट इंडिया फंड	100.00	51.87	40.51	32.72	17.00	शून्य

(\* ) गैर लेखा परीक्षित परिणामों के अनुसार निवल परिसम्पत्ति मूल्य।



सत्यमेव जयते

## Technology Development Board

Department of Science & Technology  
Government of India

**24<sup>th</sup>**  
**ANNUAL**  
**REPORT**

**2019-20**





## Content

Secretary's Desk	05
TDB's Mandate	06
Sectors funded by TDB	06
Board Members	08
Overview	09
TDB-Year at a glance	21
Agreement Signed	29
Projects Completed	35
Promotional Activities	43
Administration	51
Audited Annual Accounts Statement for the year 2019-20	53
Separate Audit Report of C&AG for the year 2019-20	81





## FROM SECRETARY'S DESK

It gives me great pleasure in sharing with you the achievements of TDB for the year 2019-20.

In the year 2019-20, TDB entered into five agreements to provide financial assistance to various industrial concerns. Through these agreements, TDB committed ₹ 29.87 Crore assistance out of total project outlay of ₹ 70.32 Crore covering various sectors such as Agriculture, Energy and Waste utilization and Health & Medical. This year, TDB received 23 applications for financial assistance from various industrial concerns.

During the year, TDB disbursed an amount of ₹ 128.74 Crore towards ongoing and new projects and other schemes. This included ₹ 128.37 Crore as loan, ₹ 0.11 Crore as grant and ₹ 0.26 Crore to VCF for investment.

The INVENT program initiated with DFID

(Department for International Development), United Kingdom in 2015-16, came to a close in this year. It has incubated 150 entrepreneurs, out of which 141 companies have signed the agreements and 30 of which have raised follow-on funding to the tune of ₹ 76.50 Crore. It has estimated to have touched around 6.2 lakh lives with employment generated for around 5000 people in the low-income states.

TDB has so far participated in 11 Venture Capital Funds, along with other investors; with a total commitment of ₹ 285.00 Crore, TDB has invested in close to 220 companies. This year ₹ 0.26 Crore were invested towards VCF's.

Of the projects sanctioned earlier, 07 were declared completed and commercialized, one of which was by M/s Grasim Industries Limited, Mumbai for setting up the project "Birla Excel Solvent Spun Cellulosic Fibre Plant" with an investment of ₹ 250.00 Crore and a total project cost of ₹ 689.00 Crore. A total of 10 companies settled their loan account by completing the repayments.

The Board met twice during the year and helped in speedy and effective decision making.

TDB actively participated in many events and exhibitions which helped in boosting TDB's role as a technology promoter towards making India self-reliant.

This year also saw TDB reinventing itself and furthering its mandate of commercialisation indigenous technology. TDB inducted fresh manpower for further streamlining its functioning. While the year was coming to an end, the world was struck by COVID-19 pandemic. The Board took a proactive approach towards fighting COVID-19 and issued a call for proposals on 20.03.2020 inviting applications from Indian companies and enterprises for technologically innovative solutions in various domains.

Overall, the year 2019-20 has been an effective year for TDB.

(Dr. Neeraj Sharma)

## TDB's Mandate

---

- Provide financial assistance to industrial concerns and other agencies attempting commercial application of indigenous technology or adapting imported technology for wider domestic applications;
- Provide financial assistance to such research and development institutions engaged in developing indigenous technology or adaptation of imported technology for commercial application, as may be recognized by the Central Government;
- Perform such other functions as may be entrusted to it by the Central Government.

## Sectors Funded by TDB So Far



## Composition of The Technology Development Board

(As on 31<sup>st</sup> March, 2020)

1.	<b>Prof. Ashutosh Sharma</b> Secretary, Department of Science & Technology	Ex-officio Chairperson
2.	<b>Dr. Shekhar C. Mande</b> Secretary, Department of Scientific & Industrial Research	Ex-officio Member
3.	<b>Dr. G. Satheesh Reddy</b> Secretary, Department of Defence Research & Development	Ex-officio Member
4.	<b>Dr. T. V. Somanathan</b> Secretary, Department of Expenditure	Ex-officio Member
5.	<b>Dr. Guruprasad Mohapatra</b> Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion	Ex-officio Member
6.	<b>Shri Rajesh Bhushan</b> Secretary, Department of Rural Development	Ex-officio Member
7.	<b>Prof. Deshdeep Sahdev</b> Mentor, Quazar Technologies Pvt. Ltd., New Delhi	Member
8.	<b>Ms. Bineesha P.</b> Executive Director, International Institute of Waste Management, Bangalore	Member
9.	<b>Shri Sabu M. Jacob</b> Managing Director, Kitex Garments Ltd., Ernakulam- Kerala	Member
10.	<b>Shri Pradeep Goyal</b> Chairman, Pradeep Metals Ltd., Navi Mumbai	Member
11.	<b>Dr. Neeraj Sharma</b> Secretary, Technology Development Board	Ex-officio (Member Secretary)

## Board Member

(As on 31<sup>st</sup> March, 2020)



Prof. Ashutosh Sharma



Dr. Shekhar C. Manda



Dr. G. Satheesh Reddy



Dr. T. V. Somanathan



Dr. Guruprasad Mohapatra



Shri Rajesh Bhushan



Prof. Deshdeep Sahdev



Ms. Bineesha P.



Shri Sabu M. Jacob



Shri Pradeep Goyal



Dr. Neeraj Sharma



# Overview

# Overview

The Government of India constituted the Technology Development Board (TDB) on September 01, 1996 as per the provisions of the Technology Development Board Act, 1995 with an aim to promote development and commercialization of indigenous technology and adaptation of imported technology for wider domestic applications. TDB provides financial assistance to industrial concerns and other agencies attempting such development and commercial application.

The Act enabled the creation of a Fund for Technology Development and Application to be administered by TDB. The Fund receives grants from the Government of India out of the R&D Cess collected by the Government from the industrial concerns under the provisions of the Research and Development Cess Act, 1986, as amended in 1995. The Act also enables TDB to build up the Fund by crediting all sums received by TDB from any other source, recoveries made of the amounts granted from the Fund, and any income from investment of the amount of the Fund. The Finance Act, 1999, enabled full deductions to donations to the Fund for income tax purposes.

In its General Budget 2017-18, the Central Government abolished Research and Development Cess Act, 1986 w.e.f. 1<sup>st</sup> April, 2017. During the period of 1996-97 to 2016-17, the Government has collected ₹ 7974.32 Crore as R&D Cess.

TDB received accumulative sum of ₹ 977.47 crore over the period of 24 years (1996-97 to 2019-20) as Grant-in-aid from non-plan budget of the Department of Science & Technology, Government of India.

## Modes of Financial Assistance

The financial assistance from TDB is available in the form of loan or equity and/or in exceptional cases, as a grant. Application for financial assistance from Industrial concerns (incorporated under the Companies Act, 1956 or as per Companies Act 2013) is accepted throughout the year.

### Loan

The financial assistance to the industrial concerns is provided as a soft loan at 5% simple rate of interest per annum. The limit of financial assistance in the form of Loan is 50% of the unincurred project cost. The loan amount is disbursed in installments as per the implementation of associated milestones in accordance with the terms and conditions as stipulated in the loan agreement. Royalty is payable on sales of products under TDB's project during concurrency of the loan.

In some cases, TDB may have nominee director(s) on the Board of Directors of the assisted industrial concern. The implementation period of a project should generally not exceed three years. The loan and interest is secured through collaterals and guarantees. Normally, the repayment of the loan and payment of interest commences after the project is completed and a moratorium period not exceeding one year. The loan amount is generally recoverable in nine, half yearly installments. The accumulated interest upto the repayment of the first installment is distributed over a period of three years.

TDB does not collect administrative, processing or commitment charges from the applicants.

## Equity

TDB contributes by the way of equity capital in an industrial concern (incorporated under the Companies Act, 1956 or as per Companies Act 2013), on its commencement, start-up and/ or growth stages according to the requirements as assessed by TDB and keeping in view the debt-equity ratio. The equity subscription is decided by the full Board of the TDB. It is upto 25 percent of the approved project cost, provided such investment does not exceed the capital paid-up by the promoters. TDB does not consider

substituting the existing loan or equity of the industrial concerns which have obtained such finances from other institutions.

## Grant

TDB also provides financial assistance by way of grants to industrial concerns and R&D institutions engaged in developing indigenous technologies. The sanction of grants is decided by the full Board and provided in exceptional cases having importance towards fulfilling national interest.

The following table indicates the modes of financial assistance provided by TDB till March 31, 2020:

(₹ in Crore)

Instrument	*Sanctioned by TDB	Disbursement by TDB
Loan	1729.17	1506.17
Equity	33.06	34.66
Grant	150.66	150.60
Venture Funds	285.00	252.77
<b>Total</b>	<b>2197.89</b>	<b>1944.20</b>

\* The actual sanctioned amount by TDB as on 31.03.2020 may vary due to conversion of loan into equity in some cases in the past and revision in quantum of financial assistance, foreclosure and cancellations.

## Sector-wise Coverage of Agreements

TDB's financial assistance has covered almost all sectors of the economy. Till March 31, 2020, TDB has signed 360 agreements since its inception in 1996 with a project cost of ₹ 8407.64 Crore and TDB's commitment of ₹ 2197.89 Crore. TDB has disbursed ₹ 1944.20 Crore out of grant-in-aid of ₹ 977.47 Crores provided by Government and through internal accruals.

The following table gives sector-wise projects sanctioned by TDB upto March 31, 2020, since inception in 1996-97.

(₹ in Crore)

S. No.	Sector	Number of Agreements	Total Cost	TDB's Commitment
1	Health & Medical	96	2015.62	587.85
2	Engineering	69	699.96	256.98
3	Information Technology	45	454.54	169.31
4	Chemical	26	236.80	84.69
5	Agriculture	27	217.48	69.85
6	Telecommunication	12	99.88	37.85
7	Road Transport	10	527.04	81.20
8	Energy & Waste Utilization	10	140.10	59.61
9	Electronics	4	52.56	17.75
10	Defence and Civil Aviation	10	648.83	229.95
11	Textile	1	689.00	250.00
12	Others – Including			

## Overview

Venture Funds	11	2463.00	285.00
STEP-TBIs	35	35.00	35.00
CII	1	0.83	0.50
Millennium Alliance	1	112.00	25.00
Global Innovation & Technology Alliance	1	15.00	7.35
INVENT Programme	1	-	-
<b>Grand Total</b>	<b>360</b>	<b>8407.64</b>	<b>2197.89</b>

The support by TDB is largely market-driven and technology oriented in all its new ventures and various industrial sectors.

## State-wise Distribution of Agreements (1996-2020)

The State-wise distribution (based on registered office of the company) of agreements signed during the years 1996-2020 is given below:

(₹ in Crore)

S. No.	State/ Union Territory	Number of Agreements	Total Cost	TDB's Commitment
1	Assam	1	18.31	8.20
2	Andhra Pradesh/ Telangana	86	1677.97	541.34
3	Karnataka	45	1027.96	355.67
4	Maharashtra	48	1624.18	450.93
5	Tamil Nadu	37	319.51	100.38
6	Delhi	22	310.57	114.38
7	Gujarat	14	149.06	45.94
8	West Bengal	10	137.39	57.57
9	Uttar Pradesh	12	94.77	50.44
10	Madhya Pradesh	7	155.92	42.20
11	Haryana	7	47.57	19.48
12	Punjab	7	91.79	21.98
13	Chandigarh	4	43.75	16.50
14	Kerala	5	21.63	8.15
15	Himachal Pradesh	1	6.24	1.90
16	Jammu & Kashmir	1	5.65	2.38
17	Manipur	1	7.94	2.70
18	Pondicherry	1	5.83	1.90
19	Rajasthan	1	35.77	3.00
20	Others – Including			
	Venture Funds	11	2463.00	285.00
	STEP-TBIs	35	35.00	35.00
	CII	1	0.83	0.50
	Millennium Alliance	1	112.00	25.00
	Global Innovation & Technology	1	15.00	7.35
	INVENT Programme	1	-	-
	<b>Grand Total</b>	<b>360</b>	<b>8407.64</b>	<b>2197.89</b>

## Submission of the Project Proposal

An industrial concern seeking financial assistance from TDB needs to submit the application in the prescribed format. The format of the application for seeking financial assistance and other details are provided in 'Project Funding Guidelines' available on TDB's website. Industrial concern may apply online @<http://e-techcom.tdb.gov.in> in any time through out the year.

## Processing of Project Proposals

Applications received are processed extensively by the Committee encompassing Technical and Financial Experts.

## Initial Screening of Applications

A duly constituted Initial Screening Committee (ISC) preliminarily examines the applications received for financial assistance, from the point of view of completeness of the application, objective of the project, status of the technology etc.

The committee composition involves Technical domain Experts and Financial Experts from reputed National Institutions/Organizations. In front of this committee, applicants and/ or technology provider gives a detailed presentation followed by questionnaire by the Experts to have more clarity on submitted project. As per the suggestion/ remarks of the Committee, if additional information / details or further clarification is required for assessment, it is sought from the Company.

If the application does not meet the eligibility criteria prescribed for TDB's financial assistance, the ISC may not recommend the application for further processing after providing written reasons.

## Project Evaluation Committee (PEC)

Based on the recommendations of the ISC, the application is referred to a PEC for further assessment and evaluation including visit to

the project site. For each project, a PEC is constituted keeping in view the nature of the project. PEC consists of experts (scientific, technical and financial) in the relevant fields from outside TDB for an independent evaluation of the project. The experts (serving or retired) may belong to government departments, R&D organizations, academic institutions, industry, industry associations, financial institutions and commercial banks. The applicant along with the technology provider is given full opportunity to give a detailed presentation on the scientific, technical, marketing, commercial and financial aspects and to provide in-depth information on various issues related to the project & the company.

## Evaluation Criteria

The application is evaluated for its scientific, technological, commercial and financial merits. The evaluation criteria include:

- Uniqueness and innovative content of the proposal
- Soundness, scientific quality and technological merit
- Potential for wide application and the benefits expected to accrue from commercialization
- Adequacy of the proposed effort
- Capability of the R&D institution(s) in the proposed action network
- Organizational and commercial capability of the enterprise including its internal accruals
- Reasonableness of the proposed cost and financing pattern
- Measurable objectives, targets and milestones
- Track record of the entrepreneur

## Confidentiality and Transparency

TDB recognizes that it is important to maintain confidentiality, as each proposal is a commercial

proposal involving a new product or process. In case the applicant mentions that some information provided in the project proposal has to be treated as strictly confidential, it is not circulated to the experts of the PEC. The PEC respects the sensibility of the applicant's apprehensions in disclosing certain vital information on the processes.

After a comprehensive discussion / deliberation with the applicant, the observations and recommendations are finalised by the experts constituting the PEC.

### Approval of Financial Assistance

The recommendations of PEC are approved by Chairperson TDB. All the project proposals recommended by the PEC where TDB's assistance exceeds ₹ 10.00 Crore or total project cost is above ₹ 30.00 Crore, are processed for third party due-diligence. The PEC inputs along with third party due-diligence report are put up to the Board for their approval. Rest of the recommended cases are put up to the respective Competent Authority for their approval.

### Monitoring and Review

TDB disburses the approved financial assistance to the beneficiaries in instalments that are based on compliance of pre-defined milestones as per the mutually agreed Loan Agreement.

The project is monitored periodically by the Project Monitoring Committee. The PMC consists of scientific/ technical and financial experts.

### Proactive Role

Besides responding to the applications received from industrial concerns and other agencies, TDB takes a pro-active role to ensure a comprehensive support for technology development and commercialization. Under the aegis of its mandate, TDB has encouraged development and

commercialization of indigenous technologies through various initiatives. Some of them are as follows:

#### a) Participation in Venture Capital Funds (VCFs)

Technology Development Board (TDB) realized that many technological projects are unable to satisfy the traditional requirements of financial institutions and commercial banks. In addition to directly supporting indigenous technologies for commercialization, TDB felt the need for networking with other institutions to encourage technology focused Venture Capital Fund (VCF) to ensure that lack of adequate funds is not an obstacle for good technologically innovative viable projects.

TDB thus participated in Venture Capital Funds to provide support to early stage ventures through SMEs having innovation and innovative products /services. TDB's motivation and participation has resulted in the venture capitalists contouring their assistance to TDB's mission. The Board also considered TDB's participation in VCFs as a tool for increasing geographical spread of the mandate of TDB to support technology companies especially in the MSMEs/SMEs category having innovation and innovative products / services.

The initiative of TDB has also given confidence to Venture Capitalist/Private Equity Funds to come up in big way to support technology-based projects with a pronounced emphasis on sectors which are growth drivers of Indian economy.

#### b) Seed Support for Start-ups in Incubators

In 2005, TDB instituted the Seed Support Scheme to provide early stage/start-up financial assistance to young entrepreneurs with innovative technology venture ideas to incubate and bring

their ideas under development to fruition and finally to reach the market place. The proposed assistance was positioned to act as a bridge between development & commercialization of the technologies. The scheme was started for providing financial assistance for Start-ups in Incubators /Technology Business Incubators (STEP/TBI) administered by the National Science & Technology Entrepreneurship Development Board (NSTEDB) of DST.

Till 31<sup>st</sup> March, 2018, TDB has supported 35 (which includes two times financial assistance to 4 TBIs/STEPS) TBIs and STEPs with a financial assistance of ₹ 1.00 Crore each aggregating to ₹ 35.00 Crore. These incubators have provided assistance to several incubates companies for their project spread in the areas of Telecom, IT, Robotics, Agriculture, Instrumentation, Engineering, Environment, Pharma, Food, Solar, Textile and Biotechnology. The scheme progressed well and benefited a number of entrepreneurs in up-scaling and related work. It also facilitated in building up a corpus of incubation fund by the incubators.

### c) International Collaboration

#### i) MoU with Bpi-France

TDB continues its technical collaboration with Bpi-France France erst while, OSEO, France as per renewed Memorandum of Understanding (MoU) between TDB and Bpi-France along with CEFIPRA as the managing partner. The agreement was signed in 2016 and is valid for a period of 5 years. The agreement entails to carry out activities related to the exchange of best practices and setting up of coordinated measures to foster technological exchanges in the field of Science, Technology and Innovation through collaboration between companies, organizations and institutions of France & India. This program aims to fund proposals on Aeronautics, Automotive & Biotechnology areas.

#### ii) MoU with Department for International Development (DFID), UK

TDB in partnership with Department for International Development (DFID), UK initiated the Innovative Ventures and Technologies for Development (INVENT) Programme in the FY2015-16. The program was designed to create a platform to support inclusive innovation solutions, both technological and process oriented, that have a positive social and economic impact on people in the lower income segments, also known as the Bottom of the Pyramid (BoP). The support includes, but not be limited to the provision of funding, intense mentoring, knowledge and access to capacity building programmes, support services, and relevant networks in the 8 Low Income States (LIS) of India (UP, MP, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Rajasthan, Orissa and West Bengal).

#### The ultimate aim:

- Creating the viable social enterprises pipeline for impact investment in the above mentioned 8 LIS.
- Generate 50 investments ready for profit social enterprises in 8 Low Income States.
- Support 160 entrepreneurs in the 8 Low Income States.

#### The Impact

- An ecosystem will be in place to diversify the funding opportunities that are appropriate to scale social enterprises in 8 LIS.
- Increment in government support to break down the cultural barriers and encourage more people to get involved in social entrepreneurship.
- Established social incubator with strong recognition

An Agreement was executed between TDB and M/s Villgro Innovations Foundation (VIF) in FY 2015-16 wherein Villgro was selected to act as

the lead incubator to provide incubation support aimed at creating a viable social enterprise (for profit) pipeline for impact investments in the 8 low income states of India. Villgro is presently supporting four incubators viz. IIM Calcutta Innovation Park (IIMCIP), KIIT Technology Business Incubator at Bhubaneswar (KIIT TBI), SIDBI Innovation & Incubation Centre at IIT Kanpur (SIIC IITK) and Startup Oasis (an initiative of CIIE, IIM Ahmedabad and RIICO) in the LIS to hand-hold innovative businesses at seed or early stages of enterprise development that benefit the poor in the LIS of India while being commercially successful.

### d) National Collaborations:

#### • MoU with WWF-India for Climate Solver Partner

Considering India's strength in innovation wherein it has been ranked 12<sup>th</sup> on the Global Clean Tech Innovation Index 2012, TDB decided to join the Climate Solver Platform launched by WWF-India on 21<sup>st</sup> May 2012.

In India, besides TDB, the Confederation of Indian Industry (CII), New Ventures India, Centre for Innovation Incubation & Entrepreneurship (IIM Ahmedabad) and Sky quest Technology Consulting Pvt. Ltd. participated in this programme.

#### • MoU with TIFAC

TDB and Technology Information Forecasting and Assessment Council (TIFAC) an autonomous body under DST signed an MoU on "Transformational Technological Innovation" on 10<sup>th</sup> February, 2018 with an aim to scout for innovative technologies, commercialize indigenous technologies and invest in companies commercializing such technologies. The areas and scope of cooperation include:

- Scouting of emerging (core thrust) technologies/

technological areas with investment trends and the forces driving those;

- Identifying technologies which have the ability to transform social and economic environment as well as generate employment for the growing youth of the nation on immediate, medium-term and long-term basis.
- Developing policy frame works for easy adoption of technology; up scaling and manufacturing leading to its commercialization in the nation for the identified domains.

#### • MoU with ICCo

TDB and Innovative Change Collaborative (ICCo) India organisation, a development organisation working in India signed an MoU on "Transformational Agricultural Technology Business Solutions" on 6<sup>th</sup> March, 2018 with an aim to scout for innovative agricultural technologies, commercialize indigenous technologies and invest in companies which will exhibit the potential to double farmers' income. The areas and scope of cooperation include:

- Scouting of relevant agriculture technology business solutions in pre-harvest domain, allied agriculture, post-harvest domain;
- Identifying technologies and business solutions which demonstrate the ability to transform rural economic environment as well as generate employment for rural youth of the nation on immediate, medium-term and long-term basis.
- Assessing the ability of interested agri-tech businesses in the identified domains to truly improve farmers' income level by evaluating their technology readiness and business model for commercial and financial viability.

#### • MoU with PHD Chambers of Commerce and Industry

TDB and PHD Chambers of Commerce and Industry (PHDCCI) signed MoU on 25<sup>th</sup> April, 2018 to scout for emerging technologies/

technological areas of National Importance such as Agribusiness and Food Processing, Healthcare and Pharmaceuticals, Electric Mobility, Water and Waste to Energy, Automobiles, etc. and identify factors driving those; also to develop policy frameworks for easy adoption of technology, upscaling and manufacturing leading to its commercialization. Both the organizations are collaborating in identifying industries with technology-driven projects which may have social and economic implications and generate employment on immediate, medium-term and long-term basis.

#### • MoU with ASSOCHAM

TDB and the Associated Chambers of Commerce & Industry of India (ASSOCHAM) signed an MoU on 3<sup>rd</sup> May, 2018 to scout for emerging technologies/technological areas of national importance such as Pharmaceuticals, Medical Devices & Diagnostics, Agriculture, Food Processing, Defence & Aerospace, Electric Mobility and Automobiles; and identify factors driving those; also to develop policy frameworks for easy adoption of technology, upscaling and manufacturing leading to its commercialization. Both the organizations are working in close association through seminar, symposia and project-writing workshops to identify companies with prototypes technologies/technology-driven projects with commercial outcome on immediate, medium-term and long-term basis

#### • MoU with BIRAC

For bringing synergy between various industry supporting organisations for "Commercialization of Indigenously Developed Technologies", an MoU was signed between Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC) and Technology Development Board (TDB) on 7<sup>th</sup> September, 2018 for creating and fostering a global and national ecosystem for Biomedical/ Biotechnological Innovations, Translation and Commercialization in a seamless manner.

#### The area and scope of co-operation include:

- BIRAC and TDB shall enable joint inter organizational mechanism for concerted efforts to meet the innovation and commercialization gap.
- Mutually agree upon the Biotechnology projects that can fall within the respective organizational scope for seamless evaluation and funding assistance considerations by establishment of a coactive governance structure.
- The Parties shall create a synergy to benefit from their respective organizational strength to mobilize effective funding and subtend technology readiness gap.
- The projects for cross reference will be decided on mutual understanding with respect to operative period of MoU; financial obligations and extent of cooperation.
- The Parties through this MoU have jointly agreed to share knowledge base, in-house processes and project inputs in furtherance to attainment of the united initiative.

#### e) Alliances

##### i) Global Innovation & Technology Alliance (GITA)-2011

As an outcome of the Prime Minister's Council on Trade & Industry, to support acceleration of India's industrial R&D efforts, The Global Innovation & Technology Alliance (GITA) was set up in 2011, as a PPP JV between the Confederation of Indian Industry (CII) and the Technology Development Board, Department of Science & Technology (DST), Government of India.

GITA is an innovative platform that maps technology gaps, evaluates technologies available across the globe and forges techno-strategic collaborative partnerships appropriate for the Indian economy. GITA connects industrial and institutional partners for effective matchmaking

and collaborative industrial R&D projects, facilitating funding for technology development/ acquisition/ customization / deployment. As on date, GITA is responsible for approximately US\$150 mn of industrial R&D funding on behalf of the Government of India and has catalysed approximately 2X private investment in R&D for every dollar invested by the Government.

Over the years, GITA has been successfully managing various national and bilateral Industrial R&D and technology acquisition projects under the partnership of various Government of India Ministries and Departments, such as the Department of Science & Technology (DST), Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY), the Department of Heavy Industry (DHI), the Defence Research & Development Organisation (DRDO), the Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) and the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MoMSME). GITA has also collaborated with multilateral bodies such as the European Commission for enhancing the innovation ecosystem.

Interventions have focused on sectors of national relevance to India's technological aspirations e.g., Affordable Healthcare, Clean Technologies including Energy and Transportation, Advanced Manufacturing, Capital Goods Sector, Defence & Aerospace, Information & Communication Technology (ICT), Electronic System Design & Manufacturing (ESDM), Water Technologies (including Water Purification, Desalination, Irrigation Technologies, Waste Water Treatment and Management), etc.

GITA also broadened and formalised its engagement with the Indian innovation ecosystem with the GITA Innovation Exchange (GIXC). The GIXC is a unique, virtual platform that endeavours to create credible connects for technological partnerships, technologies, IP services and finance for innovation, for actors across the innovation spectrum.

### ii) Millennium Alliance (MA)

The Millennium Alliance (MA) Program was launched in 2011 jointly by TDB, United States Agency for International Development (USAID) and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) as a platform to identify, test, and scale innovations which bring improvements at the Bottom of the Pyramid (BoP) level. This alliance was forged as an innovation partnership for global development focusing on important sectors including health, basic education, water & sanitation, food security/agriculture and clean energy to ensure that the benefits of innovation percolate to the BoP population. Later, the platform was joined by UK's DFID, ICCO Cooperation, ICICI Foundation for Inclusive Growth, World Bank Group and Facebook.

Each MA Partner brought along financial and knowledge resources with an end aim of supporting social enterprises that could bring about transformational change. The MA was an inclusive platform to leverage Indian creativity, expertise, and resources to identify and scale innovative solutions being developed and tested in India to address development challenges that benefited BoP populations across India and the world. The MA was a network to bring together various social innovators, philanthropy organizations, social venture capitalists, angel investors, donors, service providers and corporate foundations to stimulate and facilitate financial and other support to the innovators. A USD 25 million fund was set up for a period of 5 years of which TDB contributed ₹ 25.00 Crore (₹ 5 Crore per year). Under the program, innovators were provided with seed funding, grants, incubation, networking opportunities, business support, knowledge exchange and technical assistance which facilitates further access to equity, debt, and other capital.

The program completed its 5 rounds in the year 2018-19. Through these rounds, the program directly supported 124 innovative

projects with a funding support of ₹ 86.7 Crore. These projects have touched millions of lives, increasing farmer incomes, providing them access to early grade education, clean drinking water, energy for their homes, affordable & digital healthcare and sanitation facilities. The supported enterprises were able to leverage the grant given as a catalytic fund to raise external funds as well as develop partnerships for extensive and sustainable project implementation. The projects funded by MA are being implemented in 21 states in India. The funds are also supporting interventions in 11 countries. MA is the only program of its kind to support 22 Indian companies replicate and scale their innovations in Africa (Kenya, Rwanda, Uganda, Ethiopia, Burkina Faso and Malawi) and South Asia (Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka and Nepal). The MA has provided a huge impetus to the new genre of social entrepreneurs who are developing sustainable, scalable innovative models to ensure service delivery at the last mile. The program has played a significant role in entrepreneurship development in the social sector across the globe.

## f) Technology Day and Presentation of National Awards

### Technology Day

Every year National Technology Day is observed across India on May 11<sup>th</sup>. This day emphasizes the importance of science in day-to-day life and motivates students to adopt science as a career option. National Technology Day is being commemorated to celebrate the anniversary of first of the five tests of Operation Shakti (Pokhran-II) nuclear test which was held on 11<sup>th</sup> May, 1998 in Pokhran, Rajasthan. Apart from Pokhran nuclear test, on this day first indigenous aircraft Hansa-3 was test flown at Bangalore and India also conducted successful test firing of the Trishul missile on the same day. Considering all these achievements 11<sup>th</sup>, May was chosen to

be commemorated as National Technology Day.

This day urged the industry to build powerful partnerships with the national laboratories and to create knowledge networks with academic institutions for promoting research and development and gaining entry into global markets.

### National Award

To commemorate this day, TDB has instituted National Award. This award is conferred to various industries for successful commercialization of innovative Indigenous Technology. This Award was given for the first time on the occasion of the Technology Day on 11<sup>th</sup> May, 1999, to M/s Shantha Biotechnics Private Limited, Hyderabad for commercial production of "Recombinant DNA based Hepatitis - B vaccine" by the then Prime Minister of India, Hon'ble Shri Atal Bihari Vajpayee.

The award carried a cash prize of ₹ 10.00 Lakh and a trophy. In case a technology has been developed and commercialized by separate entities, both are eligible to get the award separately. In 2016, the quantum of the award was increased to ₹ 25.00 Lakh.

In August 2000, TDB introduced a cash award of ₹ 2.00 Lakh and a trophy to a SSI unit that has successfully commercialized a technology-based product. The first SSI award was given on 11<sup>th</sup> May, 2001. The number and quantum of the award was increased to three and ₹ 5.00 Lakh, respectively in the year 2011. In 2016, this award was renamed as 'MSME Award' and the quantum was increased to ₹ 15.00 Lakh.

During the year 2017-18, TDB introduced a new category of award of ₹ 15.00 Lakh and a trophy for Start-ups for promising new technology with potential for commercialization.

Since then following three categories of awards are given on 11<sup>th</sup> May 2018 onwards, during the Technology Day Celebrations:

- Two National Awards for Successful Commercialization of Indigenous Technology - Cash award of ₹ 25.00 Lakh and a trophy to an industrial concern which has successfully developed & commercialized an indigenous technology; in case the technology developer and commercializing organizations are different each one would be eligible for cash prize and trophy;
- Five National Award (MSME Awards) for successful commercialization of a technology-based product – Cash awards of ₹ 15.00 Lakh and a trophy each to a MSME that has successfully commercialized a product based on indigenous technology;
- Three Technology Start-up Awards – Cash award of ₹ 15.00 Lakh and a trophy for promising new technology with potential for commercialization.

### g) Issuance of “Call for Proposals”

The Board takes a pro-active approach and from time to time issues “Call for Proposal” in different areas of importance in order to familiarise local industry towards the intent of TDB support innovation –driven technology focused projects in various strategic areas as per the policies and the initiatives by Government of India like “Make in India”, “Startup India” and “Atmanirbhar Bharat” etc.

### h) Dispute Resolution Committee (DRC)

Since inception of TDB, many cases have been declared stressed either due to technology failure or commercialization failure. Owing to these NPAs/ Stressed cases, pre-litigation and litigation cases, the Board initiated a mechanism for addressing such cases by constituting a “Dispute

Resolution Committee (DRC)” in late 2015.

The objective of DRC is to provide companies a platform to resolve issues related to payment of TDB dues. However, DRC no where interferes with the legal proceedings already initiated by TDB. The recommendations of DRC are placed for approval before the Board. Through this process, issues with many companies have been resolved and recoveries made.

### i) Online Submission of Project Proposals

TDB started an initiative towards transparent and efficient working procedure by facilitating “Online Submission of Project Proposals” through its “Project Management System(PMS)” @ <http://www.e-techcom.tdb.gov.in/> during the year 2017-18.

### j) Exhibitions/Seminars

To create awareness in the industry, entrepreneurs and R&D institutions about the available financial support from TDB, various activities during the year 2019-20 were undertaken such as interactive meetings/participation in exhibitions in collaboration with other organisations.

### k) Creation of Social Media Platform

In order to get transparency in functioning and getting more connectivity and also considering the importance of Social Media platforms in present scenario, TDB felt the need to have its own Social Media platforms and created its official pages as follows:

Face book: [www.facebook.com/tdbgoi](http://www.facebook.com/tdbgoi)  
LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/technology-development-board/>  
Twitter: <https://twitter.com/tdbgoi>



# **TDB-Year at a Glance**

# TDB Year at a Glance

## TDB –Year at a Glance

In the year 2019-20, TDB entered into five agreements to provide financial assistance to various industrial concerns. Through these agreements, TDB committed ₹ 29.87 Crore out of total project outlay of ₹ 70.32 Crore covering various sectors such as Agriculture, Engineering, Energy and Waste utilization, Health & Medical.

## Applications Received in 2019-20

TDB received twenty three applications during 2019-20 for financial assistance from various industrial concerns with total project cost of ₹ 391.80 Crore and TDB's assistance of ₹ 116.67 Crore.

The State-wise distribution of these twenty three applications are as under:

₹ In Crore

S.No	State/Union Territory	Number of Applications	Estimated Total Cost	Assistance sought from TDB
1	Andhra Pradesh / Telangana	5	161.18	26.65
2	Karnataka	5	68.83	29.35
3	Maharashtra	1	2.27	2.27
4	Tamilnadu	3	24.13	6.50
5	Delhi	1	4.97	2.48
6	Uttar Pradesh	4	49.56	20.61
7	Haryana	3	77.26	27.00
8	Chandigarh	1	3.60	1.80
	<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>391.80</b>	<b>116.66</b>

The sector wise details of receipt of applications are as under:

₹ In Crore

S. No	Sector	Number of Applications	Estimated Total Cost	Assistance sought from TDB
1	Health & Medical	6	176.20	33.02
2	Engineering	5	77.09	28.00
3	Information Technology	5	44.31	21.07
4	Agriculture	2	3.50	1.50
5	Road Transport	2	24.28	11.27
6	Energy & Waste Utilization	2	40.18	11.80
7	Defence and Civil Aviation	1	26.24	10.00
	<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>391.80</b>	<b>116.66</b>

Applications were received from Private Ltd. and Public Ltd. Companies as given below:

₹ In Crore

S.No		Number of Applications	Estimated Total Cost	Assistance sought from TDB
1	Private Limited Company	23	391.80	116.66
2	Public Limited Company	-	-	-
3	Other	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>391.80</b>	<b>116.66</b>

## Agreements Signed during FY 2019-20

During the year, TDB signed five new agreements for financial assistance to support the following project for development and commercialization of innovative technologies.

S. No.	Name of the Company	Name of the Project	Sector
1.	M/s iMinBit Tech India Pvt. Ltd., Haryana	"Manufacturing and Commercialization of Water Saving RO based Purification Technology"	Energy & Waste utilization
2.	M/s Anarobic Energy Pvt. Ltd., Bijnor	"Development & Commercialization of Bio CNG from Sewage Based Biogas Plant, at Sewage Treatment Plant Jagjeetpur, Haridwar"	Energy & Waste utilization
3.	M/s Agatsa Software Pvt Ltd, Noida	"Sanket Life"	Health & Medical
4.	M/s Arpan Nutrition Private Limited., New Delhi	"Commercialization of Zero Erucic Mustard Technology for Human Health & Nutrition"	Agriculture
5.	M/s Yashraj Biotechnology Limited, Mumbai	"Development & commercialization of products and services derived through Pluripotent stem cell technology for disease modelling biomarker discovery and drug toxicity testing"	Health & Medical

## Disbursement

TDB disbursed an amount of ₹ 128.74 Crore towards on-going & new Projects and other Schemes in FY 2019-20. This included ₹ 128.37 Crore as Loan; ₹ 0.11 Crore as Grant and ₹ 0.26 Crore to VCF for investment.

## Projects Completed

The following companies supported by TDB declared their project completed during the FY 2019-20:

S. No.	Name of the Company	Name of the Project	Sector
1.	M/s Grasim Industries Ltd., Mumbai	Birla Excel Solvent Spun Cellulosic Fibre Plant	Textile
2.	M/s Surewaves Mediatech Pvt. Ltd., Bangalore	Development and commercialization of SKyNet Programmatic TV Platform	IT
3.	M/s Kanbiosys Pvt. Ltd., Pune	Development and commercialization of straw utilization technology: In-situ Accelerated and Sustainable Rice Straw Decomposition (ASRSD)	Agriculture

4.	M/s BitChem Asphalt Technologies Ltd, Guwahati	Cold Mix Technology in Road Construction & Maintenance	Chemical
5.	M/s Incredible Devices Private Ltd, Chandigarh	Development and commercialization of Catheter Reprocessing system	Health & Medical
6.	M/s Iatome Electric India Pvt. Ltd., Coimbatore	Development and Commercialization of Portable X-ray machine	Health & Medical
7.	M/s VEM Technologies Pvt. Ltd., Hyderabad	Development and Commercialization of RF Seekers	Engineering

### Settlement of Repayment of Loan

During the year, following companies financed by TDB repaid their Loan and settled loan account as per the agreement:-

- M/s AquAgri Processing Pvt. Ltd., New Delhi
- M/s Ampere Vehicles Pvt. Ltd., Coimbatore
- M/s Yashraj Biotechnology Ltd., Navi Mumbai
- M/s Silvan Innovation Labs Pvt. Ltd., Bangalore
- M/s Incredible Devices Private Limited, Chandigarh
- M/s Zen Technologies Limited, Hyderabad
- M/s KVB Agro Farms Private Limited, Kashmir (J&K)
- M/s Vayayva Labs Pvt. Ltd., Belgaum
- M/s Sankhya Technologies Private Limited, Chennai
- M/s Sudershan Biotech Limited, Hyderabad

### Technology Day

The following winners have been awarded with the National Award-2019 under following three categories:

Award Category	Awardee (Company Name)
<b>National Award for successful commercialization of Indigenous technology</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Company: M/s Reliance Industries Limited, Mumbai, along with; (Technology Provider - CSIR - Indian Institute of Petroleum, Dehradun for – "Production of Benzene lean Gasoline by recovery of high purity benzene from unprocessed cracked gasoline fraction containing peroxides.")</li> </ul>
<b>The National Award (MSME Awards) for successful commercialization of technology-based product based on indigenous technology</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M/s Nimra Cerglass Technics Private Limited, Hyderabad for "Development and supply of Fused Silica Radomes".</li> <li>• M/s Tejas Networks Ltd, Bengaluru – for "Tejas GPON product family (TJ1400 OLT and TJ2100N ONT)".</li> <li>• M/s Metal Power Analytical (India) Private Limited, Mumbai for "Optical Emission Spectrometers (OES) and technology".</li> </ul>

Applications were received from Private Ltd. and Public Ltd. Companies as given below:

₹ In Crore

S.No		Number of Applications	Estimated Total Cost	Assistance sought from TDB
1	Private Limited Company	23	391.80	116.66
2	Public Limited Company	-	-	-
3	Other	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>391.80</b>	<b>116.66</b>

## Agreements Signed during FY 2019-20

During the year, TDB signed five new agreements for financial assistance to support the following project for development and commercialization of innovative technologies.

S. No.	Name of the Company	Name of the Project	Sector
1.	M/s iMinBit Tech India Pvt. Ltd., Haryana	"Manufacturing and Commercialization of Water Saving RO based Purification Technology"	Energy & Waste utilization
2.	M/s Anarobic Energy Pvt. Ltd., Bijnor	"Development & Commercialization of Bio CNG from Sewage Based Biogas Plant, at Sewage Treatment Plant Jagjeetpur, Haridwar"	Energy & Waste utilization
3.	M/s Agatsa Software Pvt Ltd, Noida	"Sanket Life"	Health & Medical
4.	M/s Arpan Nutrition Private Limited., New Delhi	"Commercialization of Zero Erucic Mustard Technology for Human Health & Nutrition"	Agriculture
5.	M/s Yashraj Biotechnology Limited, Mumbai	"Development & commercialization of products and services derived through Pluripotent stem cell technology for disease modelling biomarker discovery and drug toxicity testing"	Health & Medical

## Disbursement

TDB disbursed an amount of ₹ 128.74 Crore towards on-going & new Projects and other Schemes in FY 2019-20. This included ₹ 128.37 Crore as Loan; ₹ 0.11 Crore as Grant and ₹ 0.26 Crore to VCF for investment.

## Projects Completed

The following companies supported by TDB declared their project completed during the FY 2019-20:

S. No.	Name of the Company	Name of the Project	Sector
1.	M/s Grasim Industries Ltd., Mumbai	Birla Excel Solvent Spun Cellulosic Fibre Plant	Textile
2.	M/s Surewaves Mediatech Pvt. Ltd., Bangalore	Development and commercialization of SKyNet Programmatic TV Platform	IT
3.	M/s Kanbiosys Pvt. Ltd., Pune	Development and commercialization of straw utilization technology: In-situ Accelerated and Sustainable Rice Straw Decomposition (ASRSD)	Agriculture

4.	M/s BitChem Asphalt Technologies Ltd, Guwahati	Cold Mix Technology in Road Construction & Maintenance	Chemical
5.	M/s Incredible Devices Private Ltd, Chandigarh	Development and commercialization of Catheter Reprocessing system	Health & Medical
6.	M/s latome Electric India Pvt. Ltd., Coimbatore	Development and Commercialization of Portable X-ray machine	Health & Medical
7.	M/s VEM Technologies Pvt. Ltd., Hyderabad	Development and Commercialization of RF Seekers	Engineering

### Settlement of Repayment of Loan

During the year, following companies financed by TDB repaid their Loan and settled loan account as per the agreement:-

- M/s AquAgri Processing Pvt. Ltd., New Delhi
- M/s Ampere Vehicles Pvt. Ltd., Coimbatore
- M/s Yashraj Biotechnology Ltd., Navi Mumbai
- M/s Silvan Innovation Labs Pvt. Ltd., Bangalore
- M/s Incredible Devices Private Limited, Chandigarh
- M/s Zen Technologies Limited, Hyderabad
- M/s KVB Agro Farms Private Limited, Kashmir (J&K)
- M/s Vayayva Labs Pvt. Ltd., Belgaum
- M/s Sankhya Technologies Private Limited, Chennai
- M/s Sudershan Biotech Limited, Hyderabad

### Technology Day

The following winners have been awarded with the National Award-2019 under following three categories:

Award Category	Awardee (Company Name)
<b>National Award for successful commercialization of Indigenous technology</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Company: M/s Reliance Industries Limited, Mumbai, along with; (Technology Provider - CSIR - Indian Institute of Petroleum, Dehradun for – “Production of Benzene lean Gasoline by recovery of high purity benzene from unprocessed cracked gasoline fraction containing peroxides.”)</li> </ul>
<b>The National Award (MSME Awards) for successful commercialization of technology-based product based on indigenous technology</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M/s Nimra Cerglass Technics Private Limited, Hyderabad for “Development and supply of Fused Silica Radomes”.</li> <li>• M/s Tejas Networks Ltd, Bengaluru – for “Tejas GPON product family (TJ1400 OLT and TJ2100N ONT)”.</li> <li>• M/s Metal Power Analytical (India) Private Limited, Mumbai for “Optical Emission Spectrometers (OES) and technology”.</li> </ul>

Applications were received from Private Ltd. and Public Ltd. Companies as given below:

₹ In Crore

S.No	Number of Applications	Estimated Total Cost	Assistance sought from TDB
1	Private Limited Company	23	391.80
2	Public Limited Company	-	-
3	Other	-	-
	<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>391.80</b>
			<b>116.66</b>

## Agreements Signed during FY 2019-20

During the year, TDB signed five new agreements for financial assistance to support the following project for development and commercialization of innovative technologies.

S. No.	Name of the Company	Name of the Project	Sector
1.	M/s iMinBit Tech India Pvt. Ltd., Haryana	"Manufacturing and Commercialization of Water Saving RO based Purification Technology"	Energy & Waste utilization
2.	M/s Anarobic Energy Pvt. Ltd., Bijnor	"Development & Commercialization of Bio CNG from Sewage Based Biogas Plant, at Sewage Treatment Plant Jagjeetpur, Haridwar"	Energy & Waste utilization
3.	M/s Agatsa Software Pvt Ltd, Noida	"Sanket Life"	Health & Medical
4.	M/s Arpan Nutrition Private Limited., New Delhi	"Commercialization of Zero Erucic Mustard Technology for Human Health & Nutrition"	Agriculture
5.	M/s Yashraj Biotechnology Limited, Mumbai	"Development & commercialization of products and services derived through Pluripotent stem cell technology for disease modelling biomarker discovery and drug toxicity testing"	Health & Medical

## Disbursement

TDB disbursed an amount of ₹ 128.74 Crore towards on-going & new Projects and other Schemes in FY 2019-20. This included ₹ 128.37 Crore as Loan; ₹ 0.11 Crore as Grant and ₹ 0.26 Crore to VCF for investment.

## Projects Completed

The following companies supported by TDB declared their project completed during the FY 2019-20:

S. No.	Name of the Company	Name of the Project	Sector
1.	M/s Grasim Industries Ltd., Mumbai	Birla Excel Solvent Spun Cellulosic Fibre Plant	Textile
2.	M/s Surewaves Mediatech Pvt. Ltd., Bangalore	Development and commercialization of SKyNet Programmatic TV Platform	IT
3.	M/s Kanbiosys Pvt. Ltd., Pune	Development and commercialization of straw utilization technology: In-situ Accelerated and Sustainable Rice Straw Decomposition (ASRSD)	Agriculture

4.	M/s BitChem Asphalt Technologies Ltd, Guwahati	Cold Mix Technology in Road Construction & Maintenance	Chemical
5.	M/s Incredible Devices Private Ltd, Chandigarh	Development and commercialization of Catheter Reprocessing system	Health & Medical
6.	M/s Iatome Electric India Pvt. Ltd., Coimbatore	Development and Commercialization of Portable X-ray machine	Health & Medical
7.	M/s VEM Technologies Pvt. Ltd., Hyderabad	Development and Commercialization of RF Seekers	Engineering

### Settlement of Repayment of Loan

During the year, following companies financed by TDB repaid their Loan and settled loan account as per the agreement:-

- M/s AquAgri Processing Pvt. Ltd., New Delhi
- M/s Ampere Vehicles Pvt. Ltd., Coimbatore
- M/s Yashraj Biotechnology Ltd., Navi Mumbai
- M/s Silvan Innovation Labs Pvt. Ltd., Bangalore
- M/s Incredible Devices Private Limited, Chandigarh
- M/s Zen Technologies Limited, Hyderabad
- M/s KVB Agro Farms Private Limited, Kashmir (J&K)
- M/s Vayayva Labs Pvt. Ltd., Belgaum
- M/s Sankhya Technologies Private Limited, Chennai
- M/s Sudershan Biotech Limited, Hyderabad

### Technology Day

The following winners have been awarded with the National Award-2019 under following three categories:

Award Category	Awardee (Company Name)
<b>National Award for successful commercialization of Indigenous technology</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Company: M/s Reliance Industries Limited, Mumbai, along with; (Technology Provider - CSIR - Indian Institute of Petroleum, Dehradun for – "Production of Benzene lean Gasoline by recovery of high purity benzene from unprocessed cracked gasoline fraction containing peroxides.")</li> </ul>
<b>The National Award (MSME Awards) for successful commercialization of technology-based product based on indigenous technology</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M/s Nimra Cerglass Technics Private Limited, Hyderabad for "Development and supply of Fused Silica Radomes".</li> <li>• M/s Tejas Networks Ltd, Bengaluru – for "Tejas GPON product family (TJ1400 OLT and TJ2100N ONT)".</li> <li>• M/s Metal Power Analytical (India) Private Limited, Mumbai for "Optical Emission Spectrometers (OES) and technology".</li> </ul>

Applications were received from Private Ltd. and Public Ltd. Companies as given below:

₹ In Crore

S.No	Number of Applications	Estimated Total Cost	Assistance sought from TDB
1	Private Limited Company	23	391.80
2	Public Limited Company	-	-
3	Other	-	-
	<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>391.80</b>
			<b>116.66</b>

## Agreements Signed during FY 2019-20

During the year, TDB signed five new agreements for financial assistance to support the following project for development and commercialization of innovative technologies.

S. No.	Name of the Company	Name of the Project	Sector
1.	M/s iMinBit Tech India Pvt. Ltd., Haryana	"Manufacturing and Commercialization of Water Saving RO based Purification Technology"	Energy & Waste utilization
2.	M/s Anarobic Energy Pvt. Ltd., Bijnor	"Development & Commercialization of Bio CNG from Sewage Based Biogas Plant, at Sewage Treatment Plant Jagjeetpur, Haridwar"	Energy & Waste utilization
3.	M/s Agatsa Software Pvt Ltd, Noida	"Sanket Life"	Health & Medical
4.	M/s Arpan Nutrition Private Limited., New Delhi	"Commercialization of Zero Erucic Mustard Technology for Human Health & Nutrition"	Agriculture
5.	M/s Yashraj Biotechnology Limited, Mumbai	"Development & commercialization of products and services derived through Pluripotent stem cell technology for disease modelling biomarker discovery and drug toxicity testing"	Health & Medical

## Disbursement

TDB disbursed an amount of ₹ 128.74 Crore towards on-going & new Projects and other Schemes in FY 2019-20. This included ₹ 128.37 Crore as Loan; ₹ 0.11 Crore as Grant and ₹ 0.26 Crore to VCF for investment.

## Projects Completed

The following companies supported by TDB declared their project completed during the FY 2019-20:

S. No.	Name of the Company	Name of the Project	Sector
1.	M/s Grasim Industries Ltd., Mumbai	Birla Excel Solvent Spun Cellulosic Fibre Plant	Textile
2.	M/s Surewaves Mediatech Pvt. Ltd., Bangalore	Development and commercialization of SKyNet Programmatic TV Platform	IT
3.	M/s Kanbiosys Pvt. Ltd., Pune	Development and commercialization of straw utilization technology; In-situ Accelerated and Sustainable Rice Straw Decomposition (ASRSD)	Agriculture

## TDB Year at a Glance

4.	M/s BitChem Asphalt Technologies Ltd, Guwahati	Cold Mix Technology in Road Construction & Maintenance	Chemical
5.	M/s Incredible Devices Private Ltd, Chandigarh	Development and commercialization of Catheter Reprocessing system	Health & Medical
6.	M/s Iatome Electric India Pvt. Ltd., Coimbatore	Development and Commercialization of Portable X-ray machine	Health & Medical
7.	M/s VEM Technologies Pvt. Ltd., Hyderabad	Development and Commercialization of RF Seekers	Engineering

## Settlement of Repayment of Loan

During the year, following companies financed by TDB repaid their Loan and settled loan account as per the agreement:-

- M/s AquAgri Processing Pvt. Ltd., New Delhi
- M/s Ampere Vehicles Pvt. Ltd., Coimbatore
- M/s Yashraj Biotechnology Ltd., Navi Mumbai
- M/s Silvan Innovation Labs Pvt. Ltd., Bangalore
- M/s Incredible Devices Private Limited, Chandigarh
- M/s Zen Technologies Limited, Hyderabad
- M/s KVB Agro Farms Private Limited, Kashmir (J&K)
- M/s Vayayva Labs Pvt. Ltd., Belgaum
- M/s Sankhya Technologies Private Limited, Chennai
- M/s Sudershan Biotech Limited, Hyderabad

## Technology Day

The following winners have been awarded with the National Award-2019 under following three categories:

Award Category	Awardee (Company Name)
<b>National Award for successful commercialization of Indigenous technology</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Company: M/s Reliance Industries Limited, Mumbai, along with; (Technology Provider - CSIR - Indian Institute of Petroleum, Dehradun for – “Production of Benzene lean Gasoline by recovery of high purity benzene from unprocessed cracked gasoline fraction containing peroxides.”)</li> </ul>
<b>The National Award (MSME Awards) for successful commercialization of technology-based product based on indigenous technology</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M/s Nimra Cerglass Technics Private Limited, Hyderabad for “Development and supply of Fused Silica Radomes”.</li> <li>• M/s Tejas Networks Ltd, Bengaluru – for “Tejas GPON product family (TJ1400 OLT and TJ2100N ONT)”.</li> <li>• M/s Metal Power Analytical (India) Private Limited, Mumbai for “Optical Emission Spectrometers (OES) and technology”.</li> </ul>

<b>The National Award for technology Start-ups for promising new-technology with potential for commercialization</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M/s Pratimesh Lab Pvt Ltd, Bengaluru, for "Home testing solution for blood cell counting".</li> <li>• M/s Coeo Labs Pvt Ltd, Bengaluru, for "Saan-a neonatal breathing support device".</li> <li>• M/s Tvasta Manufacturing Solutions Pvt Ltd, Bengaluru – "3D Printers for Automation of Construction process".</li> <li>• M/s Inficold India Pvt Ltd, Noida for "Retrofittable Thermal Storage for Enabling Farm / Mandi Level Solar Cold Storage".</li> <li>• M/s Innovation Imaging Technologies Pvt Ltd, Bengaluru for "CATHLAB for Medical Imaging-Optimized Radiation".</li> </ul>
--	--

However, due to Lok Sabha elections in Delhi on 12<sup>th</sup> May, 2019, the award ceremony for presentation of National Awards could not take place during this year on the Technology Day.

### Participation in Venture Capital Funds (VCFs)

This year an amount of ₹ 8.48 Cr is received towards redemption. The details of VCF's Managers, fund size and TDB's contribution are given below:

₹ In Crore

S. No	Fund Name	Investment Manager	Total Fund size	TDB Commitment	Receipts during FY 2019-20 towards redemption
1.	Ascent India Fund	UTI Venture Funds Management Company pvt ltd, Bangalore	739.25	75.00	1.46
2.	Biotechnology Venture Fund(BVF)	APIDC Venture Capital ltd, Hyderabad	155.00	30.00	2.50
3.	Ventureast Tenet Fund II	Ventureast Fund Advisors (India) Pvt ltd, Chennai	54.45	15.00	--
4.	SME Technology Venture Fund	Gujarat Venture Finance ltd (GVFL),Ahmadabad	89.32	15.00	--
5.	SME Tech Fund RVCF II	Rajasthan Asset Management Company Pvt Ltd, Rajasthan	150.00	15.00	0.34
6.	India Opportunities Fund (IOF)	SIDBI Venture Capital ltd, Fund	421.30	25.00	1.44
7.	SEAF India Agribusiness Fund	SEAF India Investment Advisors Pvt ltd, Mumbai	106.25	25.00	1.87
8.	Multi Sector Seed Capital Fund	Blume Ventures Advisors Pvt ltd, Mumbai	100.00	25.00	0.77
9.	Ivycap ventures Trust Fund I	Ivycap Ventures Advisors Pvt ltd, Mumbai	238.20	25.00	0.10
10.	Indian Fund for sustainable Energy	CII, IIM Ahmadabad	125.00	10.00	--

## **Innovative Ventures and Technologies for Development (INVENT) Programme**

TDB in partnership with Department for International Development (DFID), UK initiated the Innovative Ventures and Technologies for Development (INVENT) Programme in the FY 2015-16. The program was designed to create a platform to support inclusive innovation solutions, both technological and process oriented, that have a positive social and economic impact on people in the lower income segments, also known as the Bottom of the Pyramid (BoP).

The INVENT programme is basically about Inclusive Innovations and will address challenges and barriers across the inclusive innovation lifecycle, for the benefit of up to 1 million poor people at the bottom of the economic pyramid in the 8 low income states of India (LIS) (UP, MP, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Rajasthan, Orissa and West Bengal).

The financial outlay for this programme is £5 million in the form of technical assistance for the period of 05 years with support of Department for International Development (DFID), UK. The programme has a mandate to develop at least 50 investment ready business and incubate 160 entrepreneurs in 08 LIS over the period of the program. Till date and since its inception in 2016, the program has incubated 150 enterprises, out of which 48 companies have raised follow-on funding to the tune of INR ₹ 118 Crores. Follow on funding partners include, so far, are from both government and non-government bodies like Intellectap, Omnivore, AgFunder, Zomato, TATA Trust, Info Edge, Ankur Capital, Gray Matters Capital, Google, Yes Bank, HDFC, SBI and Angel Investors.

It is to be noted that of the 150 incubated enterprises 33.3 % belong to Agri- and allied business, 20.2% belong to Healthcare, 14.7%

belong to Education, 5.4% belong to Energy sector, 19.4% belong to Livelihood & Skill Development. Also, of the 150 enterprises, IIT Kanpur has incubated 36 enterprises, IIM CIP has 40 enterprises, KIIT TBI has 34 and Startup Oasis has incubated another 33. In terms of impact created on the ground, it is estimated that around 6.2 lakhs lives have been touched with 5000 direct & indirect employment generated through these INVENT companies across LIS.

## **Call for Proposal- "Fighting COVID-19"**

TDB has issued a call for proposals inviting applications from Indian companies and enterprises for technologically innovative solutions towards "Fighting COVID-19" on 20.03.2020. The aim of this call is to strengthen the nation's core capacities in surveillance, laboratory support, infection prevention and control, logistics, risk communication & in particular, the preparedness in terms of isolation and ventilator management of critically ill patients for containing/ preventing the spread of COVID-19. Such health care related technologies were in short supply world over, due to sudden spread of this pandemic globally. TDB has therefore invited proposals for development of solutions under the following categories:-

- Low-cost masks which can capture virus from the air and absorb respiratory droplets
- Cost-effective Thermal Scanning
- Large area sanitization and sterilization (including electrostatic spray and Ultra Violet treatment for various available surfaces like glass, ceramic, wood, textile, etc.)
- Bioinformatics and Surveillance
- Rapid and Accurate Diagnosis kit (paper-based and other point of care devices)
- AI and IoT based solution for contact-less entry

- Oxygenators and ventilators (Low cost and portable)
- Or any other related technology

The Indian industry and the start-up ecosystem responded enthusiastically to the invitation by the Technology Development Board (TDB). The last date of submission for proposals was March 30, 2020.

### Social Media Outreach

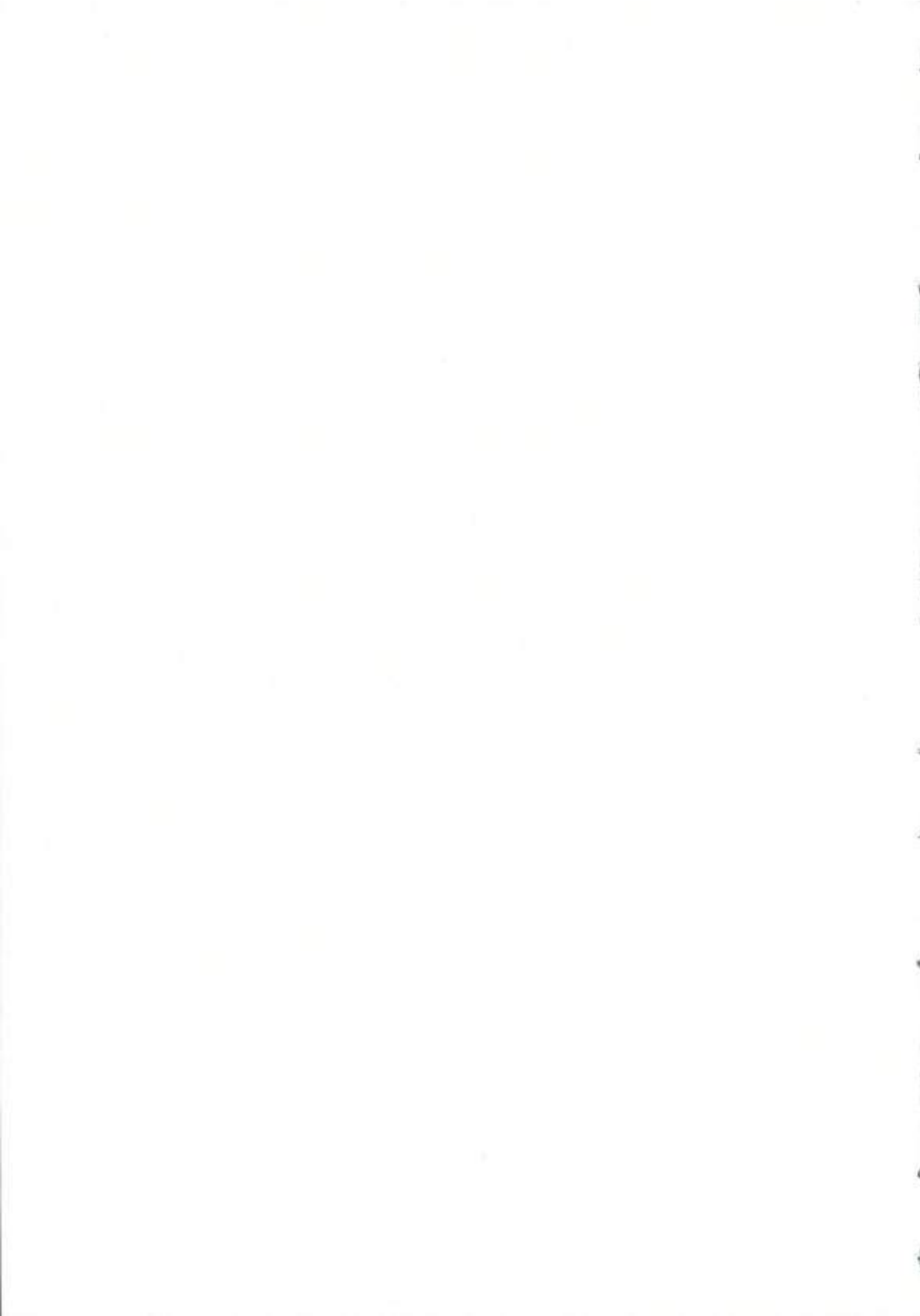
Technology Development Board is strived to stay updated on all the social media platforms trending across the globe. In order

to have broader outreach and networking via Facebook, LinkedIn, Twitter, TDB created its Instagram profile this year. This will enable TDB to connect with companies, academia, industrialists, and other related organisations for exploring opportunities in the field of scientific innovations.

**Instagram:** [www.instagram.com/technologydevelopmentboard/](https://www.instagram.com/technologydevelopmentboard/)

### Acknowledgement

TDB is grateful to all the Board Members for their time, effort, guidance and contribution.





**Agreements Signed**

## Manufacturing and Commercialization of Water Saving RO based Purification Technology

M/s iMinBit Tech India Pvt. Ltd., Haryana

Sector: Energy & Waste utilization



Technology Development Board (TDB) has entered into an agreement on 24<sup>th</sup> June, 2019 with M/s iMinBit Tech India Pvt. Ltd., Haryana for implementation of their project title "Manufacturing and Commercialization of Water Saving RO based Purification Technology" for Loan assistance of ₹ 148.00 lakh against the total project cost of ₹ 341.60 lakh. As per the Agreement, the project would be completed on before 30<sup>th</sup> June, 2020.

The company is an IIT BHU alumnus initiative Start-up recognised by Start-up India and Stand up India and seed supported by Malaviya Centre for Innovation, Incubation and Entrepreneurship (MCIE TBI, IIT BHU, Varanasi). It was also supported and funded by the Invent Program, SIIC, IIT Kanpur.

### About the Project and Product

The Company intends to build Reverse Osmosis (RO) based water purifiers which will be saving water and is cost and energy efficient. Their innovative technology gives around 70% recovery of product water. Company has developed a process and different types of filters which can control the parameters and stabilise the process in an economical way. The execution and stabilisation of such pressurised system is the key innovation of this water filtration technology.



The competitive advantage is that the technology has reduced the water wastage and energy consumption by 50%. The brand name of their product is "Aquivio".

Aquivio water purifier comes in two variants; 100 LPH and 50 LPH. The main target groups for this product are educational institutes, organizations, offices etc.

Project Cost  
₹ 341.60 lakh  
Loan Assistance  
₹ 148.00 lakh



## Development & Commercialization of Bio CNG from Sewage Based Biogas Plant, at Sewage Treatment Plant Jagjeetpur, Haridwar

M/s Anarobic Energy Pvt. Ltd., Bijnor

Sector: Energy & Waste utilization



Technology Development Board (TDB) has entered into an agreement on 8<sup>th</sup> July, 2019 with M/s Anarobic Energy Pvt. Ltd., Bijnor for implementation of their project title "Development & Commercialization of Bio CNG from Sewage Based Biogas Plant, at Sewage Treatment Plant Jagjeetpur, Haridwar" for Loan assistance of ₹ 215.00 lakh against the total project cost of ₹ 431.70 lakh. As per the Agreement, the project would be completed on before 30<sup>th</sup> June, 2020

It is a newly initiated start-up company certified by Department of Industrial Policy & Planning (DIPP).

### About the Project and Product

In this project, the company wants to establish its first biogas plant to produce bio CNG at Haridwar based on sewage sludge available at sewage treatment plant at Jagjeetpur, Haridwar. The company proposes to generate biogas, refine the biogas to produce bio CNG and generate revenue by sale of bio CNG. Generation of bio CNG requires two distinct processes i) Generation of biogas from substrate via anaerobic digestion and ii) Purification / up-gradation of biogas to bio CNG. The required technology is being sourced from Atmos Power Pvt. Ltd., Ahmedabad and Indian Oil Research & Development Centre, Faridabad.



The company will earn revenue through the production of bio CNG for the use of vehicle fuel and for that they are setting up a bio CNG filling station. Another component of the revenue generation is the production of Organic fertilizer from the digester effluent and for that tying up with leading fertilizer companies viz. IFFCO & KRIBHCO.

Project Cost  
₹ 431.70 lakh  
Loan Assistance  
₹ 215.00 lakh



## Sanket Life

M/s Agatsa Software Pvt Ltd, Noida

Sector: Health & Medical

Technology Development Board (TDB) has entered into an agreement on 20<sup>th</sup> September, 2019 with M/s Agatsa Software Pvt Ltd, Noida for implementation of their project title "Sanket Life" for Loan assistance of ₹ 391.00 lakh against the total project cost of ₹ 1148.00 lakh. As per the Agreement, the project would be completed on 31<sup>st</sup> March 2021

M/s Agatsa Software Pvt Ltd is a start-up company established in March 2010.

### About the Project and Product

The company has indigenously designed and developed an innovative match-box size device called "Sanket Life" that can perform sequential 12 LEAD ECG test. The device can be connected to a smart phone via Bluetooth and the ECG is displayed on the mobile's screen through the company's in-house developed mobile application. The generated ECG report can also be sent to a cardiologist for review, through Agatsa's integrated Cloud platform. It is a self-use device and does not require patient cables or gels. Sanket Life uses Agatsa's indigenously developed software technology to offer Cloud and SDK based integration for Android / iOS platform. The prototype "Sanket Life 1.0" was developed at the Department of Science & Technology incubator at JSSATE, Noida



during 2015-2016. Since then, the company is extensively working on their R & D and business expansion to commercialize their product with improved features. In the project submitted to TDB, company plans to commercialize "Sanket Life 2.0" and expand their manufacturing capabilities from existing 200 units/month to 10000 units/month, by introducing automation in the manufacturing processes.

Project Cost  
₹ **1148.00** lakh  
Loan Assistance  
₹ **391.00** lakh



## Commercialization of Zero Erucic Mustard Technology for Human Health & Nutrition

M/s Arpan Nutrition Private Limited., New Delhi

Sector: Agriculture



Technology Development Board (TDB) has entered into an agreement on 4<sup>th</sup> October, 2019 with M/s Arpan Nutrition Private Limited., New Delhi for implementation of their project title "Commercialization of Zero Erucic Mustard Technology for Human Health & Nutrition" for Loan assistance of ₹ 233.00 lakh against the total project cost of ₹ 495.00 lakh. As per the Agreement, the project would be completed on before 31<sup>st</sup> July, 2021.

The company is an initiative by agriculture entrepreneurs who are committed to advance innovation in agriculture & food for nutritional security and supported by Division of Genetics & incubated by ZTM-BPD of ICAR-Indian Agricultural Research Institute (IARI), New Delhi. It was also supported by the Ministry of Micro Small & Medium Enterprises (MSME).

### About the Project and Product

The company will develop the identify preserved production system, promote contract farming and establish integrated "seed to oil" supply chain for the production of canola quality mustard oil while retaining its pungency—offering mustard oil better than imported canola oil. ZEM mustard oil will contain double in Oleic, lenoleic omega-6 and linolenic omega-3 fatty acids – the essential fatty acids (EFA) for human health. ZEM mustard



oil has the best combination of other desirable fatty acids that offer significantly higher health benefits of MUFA & PUFA in maintaining the balance of LDL and HDL in human cholesterol. Notably, it substantially reduces the probability of diseases like myocardial fibrosis in adults and lipidosis in children, thereby ensuring human health and prolong life.

Project Cost  
₹ 495.00 lakh

Loan Assistance  
₹ 233.00 lakh



## Development & commercialization of products and services derived through Pluripotent stem cell technology for disease modelling biomarker discovery and drug toxicity testing

M/s Yashraj Biotechnology Limited, Mumbai

Sector: Health & Medical



Technology Development Board (TDB) has entered into an agreement on 26<sup>th</sup> February, 2020 with M/s Yashraj Biotechnology Limited, Mumbai for implementation of their project title "Development & commercialization of products and services derived through Pluripotent stem cell technology for disease modelling biomarker discovery and drug toxicity testing" for Loan assistance of ₹ 2000.00 lakh against the total project cost of ₹ 4615.36 lakh. As per the Agreement, the project would be completed on before 31<sup>st</sup> March 2021.

M/s Yashraj Biotechnology Limited is working towards the manufacturing of Antigens & Proteins having diagnostic importance from native source.

### About the Project and Product

The company, with this assistance, aims to establish infrastructure and facilities for the development of stem cells, derivatives of stem cells, purified protein antigens and growth factors. These will be used for preclinical drug discovery, diagnostics and therapeutics. This will lead to the development of disease and lineage specific cellular derivatives from cancer tissue, somatic or stem cells of patients from India. These will be used for the in vitro disease modelling of cancer, which will bring in vast information regarding progression of this disease in the Indian population.



In addition, the company will also develop a bio-bank of clinical samples from patients with breast cancer, which is the most prevalent cause of morbidity and mortality in Indian women and across globe. Further, the facilities will be used for high-through put drug screening and toxicological testing as well. The drug screening will lead to identification of new and alternate drugs for cancer. The toxicological testing will help in predicting therapeutic response and side-effect of a given drug in patients. This information will help in making it possible to personalize treatment for each patient based on the likely course of their disease.

**Project Cost**  
**₹ 4615.36 lakh**

**Loan Assistance**  
**₹ 2000.00 lakh**





**Projects Completed**

## Birla Excel Solvent Spun Cellulosic Fibre Plant

M/s Grasim Industries Ltd., Mumbai

Textile

M/s Grasim Industries Limited has set up a production line with a capacity of 50 TPD for solvent spun 3rd generation Cellulosic Fibre Lyocell, at Birla Cellulosic campus, Kharach, District Bharuch, Gujrat for commercialization under the Brand name 'Birla Excel' based on the technology developed in-house.

Birla Excel is the third generation fibre lyocell best suited for blending with cotton as it enhances performance of cotton fibre by adding color brilliance and softness on repeated washes. It is also used in 100% blends in many applications like bottom wear and home textiles due to its high dry and wet strength.

This 3<sup>rd</sup> generation Cellulosic Fibre 'Birla Excel' is manufactured by dissolving cellulose (pulp sheets) in an organic solvent to form a polymer solution, which is spun, through an air gap into an aqueous regeneration bath to form cellulose fibres. M/s Grasim has continuously enhanced its lyocell process understanding there by improving the design & engineering specifically in the areas of dope preparation, spinning & solvent recovery system. The solvent is recovered and recycled to the extent greater than 99.7% level in commercial plants. The lyocell process is the most environment friendly & green process as compared to manufacturing process of other regenerated cellulose fibres. This technological innovation would provide significant benefits to downstream textile and non-woven industry, catering to the rising demand of eco-friendly man-made fibres and provide sustainable raw material for growing demand of technical textiles in the country alongwith reducing excel fibre



import dependence. In terms of consumption, Asia Pacific dominated the global lyocell market in 2018. Favorable growth of the textile industry in emerging economies such as China and India has created a highly conducive environment for growth of lyocell fabrics market in the region. Recently, there has been increasing demand for lyocell fabric in healthcare applications due to its high tensile nature. The target premium markets include Indian subcontinent & Middle East.

Although the plant is designed for the capacity of 50 TPD, the optimum production from the proposed plant has been pegged at 45 TPD. This commercial line is projected for the Indian Market.

The total investment on setting up the project "Birla Excel Solvent Spun Cellulosic Fibre Plant" was assessed to ₹ 689.00 Crore and TDB had sanctioned Term loan aggregating to ₹ 250.00 Crore. M/s Grasim Industries Limited has completed the project and commenced commercial operation from 01.05.2019. Repayment of the loan will be started from April 2020.

## Development and Commercialization of SkyNet Programmatic TV Platform

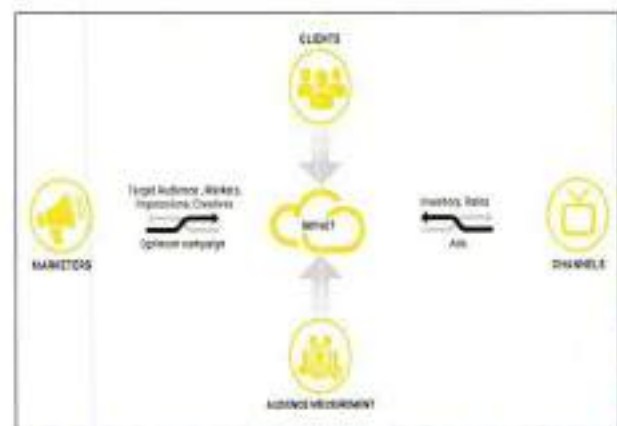
M/s Sure Waves Mediatech Pvt. Ltd., Bangalore

Information Technology

M/s SureWaves a Media Convergence Pioneer, has developed Skynet, through In-house R&D, is a first-of-its-kind Programmatic Television Advertising. It automates the entire process for the mainstream television advertising by providing a unified platform for both, the advertisers/agencies and the broadcasters, to find each other and execute campaigns on broadcast channels in a simple, systematic and accountable manner.

SureWaves' new offering represents a paradigm shift in the world of television advertising. Programmatic advertising has been prominent in digital media and has proved to be highly efficient and accountable, but it is yet to be implemented successfully, end-to-end on television before. Skynet for the first time, enables a data driven, technology-based empowerment for the planning, buying, measurement and optimization disciplines of traditional television advertising. Beyond its application in simplifying television advertising,

Traditionally, television advertising planning has been a complex, time consuming process. Moreover, it has been difficult for planners to get instant data on their campaigns, thus prolonging the time for course correction. Skynet seeks to change that with robust technology using sophisticated planning algorithms that guarantee



absolute and measurable implementation of a brands' television campaign.

Skynet with its new-age technology and far-reaching impact, has already seen widespread interest from leading broadcasters and media agencies in India and the Company has already begun pilot engagements with select customers and partners to pave the way for full-scale commercialisation of the platform.

The total investment of the project was assessed to ₹ 4709 Lakhs and TDB had sanctioned Term loan aggregating to ₹ 980 Lakhs. M/s SureWaves has completed the project and commenced commercial operation from 23<sup>rd</sup> August, 2019. Repayment of the loan to be start from 23<sup>rd</sup> August,2020

## Development and commercialization of straw utilization technology: In-situ Accelerated and Sustainable Rice Straw Decomposition (ASRSD)

M/s Kanbiosys Pvt. Ltd., Pune



Agriculture

M/s Kanbiosys Pvt. Ltd., Pune is an Agri-biotech based Company engaged in the production of microbial inputs for agriculture. Through in-house R&D, they have developed a product "Speed Kompost" which is an organic manure based microbial consortia containing ligno-cellulose degrading fungi and bacteria and having shelf life of one year.

Fungi are produced by solid state fermentation while bacterial cultures are grown under submerged fermentation conditions and the dormant forms of these microbes are mixed with organic manure carrier. They have also developed the Microbe food which boosts the initial growth of microbes to ensure early colonization on rice straw.

Stubble burning in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh is considered one of the traditional practice for getting their field ready for next crop (Kharif / rabi). However, this practice contributes to poor air quality, poor soil health and hence the invert impact on the yield of the future crop.

Product offered by the company is of greater importance as it focuses on the utilization of rice straw in-situ degradation approach utilizing microbial cultures and other technical inputs etc. One of the major benefits of this technology is that the microbial culture is directly added to the soil where they aid in cellulose, starch and silica conversion. This technology involves minimal use of machinery and water. This is an economically viable option to farmers for management of rice straw and at the same time maintaining soil health for higher yield and



pollution abatement measures by efficiently recycling of hard to recycle organic waste yielding stable compost which is Residue free and Non-toxic.

The Company Exemplifies the India's move on Waste to Wealth. The total investment of the project was assessed to ₹ 518.00 Lakhs and TDB had sanctioned Term loan aggregating to ₹ 174.00 Lakhs. M/s Kanbiosys Pvt. Ltd., Pune has completed the project and commenced commercial operation from 31<sup>st</sup> August, 2019. Repayment of the loan to be started from 1<sup>st</sup> April, 2020.

## Cold Mix Technology in Road Construction & Maintenance

M/s BitChem Asphalt Technologies Ltd., Guwahati

Chemical



Laying of Cold Mix with Paver



Compaction of Cold Mix



Cold Mix Road Finished Surface

M/s BitChem Asphalt Technologies Limited (BATL) is a new-generation road science and technology enterprise. It is engaged in promoting Green road philosophy by using environment-friendly Cold Mix Technology in road construction and maintenance. M/s Bitchem sourced this Cold Mix Technology from Central Road Research Institute (CRRI) on exclusive basis for construction & maintenance of Roads for all applications. The company has made further improvements in this technology by carrying out in-house Research & Developments to address field challenges at site applications such as varied aggregate quality, need of pre-wetting of

aggregates and utilizing various existing mixing equipment used for the conventional Hot Mix Process etc. thereby saving time and drastically reducing environmental pollution. A patent has been filed by the company on Tailor-made Cold Binder.

The total investment of the project was assessed to ₹ 1831.03 Lakhs and TDB had sanctioned Term loan aggregating to ₹ 820.00 Lakhs. M/s Bitchem has completed the project and commenced commercial operation from 30<sup>th</sup> September, 2019. Repayment of the loan to be start from 1<sup>st</sup> July, 2020.

## Development and Commercialization of Catheter Reprocessing System

M/s Incredible Devices Pvt. Ltd., Chandigarh

Health & Medical



M/s Incredible Devices Private Limited (IDPL) has developed cost effective Catheter Reprocessing System (CRS) system, which is an automatic computer guided Catheter cleaning machine with inbuilt self-testing and calibration which ensures cleaning of catheter. CRS inbuilt computer stringently monitors every process and effectively cleans catheters with precision and accuracy. It can reprocess all types of catheters used in cardiac, neuro, gastro and interventional radiology. A catheter comes in different size and shape. Hence, they require different cleaning parameter such as water pressure, flow, volume, multi enzyme dilution, etc.

CRS can reprocess up to 12 catheters in 1 cycle. Each catheter is attached to a dedicated port with inbuilt sensors which identify the type of catheter attached and accordingly calibrate the pre mentioned catheters to ensure best cleaning. CRS uses a patented cleaning process called DFC (Dynamic Fluid Cleaning). It generates laminar, turbulent, critical transitional and turbulent flow to break biofilms, helps enzyme binding, generate critical pressure to breakdown fibrin and much more. Catheters are first flushed with chemical solution using DFC Technique



which eliminates contamination. Once done, CRS rinses off catheters with water to remove chemical traces. It then dries the catheter with dry clean air and make them ready for sterilization.

Incredible Devices has benefited more than 2.5 Lakh economically weak patients. This product, CRS (Catheter Reprocessing System) is being used across 14 leading hospitals across 9 states in India. Total investment of the project was assessed at ₹ 104.80 lakhs and TDB sanctioned term loan aggregating to ₹ 46.61 lakh. M/s Incredible Devices Private Limited completed the project successfully and started commercial production from November 2019.

## Development and Commercialization of Portable X-ray machine

M/s. latome Electric India Pvt. Ltd., Coimbatore

Health & Medical

latome is a Power Electronics Engineering and Technology company with product profile on X-Ray Generators and High Voltage Electronics. The company has developed products for GE Medical Systems & BPL Medical Systems. Further, they have researched and developed their own indigenous technology for x-ray generation, involving advanced methods in electrical, mechanical, high voltage, materials & software engineering. Company produce innovative x-ray products such as a hand-held battery operated x-ray machine etc. with the support form TDB and be able to sale in market.

The supported project is for manufacturing and commercialization of four types of X-Ray Imaging Equipment including:

- Portable Hand Held X-Ray- This is a battery operated compact x-ray machine that can be hand held and operated. This equipment is specifically designed for dental intra-oral radiography.
- Digital Imaging for Dental X-Ray- To complement first product, the company is worked on a digital x-ray sensor. Using this, x-ray imaging can go filmless and software part is developed in-house.
- Portable General X-Ray- This is the multi-purpose x-ray equipment. The device is designed



Battery powered handheld portable Dental X-Ray

- to be highly mobile/portable, simple to operate, reliable and with a battery back-up to enable usage even without electric power.
- X-Ray Generator for Fluoroscopy- This is OEM sub-component product which used by the many C-Arm system builders in the country.

The total investment of the project was assessed to ₹ 536.00 Lakhs and TDB had sanctioned Term loan aggregating of ₹ 203.00 Lakhs. Company has completed the project and commenced commercial operation from 31<sup>st</sup> December, 2019. Repayment of the loan to be start from 1<sup>st</sup> January, 2021.

## Development and Commercialization of RF Seekers

M/s VEM Technologies Pvt. Ltd., Hyderabad

Engineering



Modern airborne systems need all weather, fire & forget capability in detecting and tracking a target. These functions are performed by RF sensor, which is called by trade-name RF seeker. The seeker is essentially a high-tech Microwave radar mounted on the nose of an air borne system with Radome providing environmental protection to it. These are compact in size and less in weight.

These seekers are complex in nature and highly customized to meet the stringent space, weight and dynamic constraints of different air borne systems.

The RF Seeker developed by the company is a pulsed Doppler radar, with capability of multiple PRF Waveform. The antenna is stabilized to maintain the line of sight to the target in spite of the body motion of the missile.

The RF Seeker can track the target in angle, velocity and range. Based on the designation given in angle, velocity and range; the seeker detects the target, subsequently locks on to



it; then it goes into tracking mode. The signal for transmission is generated by the exciter coherently using precise local oscillator and the PRF specs of the system.

While the seeker was being developed, supporting technologies were also developed, e.g. servo-control stabilization system components like motors, encoders, gyros; slotted array antenna design, fabrication and brazing; MMIC die handling, bonding etc. VEM successfully developed the sub-systems of RF Seekers, Antenna, Signal Processing Board, Radar & Control SOC, Circulator, 4 Channel uW/IF Receivers, Exciters, 4 Watt Ka Band Transmitter, WG Rotary joint, EL/AZ Drives, Dual Servo Amplifiers.

VEM Technologies built the state of the art facility for RF Seeker Production with to produce minimum @ two Seekers/day; dedicated SMT line for PCBA, Hi-precision CNC machinery, 8000 Sq.ft., clean room facility, Microwave Fabrication; RF & MW equipment (upto 40 GHz), HV & PE Equipments, Anchoic chambers for compact range and HILS besides the ESS facilities for testing.

The total investment of the project was assessed to ₹ 5900.00 Lakhs and TDB had sanctioned Term loan aggregating to ₹ 2500.00 Lakhs. M/s VEM Technologies has completed the project and commenced commercial operation from 30<sup>th</sup> December, 2019. Company is already making the Repayment of the loan from 1<sup>st</sup> July, 2018.





# Promotional Activities

### Global Bio-India Summit 2019 (21<sup>st</sup> - 23<sup>rd</sup> November, 2019)

TDB participated in the Global Bio-India Summit 2019, which was organised by the Department of Biotechnology (DBT) and its Public Sector Undertaking, Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC) at Aerocity, New Delhi. The Summit was an international congregation of biotechnology stake holders, regulatory bodies, Central and State Ministries, SMEs, large industries, bio clusters, research institutes, investors, and the startup ecosystem.



The summit was inaugurated by Dr. Harsh Vardhan, Hon'ble Union Minister for Science and Technology, Health and Family Welfare and Earth Sciences; During the summit, the TDB's delegate interacted with the innovative startup owners and industrialists and explained them about the funding mechanism that is offered by TDB.

### 8<sup>th</sup> GITA Foundation Day (28<sup>th</sup> November, 2019)

TDB participated in the 8<sup>th</sup> Foundation day of Global Innovation and Technology alliance (GITA) held on 28<sup>th</sup> November 2019 at New Delhi. The Foundation Day was themed at "Making India Future Ready". Dr. Harsh Vardhan, Hon'ble Minister of Health & Family Welfare, Science & Technology, Earth Sciences, was the chief guest and felicitated 15 successful projects supported by Global Innovation and Technology Alliance (GITA). The projects ranged from areas including smart transport management to biomedical technologies and smart water quality monitoring solutions.



Three specific sessions dedicated to Spain, Israel and Canada were also organised showcasing bilateral technology cooperation and their products. The GITA Foundation Day was also addressed by the Prof. KVijayraghavan, Principal Scientific Adviser to the Govt. of India, Prof. Ashutosh Sharma, Secretary Department of Science & Technology, Dr. Neeraj Sharma, Secretary Technology Development Board, Mr S. K. Varshney, Head, International Bilateral Cooperation, DST and various other dignitaries as well as industry leaders. Besides, there were delegations from Canada, Israel, Korea and Spain along with international participation from Brazil, Finland, Italy, Sweden, Taiwan and the UK.

### Bharat Biotech ROTAVAC 5D® 2019 (3<sup>rd</sup> December, 2019)

TDB participated in the launch of a new variant of rotavirus vaccine ROTAVAC 5D®, a smaller dosage form of its earlier oral immunisation shot that can be stored at a relatively higher temperature. The launch was inaugurated by Minister for Science and Technology Dr. Harsh Vardhan.



M/s Bharat Biotech was one of the initial companies to be funded by TDB. The Company received financial assistance from TDB for the production of recombinant vaccine for Hepatitis B, which was successfully launched in the year 1998.

### Hands-on Workshops at the NASSCOM-DSCI Annual Information Security Summit 2019 (3<sup>rd</sup> December, 2019)

TDB participated in Annual Information Security Summit 2019 organised by NASSCOM-DSCI. The workshop unfurled an array of activities including brainstorming and collating a list of suggestions for combating an upcoming age of Secure Automated and AI Enabled Networks.



Mr. Manish Chaudhary, Scientist D, TDB addressed the audience and talked about Building Secure Automated and AI Enabled Networks during the AISS Workshop. Delegates from TDB interacted with various entrepreneurs in cyber security space and exchanged information on TDB's funding process.

### Indian R & D Ecosystem Conclave organised by The Confederation of Indian Industry (CII) (17<sup>th</sup> December, 2019)

TDB participated in Indian R & D Ecosystem Conclave organised by the CII. The objective of this conclave was to foster India's R&D ecosystem and to improve India's international ranking in the Global Innovation Index (GII) 2020 by addressing data gaps. TDB interacted with various entrepreneurs and exchanged information on TDB's funding mechanism.



### 107<sup>th</sup> Session on Indian Science Congress (3<sup>rd</sup> January, 2020)

TDB participated in the 107<sup>th</sup> session of Indian Science Congress which was held during January 3<sup>rd</sup> - 7<sup>th</sup>, 2020 at University of Agricultural Sciences, GKVK Campus, Bangalore, Karnataka focusing on 'Science & Technology:



Rural Development'. The event was inaugurated by Hon'ble Prime Minister Sri Narendra Modi on 3<sup>rd</sup> January, 2020. TDB utilised this platform to inform the delegates about various funding models of TDB.

### Inauguration of Grading & Sorting Machine developed by M/s Sickle Innovation Pvt. Ltd 2020 (28<sup>th</sup> January, 2020)

TDB participated in inauguration ceremony of Grading & Sorting Machine developed by M/s Sickle Innovation Pvt. Ltd on 28<sup>th</sup>, January 2020. M/s Sickle Innovation Pvt. Ltd, Ahmedabad, has been financially assisted by TDB for the project "Grading & Sorting Machine for Fruits &Vegetables".



The company has successfully installed their grading machine for an Integrated Pack House in Centre of Excellence for Vegetables, Gharaunda, Haryana in the gracious presence of the Hon'ble Agriculture Minister of Haryana, Shri J. P. Dalal, and Dr. Ron Malka, Ambassador of Israel to India.





**Administration**

### Annual Report and Audited Accounts

Section 12 of the Technology Development Board Act, 1995, prescribes that the Board shall prepare its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year. As per section 13(4) of the Technology Development Board Act, the Board has to furnish to the central Government, its audited copy of accounts together with auditor's report.

The Annual report, including audited copy of the Annual Accounts of the Technology Development Board for the year 2018-19 was laid before Rajya Sabha and Lok Sabha on 10.12.2019 and 10.02.2020 respectively.

### New Incumbent

Col. Rajesh Jain (Retd.) from the Indian Army has joined the Technology Development Board (TDB) as Director w.e.f. 1<sup>st</sup> September, 2019. Col. Rajesh Jain (Retd.) has worked for 33 years in the Army at various levels mostly in Administration, Technical and Financial domains.

### Implementation of Official Language

With a view to ensure compliance of the constitutional provisions regarding official language, TDB has been encouraging the usage of Hindi in official communication. In TDB all the important documents such as Gazette Notifications, Annual Reports, Vacancy Notices, and Project Funding Guidelines etc are printed in Hindi and English.

During, the year 2019-20, Hindi workshops were organised on regular basis. Hindi Pakhwada / Hindi Diwas was also celebrated in the month of September, 2019, wherein various competition such as Shrutilekh, Essay writing, Poetry, Speech, Translation etc were organised.





**Audited Annual Statement of  
Accounts for the year 2019-20**

# Technology Development Board

Balance Sheet as on 31<sup>st</sup> March, 2020

Amount in ₹

	Schedule	Current Year	Previous Year
<b>Corpus/Capital Fund and Liabilities</b>			
Corpus/Capital Fund	1	146852,37,882	134695,57,301
Reserves and Surplus	2	-	-
Earmarked/Endowment Funds	3	463,51,775	1432,13,644
Secured Loans and Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans and Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities	6	-	-
Current Liabilities and Provisions	7	7734,99,891	582,58,593
<b>TOTAL</b>		<b>155050,89,548</b>	<b>136710,29,538</b>
<b>Assets</b>			
Fixed Assets	8	66,77,633	68,68,735
Investment-From Earmarked/Endowment Funds	9	65,99,000	65,99,000
Investments-others	10	14019,52,366	18359,96,145
Current Assets, Loan, Advances Etc.	11	140898,60,549	118215,65,658
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or Adjusted)			
<b>TOTAL</b>		<b>155050,89,548</b>	<b>136710,29,538</b>
Significant Accounting Policies	24	-	-
Contingent Liabilities and notes on Accounts	25	-	-

-Sd-  
**(Rajesh Jain)**  
Director  
Technology Development  
Board

-Sd-  
**(Dr. Neeraj Sharma)**  
Secretary  
Technology Development  
Board

-Sd-  
**(Prof. Ashutosh Sharma)**  
Chairperson  
Technology Development  
Board

# Technology Development Board

Income and Expenditure Accounts for the Year Ended 31<sup>st</sup> March, 2020

Amount in ₹

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
Income From Sales/ Services	12		
Grants / Subsidies	13	9838,34,331	10380,31,997
Fees/ Subscriptions	14	-	-
Income From Investments (Income On Invest. From Ear-marked/Endow)	15	-	-
Income From Royalty, Publication Etc.	16	44,87,232	62,82,547
Interest Earned	17	6360,54,565	5879,02,506
Other Income	18	3,03,563	598,34,725
Increase / (Decrease) In Stock of Finished Goods And Works-In-Progress	19		
<b>Total (A)</b>		<b>16246,79,691</b>	<b>16920,51,775</b>
<b>EXPENDITURE</b>			
Establishment Expenses	20	335,32,639	274,93,743
Other Administrative Expenses Etc.	21	3521,08,711	605,82,807
Expenditure On Grants, Subsidies Etc.	22	10,84,242	11,08,267
Interest	23	209,24,330	-
Depreciation (Net Total At The Year-End - Corresponding To Schedule -B)		11,03,455	12,28,970
<b>Total (B)</b>		<b>4087,53,377</b>	<b>904,13,787</b>
<b>Balance Being Excess of Income Over Expenditure (A-B)</b>		<b>12159,26,314</b>	<b>16016,37,988</b>
Prior Period Adjustments		(2,45,734)	(185,86,680)
Provision For Impairment of Investments			
Transfer To - General Reserve		-	-
<b>Balance Being Surplus Carried To Corpus Fund</b>		<b>12156,80,580</b>	<b>15830,51,308</b>
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and notes on Accounts	25		

-Sd-  
**(Rajesh Jain)**  
Director  
Technology Development  
Board

-Sd-  
**(Dr. Neeraj Sharma)**  
Secretary  
Technology Development  
Board

-Sd-  
**(Prof. Ashutosh Sharma)**  
Chairperson  
Technology Development  
Board

# Technology Development Board

## Receipts and Payments Accounts for the Year ended 31<sup>st</sup> March, 2020

Amount in ₹

RECEIPTS		Current Year	Previous Year
<b>Opening Balance</b>			
ii	Investment in short term deposits	4995,00,000	2000,00,000
ii)	Cash in hand	23,520	36,408
<b>Cash at Bank</b>			
a)	Bank Balance	759,89,345	2449,90,971
b)	Bank Balance- DFID INVENT	1366,14,643	1162,09,187
<b>Fund for Technology Development &amp; Application</b>			
ii	TD Fund	9800,00,000	10000,00,000
ii)	Fund For Fighting COVID-19	7500,00,000	-
iii)	Interest on short term deposits	334,75,287	209,24,330
iv)	Interest on loans	764,94,764	642,59,498
v)	Interest on royalty	2,95,247	8,03,520
vi)	Pending adjustments against loan recoveries	-	537,79,000
vii)	Repayment of loans	6333,72,600	3285,40,326
viii)	Royalty	44,87,232	63,25,887
ix)	Donations	3,00,000	1,00,100
x)	Unspent Grant received back	38,34,331	380,31,997
xi)	Interest on saving accounts (including EPF A/c)	86,65,931	152,86,632
xii)	Income recd from VCF Fund	-	595,66,726
xiii)	Miscellaneous receipts	3,563	1,67,899
xiv)	Security Deposit / Earnest Money received/ Others	1,64,231	21,14,625
xv)	Multi Sector Seed Fund	76,55,900	960,00,000
xvi)	UTI_Ascend Indian Fund	146,31,293	-
xvii)	RYCF	34,34,150	147,17,787
xviii)	GVFL	-	-
xix)	Equity realisation	656,68,800	-
xx)	SIDBI Venture Fund	144,18,678	137,96,582
xxi)	Venture East Tenet Fund	-	696,18,695
xxii)	Indian Fund for Sustainable Energy (CIIE)	-	321,54,028
xxiii)	IvyCap Venture Trust Fund-1	10,34,438	142,16,626
xxiv)	APIDC Venture Fund	250,00,000	652,14,000
xxv)	SEAF India Fund	186,63,888	58,47,619
xxvi)	DFID INVENT receipt for Project	-	1823,46,693
xxvii)	DFID INVENT savings interest	31,38,224	30,80,455
<b>TOTAL</b>		<b>33568,66,065</b>	<b>26481,29,591</b>

-Sd-  
**(Rajesh Jain)**  
Director  
Technology Development  
Board

-Sd-  
**(Dr. Neeraj Sharma)**  
Secretary  
Technology Development  
Board

-Sd-  
**(Prof. Ashutosh Sharma)**  
Chairperson  
Technology Development  
Board

# Technology Development Board

Receipts and payments Accounts for the Year ended 31<sup>st</sup> March, 2020

Amount in ₹

Payments		Current Year	Previous Year
<b>ESTABLISHMENT EXPENSES</b>			
i)	Salaries	316,67,445	265,03,428
ii)	Travel Expenses (Domestic)	17,73,934	30,23,147
iii)	Travel Expenses (International)	-	1,41,983
iv)	Staff Welfare Expenses	77,000	67,000
v)	Medical Expenses	2,23,558	5,09,718
vi)	Pension Contribution For Deputationists	-	11,60,124
<b>OFFICE EXPENSES</b>			
i)	Telephone / Telex	20,66,491	19,80,122
ii)	Postage Stamps	55,443	54,927
iii)	Petrol, Oil & Lubricants	41,422	1,88,344
iv)	Repairs & Maintenance	12,80,715	10,56,179
v)	Consumable Stores & Printing	12,09,624	7,76,731
vi)	Newspapers & Magazines	36,123	25,797
vii)	Entertainment & Hospitality	1,90,132	1,66,083
viii)	Meeting Expenses	15,33,468	19,52,570
ix)	Advertisement & Publicity	63,26,171	55,82,603
x)	Technology Day Expenditure	6,96,212	20,86,809
xi)	Miscellaneous Expenses	6,59,475	7,61,270
xii)	National Award	-	170,00,000
xiii)	Library Books & Journals	885	6,116
xiv)	Legal Charges	44,78,038	52,55,524
xv)	Asset Management Charges	71,96,785	47,29,272
xvi)	TA / DA To Experts	26,04,299	33,71,869
xvii)	Honorarium To Experts And Members	55,00,880	30,19,900
xviii)	Membership Fees	23,600	23,600
xix)	Audit Fees	77,850	2,15,056
xx)	Rent	85,36,700	73,60,017
xxi)	Remittance Of Recoveries To Other Deptts.	-	-
xxii)	Security Deposits & Advance To Staff	46,505	3,48,000
xxiii)	Duties & Taxes	4,60,031	4,19,091
xxiv)	Renovation & Refurbishing	-	14,75,348
<b>BOARD EXPENSES</b>			
i)	TA / DA To Members	24,457	1,24,076
ii)	Fee And Board Meeting Expenses	1,43,645	78,571
<b>CAPITAL EXPENDITURE</b>			
i)	Fixed Assets	9,12,353	3,43,428

<b>DISBURSEMENTS</b>			
i)	Loans	12837,12,000	16372,50,000
ii)	Grants	10,84,242	11,08,267
iii)	Interest on Grant Paid	209,24,330	-
iv)	SIDBI VCF	-	362,62,758
v)	SEAF India Agribusiness Fund	5,77,473	49,38,761
vi)	Indian Fund for Sustainable Energy (CIIE)	20,15,756	16,13,902
vii)	DFID INVENT Project Expenditure	1000,00,000	1650,00,000
viii)	DFID INVENT Bank Charges	91	21,691
<b>CLOSING BALANCE</b>			
i)	Investment in Short Term Deposits	5699,00,000	4995,00,000
ii)	Cash in Hand	34,976	23,520
	<b>Cash at Bank</b>		
A)	Bank Balance (Including EPF A/c)	126,10,21,180	759,89,345
B)	Bank Balance - DFID INVENT	397,52,776	1366,14,643
	<b>Total</b>	<b>335,68,66,065</b>	<b>26481,29,591</b>

-Sd-  
**(Rajesh Jain)**  
 Director  
 Technology Development  
 Board

-Sd-  
**(Dr. Neeraj Sharma)**  
 Secretary  
 Technology Development  
 Board

-Sd-  
**(Prof. Ashutosh Sharma)**  
 Chairperson  
 Technology Development  
 Board

# Technology Development Board

Schedules Forming Part of balance Sheet as on 31<sup>st</sup> March, 2020

Amount in ₹

	Current Year		Previous Year	
<b>SCHEDULE 1- CORPUS/CAPITAL FUND</b>				
Balance as at the beginning of the year	134695,57,302			118865,05,993
Add: Contributions Towards Corpus/Capital Fund	-		-	-
Add : Balance Of Net Income Transferred From The Income And Expenditure Account [Refer To Note No 25 (11)]	12156,80,580			15830,51,309
<b>Balance As At The Year- End</b>		<b>146852,37,882</b>		<b>134695,57,302</b>

Amount in ₹

<b>SCHEDULE 2- RESERVES AND SURPLUS</b>				
	Current Year		Previous Year	
<b>1. Capital Reserve:</b>				
As Per Last Account				
Addition During The Year				
Less: Deductions During The Year	-	-	-	-
<b>2. Revaluation Reserve:</b>				
As Per Last Account				
Addition During The Year				
Less: Deduction During The Year	-	-	-	-
<b>3. Special Reserves:</b>				
As Per Last Account				
Addition During The Year				
Less: Deduction During The Year	-	-	-	-
<b>4. General Reserve:</b>				
As Per Last Account				
Addition During The Year				
Less: Deduction During The Year				
<b>Total</b>	-	-	-	-

# Technology Development Board

Schedule Forming Part of Balance Sheets as on 31<sup>st</sup> March, 2020

Amount in ₹

SCHEDULE 3- EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS				
Liabilities	Current Year		Previous Year	
<b>A. VCF of IDBI</b>				
1) Contribution received by IDBI from Government of India		2884,00,000		2884,00,000
<b>Income from Investment</b>				
a. Interest	1331,47,041		1308,52,144	
b. Royalty	551,97,900		551,97,900	
c. Dividend	86,23,794		86,23,794	
d. Accrued income Less waivers	23880,81,913		23903,76,810	
	<b>25850,50,648</b>		<b>25850,50,648</b>	
Less : Amount transferred to TDB	2125,00,000		2125,00,000	
	<b>26609,50,648</b>		<b>23725,50,648</b>	
Less: Excess Royalty recd. earlier adjusted towards principal	112,50,000		112,50,000	
	<b>26497,00,648</b>		<b>23613,00,648</b>	
Less : Loans written off	436,36,450		436,36,450	
Less : Loss on sale of Investment	26,76,250		26,76,250	
	<b>26033,87,948</b>		<b>23149,87,948</b>	
Less : Provision on loan	832,79,357		810,04,357	
Less : Provision on interest & FILD	23880,81,913		23903,76,810	
Less: Audit Fees & other Expenses	18,32,324		17,52,075	
Less : Management fees to IDBI	1571,80,000		1432,60,000	
Less: Diminution in value of investment	26,26,000	(296,11,646)	26,26,000	(3040,31,294)
		(296,11,646)		-156,31,294
*Amount receivable from TDB (31.03.2019)		362,10,646		222,30,294
		<b>65,99,000</b>		<b>65,99,000</b>
<b>B. Innovative Ventures for Technology Development (INVENT) - DFID</b>		<b>397,52,775</b>		<b>1366,14,643</b>
<b>TOTAL</b>		<b>463,51,775</b>		<b>1432,13,643</b>

**\*Note:**

- 1) Due to non performance of the fund, the amount of management expenses claimed by IDBI has been disputed by TDB
- 2) Amount of Rs. 3,62,10,646/- has been claimed by IDBI as payable by TDB as per their last audited balance sheet for the year ended 31.03.2019. The said amount has arisen due to high management fees charged by IDBI which is disputed by TDB. TDB does not acknowledge the payment of said amount pending resolution of said amount.

# Technology Development Board

Schedule Forming Part of Balance Sheets as on 31<sup>st</sup> March, 2020

Amount in ₹

SCHEDULE 4- SECURED LOANS AND BORROWINGS:					
		Current Year		Previous Year	
1.	Central Government	-	-	-	-
2.	State Government(Specify)	-	-	-	-
3.	Financial Institutions				
	a) Term Loans				
	b) Interest Accrued and Due	-	-	-	-
4.	Banks				
	a) Term Loans				
	- Interest accrued and due				
	b) Other Loans(Specify)				
	- Interest accrued and due	-	-	-	-
5.	Other Institutions and Agencies	-	-	-	-
6.	Debentures and Bonds				
<b>TOTAL</b>		-	-	-	-
<b>Note:</b> Amounts due within one Year					

Amount in ₹

SCHEDULE 5- UNSECURED LOANS AND BORROWINGS					
		Current Year		Previous Year	
1.	Central Government	-	-	-	-
2.	State Government (Specify)				
3.	Financial Institutions	-	-	-	-
4.	Banks:				
	a) Terms Loans	-	-	-	-
	b) Other Loans (Specify)	-	-	-	-
5.	Other Institutions and Agencies	-	-	-	-
6.	Debentures and Bonds	-	-	-	-
7.	Fixed Deposits	-	-	-	-
8.	Others (Specify)	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		-	-	-	-
<b>Note:</b> Amounts due within one Year					

# Technology Development Board

## Schedule Forming Part of Balance Sheet as on 31<sup>st</sup> March, 2020

Amount in ₹

SCHEDULE 6- DEFERRED CREDIT LIABILITIES				
	Current Year		Previous Year	
a. Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	-	-	-
b. Others				
<b>TOTAL</b>				
<b>Note :</b> Amounts due within one year				

SCHEDULE 7- CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS				
	Current Year		Previous Year	
<b>A. CURRENT LIABILITIES</b>				
1. Unutilised balance of Grant in aid 'Fighting COVID-19'		7500,00,000		-
2. Sundry Creditors				
a) For Goods	-			
b) Others	-	-		
3. Security Received		-		-
4. Interest accrued but not due on :				
a) Secured Loans /borrowings				
b) Unsecured Loans/borrowings	-	-		-
5. Statutory Liabilities				
a) TDS	3,60,502		4,12,429	
b) GST	48,961		40,342	-
c) GPF payable				
d) EPF payable	3,33,797	7,43,260	3,04,906	7,57,677
6. Other current Liabilities				
a) Pension contribution for deputations				
b) Audit fee payable	3,89,839			3,87,689
c) Pending Adjustment	-			537,79,000
d) others	-	3,89,839		7,260
<b>TOTAL (A)</b>		<b>7511,33,099</b>		<b>549,31,626</b>
<b>B. PROVISIONS</b>				
1. Gratuity	17,08,387			13,52,473
2. Salary Payable	18,05,917			16,14,494
3. Legal charges payable	-			3,60,000
4. National Award Payable	170,00,000			-
5. Other Expenses Payable	18,52,488	223,66,792		-
<b>TOTAL (B)</b>		<b>223,66,792</b>		<b>33,26,967</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>7734,99,891</b>		<b>582,58,593</b>

# Technology Development Board

Schedule Forming Part of Balance Sheets as on 31<sup>st</sup> March, 2020

Amount in ₹

SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS	DESCRIPTION	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
		Cost/ valuation As at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/ valuation at the year-end	As at the beginning of the year	On Additions during the year	On Deductions during the year	Total up to the year-end	Sale/ Adjustments	As at 31.3.2020
<b>A. FIXED ASSETS:</b>											
1. LAND:											
a) Freehold											
2. BUILDING:											
b) On Leasehold Land											
c) Ownership House/ Premises											
d) Superstructures on Land not belonging to the entity											
3. PLANT MACHINERY & EQUIPMENT											
4. VEHICLES											
5. FURNITURE, FIXTURES											
6. OFFICE EQUIPMENT											
7. COMPUTER PERIPHERALS											
B. ELECTRIC INSTALLATIONS											
9. LIBRARY BOOKS											
10. SOFTWARE (PMSH-40%)											
11. OTHER FIXED ASSETS											
<b>TOTAL OF CURRENT YEAR</b>											
<b>B. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS* (Software)</b>											
<b>TOTAL</b>											
(Note to be given as to cost of assets on line purchase basis included above)											
<b>PREVIOUS YEAR</b>											
13,811,915											
343,428											
13,955,343											
1,228,970											
5,857,638											
7,086,668											
-											
6,868,735											
7,754,277											

\*Software WIP being capitalised during the year on completion of the Software

# Technology Development Board

## Schedule Forming Part of Balance Sheet as on 31<sup>st</sup> March, 2020

Amount in ₹

SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS			
	Current Year		
1. In Government Securities		-	-
2. Other approved Securities		-	-
3. Shares		-	-
4. Debentures and Bonds		-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures		-	-
6. VCF of IDBI ( Assets)		-	-
<b>Investment</b>			
(i) Loan	810,04,357		810,04,357
Less: Provisions	810,04,357	-	810,04,357
(ii) Equity	92,25,000		92,25,000
Less: Diminution in value of Investment	26,26,000	65,99,000	26,26,000
<b>Receivables</b>			
(i) Interest	2997,69,021		2997,69,021
(ii) FILD	20906,07,789		20906,07,789
	<b>23903,76,810</b>		<b>23903,76,810</b>
Less: Provisions	23903,76,810	-	23903,76,810
<b>TOTAL</b>		<b>65,99,000</b>	<b>65,99,000</b>

# Technology Development Board

Schedule Forming Part of Balance Sheet as on 31<sup>st</sup> March, 2020

Amount in ₹

SCHEDULE 10 – INVESTMENTS-OTHERS			
	Current Year		Previous Year
1. In Government Securities			
2. Other approved Securities			
3. Shares-Equity/ Preference participation	2846,72,726		2846,72,726
Less: Realisation against shares	765,09,759	2081,62,967	
4. Debentures and Bonds			
5. Subsidiaries and Joint Ventures			
6. Venture Funds			
a) UTI Ascent India Fund	2899,20,195		2899,20,195
Less : Redemption	146,31,293		
Less :Loss on closure of venture fund	2752,88,902	-	
b) APIDC Venture Funds	2347,86,000		
Less: Redemption	250,00,000	2097,86,000	2347,86,000
c) Ventureast TeNet Fund	441,43,882		
Less: Redemption	-	441,43,882	441,43,882
d) GVFL	1,50,000		
Less: Redemption	-	1,50,000	1,50,000
e) RVCF	1178,74,724		
Less: Redemption	34,34,150	1144,40,574	1178,74,724
f) SIDBI VCF	1887,26,863		
Add: Disbursement	-		
Less: Redemption	144,18,678	1743,08,185	1887,26,863
g) IvyCap Venture Trust Fund-1	2168,92,238		
Add: Disbursement	-		
Less: Redemption	10,34,438	2158,57,800	2168,92,238
h) Multi Sector Seed Capital Fund	1040,00,000		
Less: Redemption	76,55,900	963,44,100	1040,00,000
i) SEAF India Agribusiness Fund	2281,35,470		
Add: Disbursement	5,77,473		
Less: Redemption	186,63,888	2100,49,055	2281,35,470
j) Indian fund for Sustainable Energy (CIIE)	546,44,047		
Add: Disbursement	20,15,756		
Less: Redemption	-	566,59,803	546,44,047
7. GITA	720,50,000		
Add: Disbursement	-	720,50,000	720,50,000
<b>TOTAL</b>		<b>14019,52,366</b>	<b>18359,96,145</b>

# Technology Development Board

Schedule Forming Part of Balance Sheet as on 31<sup>st</sup> March, 2020

Amount in ₹

SCHEDULE 11- CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.			
	Current Year		Previous Year
<b>A. CURRENT ASSETS:</b>			
<b>1. Inventories:</b>			
a) Stores and Spares			
b) Loose Tools			
c) Stock-in- trade			
i) Finished Goods			
ii) Work-in-progress			
iii) Raw Material	-	-	-
<b>2. Sundry Debtors</b>			
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months			
b) Others		-	1,278
<b>3. Cash balance in hand (including cheques/drafts and imprest)</b>		34,976	23,520
<b>4. Bank Balances:</b>			
a) With Schedules Banks:			
-On Current Accounts			
- On Savings Accounts -TDB ( including EPF A/c)	12610,21,180		759,89,345
- On Savings Accounts- INVENT -DFID	397,52,776	13007,73,956	1366,14,643
b) Short term Deposits with Scheduled Banks:			
- On Deposit Accounts	5699,00,000	5699,00,000	4995,00,000
- On Deposit Accounts INVENT-DFID			
<b>TOTAL (A)</b>		<b>18707,08,932</b>	<b>7121,28,786</b>

# Technology Development Board

## Schedule Forming Part of Balance Sheet as on 31<sup>st</sup> March, 2020

Amount in ₹

SCHEDULE 11- CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)			
	Current Year	Previous Year	
<b>B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS:</b>			
<b>1. Loans:</b>			
a) Staff			
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the entity	-		-
c) Loan : Assistance to industrial concerns			
Opening	73099,65,366		59929,81,284
Add: During the year	12837,12,000		16372,50,000
Less: Repayment/Adjustment of loan	6763,10,641		3285,40,326
Less: Written Off due to settlement of accounts	111,54,978		-
Less: Transfer to Accrued Interest.	18,89,347		-
Add: Transferred from Accrued Interest.	-		82,50,000
Add: Prior period Adjustments.	-		24,408
	79043,22,401		73099,65,366
Less: Provision for doubtful loan	-		89,05,867
Closing loan balance after provision	79043,22,401		73010,59,499
<b>2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or of value to be received</b>			
a) Advance to staff members	8,71,280		8,24,775
b) Income tax recoverable	11,38,824		10,36,673
c) Others - Security Deposit	9,90,280		11,06,280
d) Advance with vendors	-		-
e) Others	24,056	30,24,440	71,009
<b>3. Income Accrued:</b>			
a) On Investments from Earmarked/Endow.Funds			
b) On Investments - Short Term Deposits		36,83,794	80,36,475
Short Term Deposits- INVENT -DFID		-	-
c) On Loans and Advances	45625,70,377		41259,02,361
Less: Unrecoverable interest written off during the year	228,56,713		129,35,285
Less: Transfer to loan	-		82,50,000
Less: Prior Period Adjustments during the year	6,45,734		635,20,564
Add: Transfer from loan	18,89,347		-
	45409,57,277		40411,96,512
Less: Loan Interest Provision :	2328,36,294		2438,94,352
		43081,20,983	37973,02,160
<b>TOTAL (B)</b>		<b>122191,51,618</b>	<b>111094,36,871</b>
<b>TOTAL (A +B)</b>		<b>140898,60,549</b>	<b>118215,65,658</b>

## Technology Development Board

Schedule Forming Part of Income and Expenditure for the Year Ended 31<sup>st</sup> March, 2020

Amount in ₹

SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/SERVICES			
	Current Year		Previous Year
1. Income from Sales			
a) Sales of Finished Goods			
b) Sale of Raw Material			
c) Sale of Scraps	-	-	-
2. Income from Services			
a) Labour and Processing Charges			
b) Professional/Consultancy Services			
c) Agency Commission and Brokerage			
d) Maintenance Services(Equipment/Property)			
e) Others (Specify)			-
<b>TOTAL</b>	-	-	-

## Technology Development Board

Schedule Forming Part of Income and Expenditure for the Year Ended 31<sup>st</sup> March, 2020

Amount in ₹

SCHEDULE 13 - GRANTS/SUBSIDIES (Irrevocable Grants & Subsidies Received)			
	Current Year		Previous Year
1) Central Government		9800,00,000	10000,00,000
2) State Government(s)			
3) Institutions/Welfare Bodies		-	-
4) International Organisation			
5) Others- Unspent grants received back		38,34,331	380,31,997
<b>TOTAL</b>		<b>9838,34,331</b>	<b>10380,31,997</b>

## Technology Development Board

Schedule Forming Part of Income and Expenditure for the Year Ended 31<sup>st</sup> March, 2020

Amount in ₹

SCHEDULE 14 - FEES/SUBSCRIPTIONS				
		Current Year		Previous Year
1)	Entrance Fees	-	-	-
2)	Annual Fees/Subscriptions			
3)	Seminar/Program Fees	-	-	-
4)	Consultancy Fees	-	-	-
<b>TOTAL</b>		-	-	-
<b>Note:</b> Accounting Policies towards each item are to be disclosed				

## Technology Development Board

Schedule Forming Part of Income and Expenditure for the Year Ended 31<sup>st</sup> March, 2020

Amount in ₹

SCHEDULE 15- INCOME FROM INVESTMENTS (Income on Invest. From Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)				
		Investment from Earmarked Fund		Investment - Others
		Current Year	Previous Year	Current Year
1)	Interest			
a)	On Govt. Securities			
b)	Other Bonds/Debentures			
2)	Dividends			
a)	On Shares			
b)	On Mutual Fund Securities			
3)	Rents	-	-	-
4)	Other (Specify)	-	-	-
<b>TOTAL</b>				
<b>Transferred to Earmarked/Endowment Funds</b>				

## Technology Development Board

Schedule Forming Part of Income and Expenditure for the Year Ended 31<sup>st</sup> March, 2020

Amount in ₹

SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.			
		Current Year	Previous Year
1)	Income from Royalty	44,87,232	62,82,547
2)	Royalty Accrued		
	Less: Royalty written off	-	-
3)	Others (Specify)		
<b>TOTAL</b>		<b>44,87,232</b>	<b>62,82,547</b>

## Technology Development Board

Schedule Forming Part of Income and Expenditure for the Year Ended 31<sup>st</sup> March, 2020

Amount in ₹

SCHEDULE 17-INTEREST EARNED			
	Current year		Previous Year
<b>1) On Term Deposits:</b>			
a) With Scheduled Banks		291,22,606	282,48,477
b) With Non- Scheduled Banks			-
c) With Institutions			-
<b>2) On Savings Accounts:</b>			
a) With Scheduled Banks ( including EPF A/c)		86,65,931	152,86,632
b) With Non- Scheduled Banks			-
c) Post Office Savings Accounts			-
d) Others			-
<b>3) On Loans:</b>			
a) Employees/Staff			
b) Loans assistance to industrial concerns		5979,70,781	5435,63,877
<b>4) Interest on royalty</b>		2,95,247	8,03,520
<b>5) Interest on grants</b>		-	-
<b>TOTAL</b>		<b>6360,54,565</b>	<b>5879,02,506</b>
<b>Note:</b> Tax Deducted at source to be indicated			

## Technology Development Board

Schedule Forming Part of Income and Expenditure for the Year Ended 31<sup>st</sup> March, 2020

Amount in ₹

SCHEDULE 18-OTHER INCOME			
	Current Year		Previous Year
<b>1) Profit on Sale/disposal of Assets:</b>			
a) Owned assets - UTI			
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost			
<b>2) Profits on redemption of units</b>			
<b>3) Dividend</b>		-	-
<b>4) Miscellaneous Income</b>		3,563	1,67,899
<b>5) Sitting Fees</b>		-	-
<b>6) Donations</b>		3,00,000	1,00,100
<b>7) Income from Venture Fund</b>		-	595,66,726
<b>TOTAL</b>		<b>3,03,563</b>	<b>598,34,725</b>

## Technology Development Board

Schedule Forming Part of Income and Expenditure for the Year Ended 31st March, 2020

Amount in ₹

SCHEDULE 19- INCREASE/(DECREASE) STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS			
	Current Year		Previous Year
a) Closing Stock:			
- Finished Goods			
- Work-in-progress	-	-	-
b) Less: Opening Stock			
- Finished Goods			
- Work-in-progress	-	-	-
<b>NET INCREASE / (DECREASE) [a-b]</b>	-	-	-

## Technology Development Board

Schedule Forming Part of Income and Expenditure for the Year Ended 31st March, 2020

Amount in ₹

SCHEDULE 20-ESTABLISHMENT EXPANSES				
		Current Year		Previous Year
a)	Salaries and Wages		309,94,096	243,59,716
b)	Allowances		4,32,759	1,54,237
c)	Employer Contribution to Provident Fund		14,49,312	16,27,938
d)	Uniform		-	20,000
e)	Staff Welfare Expenses		77,000	67,000
f)	Expenses on Employees' Retir. And terminal Benefits		-	4,03,306
g)	Reimbursement of Medical Charges		2,23,558	5,27,058
h)	Gratuity		3,55,914	3,34,488
	<b>TOTAL</b>		<b>335,32,639</b>	<b>274,93,743</b>

# Technology Development Board

Schedule Forming Part of Income and Expenditure for the Year Ended 31<sup>st</sup> March, 2020

Amount in ₹

SCHEDULE 21-OTHER ADMINISTRATIVE EXPANSES ETC.		
	Current Year	Previous Year
a) National Award	170,00,000	170,00,000
b) Legal charges	45,81,332	53,46,695
c) Assets Management Fees	71,96,785	47,88,432
d) Membership fees	23,600	23,600
e) TDS and Interest	-	7,296
f) Loss on sale of assets	-	-
g) Repairs and maintenance	12,80,715	10,55,507
h) Postage & stamps	55,443	54,927
i) Technology Day Expenditure	6,96,212	20,86,809
j) Vehicles Running and Maintenance	41,422	1,88,344
k) Telephone and Communication Charges	21,25,374	19,98,322
l) Printing, Stationary & Consumables	12,34,404	7,76,971
m) Travel Expenses Domestic	20,31,298	-
Travel Expenses Foreign		-
Travel Expenses Experts	28,61,788	48,93,086
n) Library books & periodical	885	6,116
o) TA/DA to Board members	24,457	1,24,076
p) Auditors Remuneration	80,000	80,000
q) Hospitality Expenses	1,90,132	1,66,083
r) Meeting Expenses	15,85,545	19,52,570
s) Professional Charges	55,12,480	30,31,100
t) a) Unrecoverable Interest written off during the Year	228,56,713	129,35,285
b) Loans Written off due to settlement of accounts	111,54,978	-
c) Loan Provision	(89,05,867)	-
d) Interest Provision for the Year	(110,58,058)	(129,35,285)
u) Bank Charges	-	250
w) Misc. Expenses	6,74,975	7,61,019
x) Newspaper & Magazine	36,123	25,797
y) Advertisement and Publicity	63,26,171	55,93,351
z) Board Expenses & fees	1,43,645	78,571
zi) Rent	90,69,257	74,20,555
zii) Renovation / Refurbishing	-	14,75,348
ziii) Loss on closure of Venture fund (Refer to schedule 25 note no.5)	2752,88,902	-
<b>TOTAL</b>	<b>3521,08,711</b>	<b>605,82,806</b>

## Technology Development Board

Schedule Forming Part of Income and Expenditure for the Year Ended 31st March, 2020

Amount in ₹

SCHEDULE 19- INCREASE/(DECREASE) STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS			
	Current Year		Previous Year
a) Closing Stock:			
- Finished Goods			
- Work-in-progress	-	-	-
b) Less: Opening Stock			
- Finished Goods			
- Work-in-progress	-	-	-
<b>NET INCREASE / (DECREASE) [a-b]</b>	-	-	-

## Technology Development Board

Schedule Forming Part of Income and Expenditure for the Year Ended 31st March, 2020

Amount in ₹

SCHEDULE 20-ESTABLISHMENT EXPANSES				
		Current Year		Previous Year
a)	Salaries and Wages		309,94,096	243,59,716
b)	Allowances		4,32,759	1,54,237
c)	Employer Contribution to Provident Fund		14,49,312	16,27,938
d)	Uniform		-	20,000
e)	Staff Welfare Expenses		77,000	67,000
f)	Expenses on Employees' Retir. And terminal Benefits		-	4,03,306
g)	Reimbursement of Medical Charges		2,23,558	5,27,058
h)	Gratuity		3,55,914	3,34,488
	<b>TOTAL</b>		<b>335,32,639</b>	<b>274,93,743</b>

# Technology Development Board

Schedule Forming Part of Income and Expenditure for the Year Ended 31<sup>st</sup> March, 2020

Amount in ₹

SCHEDULE 21-OTHER ADMINISTRATIVE EXPANSES ETC.		
	Current Year	Previous Year
a) National Award	170,00,000	170,00,000
b) Legal charges	45,81,332	53,46,695
c) Assets Management Fees	71,96,785	47,88,432
d) Membership fees	23,600	23,600
e) TDS and Interest	-	7,296
f) Loss on sale of assets	-	-
g) Repairs and maintenance	12,80,715	10,55,507
h) Postage & stamps	55,443	54,927
i) Technology Day Expenditure	6,96,212	20,86,809
j) Vehicles Running and Maintenance	41,422	1,88,344
k) Telephone and Communication Charges	21,25,374	19,98,322
l) Printing, Stationary & Consumables	12,34,404	7,76,971
m) Travel Expenses Domestic	20,31,298	-
Travel Expenses Foreign		-
Travel Expenses Experts	28,61,788	48,93,086
n) Library books & periodical	885	6,116
o) TA/DA to Board members	24,457	1,24,076
p) Auditors Remuneration	80,000	80,000
q) Hospitality Expenses	1,90,132	1,66,083
r) Meeting Expenses	15,85,545	19,52,570
s) Professional Charges	55,12,480	30,31,100
t) a) Unrecoverable Interest written off during the Year	228,56,713	129,35,285
b) Loans Written off due to settlement of accounts	111,54,978	-
c) Loan Provision	(89,05,867)	-
d) Interest Provision for the Year	(110,58,058)	(129,35,285)
u) Bank Charges	-	250
w) Misc. Expenses	6,74,975	7,61,019
x) Newspaper & Magazine	36,123	25,797
y) Advertisement and Publicity	63,26,171	55,93,351
z) Board Expenses & fees	1,43,645	78,571
zi) Rent	90,69,257	74,20,555
zii) Renovation / Refurbishing	-	14,75,348
ziii) Loss on closure of Venture fund (Refer to schedule 25 note no.5)	2752,88,902	-
<b>TOTAL</b>	<b>3521,08,711</b>	<b>605,82,806</b>

# Technology Development Board

Schedule Forming Part of Income and Expenditure for the Year Ended 31st March, 2020

Amount in ₹

SCHEDULE 22-EXPENDITURE ON GRANTS		
	Current Year	Previous Year
1) Grants given to Institutions/ Organisations		
(i) Incubators	10,84,242	11,08,267
(ii) Other Agencies		-
2) Subsidies given to Institutions / Organisations		
<b>TOTAL</b>	<b>10,84,242</b>	<b>11,08,267</b>

Note: Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants/ Subsidies are to be disclosed

# Technology Development Board

Schedule Forming Part of Income and Expenditure for the Year Ended 31st March, 2020

Amount in ₹

SCHEDULE 23-INTEREST		
	Current Year	Previous Year
a) On Fixed Loans		
b) On Other Loans (including bank Charges)		
c) Others-Grant received from DST	209,24,330	-
<b>TOTAL</b>	<b>209,24,330</b>	<b>-</b>

## Technology Development Board

### Significant Accounting Policies and Notes on Accounts-2019-20

#### A. Significant Accounting Policies

1. Receipts and Payments Accounts is prepared from the cash receipt journal and is a summary of cash transactions under various heads. It records receipts and payments of both capital and revenue nature.
2. Income and Expenditure Account is the summary of incomes and expenditures of the year. It is prepared on accrual basis. It records income and expenditure of revenue nature only. The accrued interest earned on the loan amount disbursed is accounted for in the year in which the loan installment is released; however, the interest is actually receivable after the projects have been completed in accordance with the terms and conditions of the respective loan agreements. Provision for expenses due and approved are accounted for during the year.
3. Depreciation on fixed assets is provided on the basis and rates prescribed under the Income Tax Act, 1961, on diminishing balance method. No depreciation is provided on the fixed Assets sold/transferred/ discarded during the financial year. Addition in fixed assets are accounted at the cost of acquisition.
4. Royalty payments are taken on receipt basis in Receipts and Payments Account and Income & Expenditure Account.
5. Government grants are recognized on receipt basis. Unspent balances are not to be refunded to the Government of India as the grants released by the Government are credited to the Fund for Technology Development and Application in terms of section 9(1)(a) of the Technology Development Board Act, 1995 and thus there is no such requirement of refund. No amount is, therefore, due for refund to the Government of India.
6. In terms of section 9(1) of the Technology Development Board Act, 1995, recoveries made of the amounts granted from the Fund for Technology Development and Application, receipt of interest on loans, royalty, donations and sums received from any other source are credited to the Fund. Keeping this provision in view, the Balance Sheet has been prepared.
7. The balance sheet of Earmarked/ Endowment funds (Venture Capital Funds) maintained by IDBI has indicated the following:-
  - a) The balance sheet is prepared on accrual basis except for income/expenditure in respect royalty, management fee and penal interest thereon, which are recognized on actual receipt/ payment.
  - b) The valuation of assets/ loans/ investments have been carried at the assessment value by IDBI (Fund manager) and the provision for reducing the book value of the assets is recorded as per the notes provided in the financial statements.
  - c) The financial statements of IDBI (VCF) are to be read with other notes and explanations attached with the Balance Sheet provided by IDBI. The financial statements and notes to accounts are taken on record as independently certified by IDBI and the audit report thereon.
8. Fund balances are kept in short term deposits

in nationalized banks. Interest on short term deposits is reflected in the Receipts and Payments Account and Balance Sheet.

9. The investments in companies are stated at cost price. As per the mandate of TDB, the investments are not held for capital appreciation in the strict sense or for any other benefit to TDB, the shares are held at cost of acquisition till they are finally realized. However any permanent decline in the fair value of the investments so held due to the winding up or dissolution of the respective company or any other reason, the value of decline is charged to the income & expenditure account.
10. In the case of default, rescheduling agreement(s) whatsoever done are set aside in accordance with the terms and conditions of the Loan Agreement and balances in account are restored the original agreement. This may result in increase of outstanding amount of the borrower due to reverting back to the original agreement.
11. In the case where borrower is unable to pay the loan / interest amount as per the terms of loan agreement and when the dispute arising out of noncompliance of the loan agreement and consequently matter is referred to arbitration. In such instance the outstanding amounts of loan and interest is frozen on the date of reference to arbitration. Further provisioning or adjustment in the outstanding interest is made only after the award is passed in accordance with the award conditions.
12. In the case where the borrower has defaulted in repayment of its loan and interest as per loan agreement and has since gone into liquidation, booking of interest has been restricted to the date of liquidation. Final provision for write off is made for principal and interest after receipt of final payment from the Official Liquidator since the right to claim interest up to the date of recovery is maintained by TDB.
13. Company's whose status has been identified as having been struck off from the list of registered companies or undergoing liquidation as per the records of Registrar of Companies (ROC), where the loan amount and interest remains overdue/unpaid, has been referred to the legal section. However due to high probability of default and non-confirmation of balance, no interest for the current year has been accounted. Final provision for doubtful recovery or write off is subject to legal closure of the matter in case of each company. Following the list of companies with overdues:

(Figures in ₹ Lakhs)

S. No	Name of Company	Status as per ROC	Overdue Principal	Overdue interest as on March 2019
1.	M/s White circle oxide	Under Liquidation	190.00	323.96
2.	M/s Sai Papain	Strike off	165.00	436.36
3.	M/s Samudra Biopharma	Strike off/ under Liquidation	247.77	465.46
4.	M/s JaveriAgro	Strike off	35.00	87.60
5.	M/s VardaanAgro	Liquidation as per legal	495.00	1607.47
6.	M/s Ordyn Technology	Under Liquidation	426.64	883.21
7.	M/s Cavera System	Liquidation	440.00	385.36
8.	M/s Hydrolina Biotech	Liquidation	430.00	157.73

14. In case of default by a borrower and the subsequent passing of an Arbitration Award, the restatement of loan and interest and also the charging of interest is done as per the award. This may result in decrease/ increase of outstanding amount of interest due from the borrower.
15. In the case of start of Arbitration proceedings, the charge of Interest is discontinued from the date of the start of the proceedings till the award is passed. After the award, other conditions remaining constant, the loan and interest thereon is accounted as per award.
16. In case funds have not been released for the full agreed amount and the time bound repayment schedule is active, interest is calculated on the basis of the amount released at the rate applicable as per agreement.
17. Investments with Venture Funds other Seed funds, are carried at cost. Since the Funds are continuously evolving in terms its activities and is an ongoing concern, no permanent change in the value of the investment is envisaged or provided. Income / Loss is recognized in the Venture Fund Investments either on closure of the funds or disbursement of income during the tenure of the fund.
18. Unless otherwise agreed to by TDB, the payment received from a borrower shall be accounted towards such dues in the following order, viz., Interest including additional interest; further interest and liquidated damages on defaulted amount; repayment instalments of principal due and payable or in the manner as decided and approved by the Board.
19. Stock verification is done on annual basis.
20. Figures are rounded off to the nearest rupee.

## Notes on Accounts

1. TDB received ₹ 9800 lakhs (P.Y. ₹ 10000 lakhs) as grant during the financial year 2019-20.
2. TDB received ₹ 7500 lakhs as Grant in aid under "Fighting COVID-19" during the financial year. The unspent amount has been carried forward towards targeted expenditure in the next year.
3. Technology Development Board has an overdue loan repayment (amount due but not received) amounting to ₹ 21765.44 lakhs (P.Y. ₹ 22087.91 lakhs) as on 31<sup>st</sup> March, 2020. In addition, simple interest of ₹ 10810.20 lakhs (P.Y. ₹ 10695.16 lakhs), additional interest on loan amounting to Rs. 21751.21 lakhs (P.Y. ₹ 21283.99 lakhs) and

₹ 7533.55 lakhs (P.Y. ₹ 5237.65 lakhs) as additional interest on simple interest, were also due.

4. With the change in the Government policy on Non-Performing Assets (NPA) and Insolvency & Bankruptcy Policy 2016, TDB is hopeful to recover substantial percentage of overdue accounts. Provision for doubtful debts is made on basis of representations for settlement with borrowers, recommendation of Debt Resolution Committees (DRC) or other information as is made available by the legal department in such cases, and permanent impairment is recognized on final settlement of the claim amount.
5. Investment and valuation in Venture capital funds (VCF):

Investment and valuation in Venture Capital Fund (VCF) as on 31.03.2020

Sl. No.	Particulars	Par Value of Unit	Amount Invested/Redeemed						NAV per Unit			
			Outstanding Amount as on 31.03.2019		Addition during the year		Redemption/Loss during the year		Closing Amount as on 31.03.2020		NAV as on 31.03.19	NAV as on 31.03.20
			Amount (Rs.)	Number of Units	Amount (Rs.)	Number of Units	Amount (Rs.)	Number of Units	Amount (Rs.)	Number of Units		
1	APDC Venture capital fund (I) (*)	1.00.000	23,47,86,000	2,248	-	2,35,00,000	210	20,97,86,000	2,690	2,984	1,228	
2	GVTI Listed, Ahmedabad (*)	1.00.000	1,36,000	5	-	-	-	1,50,000	2	8,20,24,141	1,82,77,994	
3	Co-Cap venture Trust Fund (*)	1.00.000	21,66,91,328	2,166	-	10,34,638	10	21,58,57,890	2,150	1,41,188	78,098	
4	Bhava venture capital fund/sectoral venture capital fund (*)	10.000	18,40,00,000	10,400	-	76,55,960	766	8,65,44,100	9,834	27,120	28,181	
5	SME Tech Fund- BVCF Trust II	100	11,78,74,724	11,78,747	-	34,34,110	34,867	11,44,40,614	11,44,406	107	106	
6	SEAF India Agri business fund	3.00.000	22,81,31,478	438	1,77,473	1,88,63,888	17	21,00,49,927	42010	2,31,946	48,714	
7	SIDES Venture capital Ltd - India Opportunistic fund	1.000	10,87,26,060	1,08,727	-	1,44,18,678	14,414	17,49,08,155	1,74,818	790	877	
8	Ascent India Fund (**)	100	28,99,70,191	28,99,392	-	28,99,20,191	-	-	28,99,202	17	-	
9	Venture East - TeNet fund II (*)	750	4,41,43,882	1,95,000	-	-	-	4,41,43,882	1,95,000	1,901	1,880	
10	CII- India Fund for Sustainable Energy (SIFTE) (*)	100	3,46,48,847	3,46,448	20,15,756	20,228	-	3,66,29,833	3,66,298	341	321	
			1,47,92,73,464	49,78,491	35,81,720	20,189	86,04,37,249	48,823	1,12,17,59,298			
									NAV Value (₹ Rs)	Cost of Investment	Unrealised Loss / profit	
									Current Year	84,81,31,120	1,12,17,59,298	27,21,81,699
									Previous Year	1,39,56,17,164	1,47,81,71,019	12,30,17,101

(\*) Provisional NAV as per unaudited results

(\*\*) Refer schedule 25 note no. 5 of notes to accounts

## Note:

- 1) The redemption from the Venture Fund recognized on the basis of the distribution by the fund in accordance with para 17 of Schedule 24 referred above.
- 2) "UTI India Ascent Fund" matured during the year and loss arising on redemption of ₹ 2752.89 lakhs has been recognized on closure of the fund.

6. TDB has signed agreement with M/s Global Innovation Technology Alliance (GITA), in joint venture with CII, in equity contribution of 51:49 respectively with a mandate to cover all key elements of innovation ecosystem that benefit industry and technology start-ups, with DST and other organizations. The equity participation of TDB in GITA is ₹ 7.35 crore. TDB release ₹ 7.21 crore up to 31<sup>st</sup> March 2020.
7. The following grant-in-aid distributed during the financial year.

S. No	Company's Name	Purpose	Amount (Rs. in lakhs)
1	Indo French Centre for Promotion of Advanced Research (CEFIPRA)	Programme Management	10.84
	<b>Total</b>		<b>10.84</b>

#### 8. Earmarked/ Endowment Fund: (Schedule 3)

(a) The transfer of money receipts and liabilities outstanding in the books of the Industrial Development Bank of India (IDBI) on account of Venture Capital Fund (VCF) transactions pertaining to grants released by Government of India are required to be transferred to the Board as on 1<sup>st</sup> September 1996. IDBI has not provided with audited statement of accounts for the current year ended 31.3.2020. No further investment or recovery against existing investments in the portfolio held by them since last several year has been reported by IDBI. Audited financial statements for the year ended 31.03.2020, (which was the responsibility of IDBI) have not been received, therefore financial values as on 31.03.2019 have been incorporated.

(b) No change in the borrower outstanding/recovery i.e.: the amount recoverable from the borrower which would include the amount of accrued interest/ additional interest in memorandum books has been reported. Further write off of bad loans

including accrued interest outstanding shall be done where the recovery process has reached a closure and no further repayments are expected from the loan accounts and the same have been approved for write off by the Board.

(c) The management fees charged by IDBI for management of the Asset portfolio has not been agreed to be payable by TDB and it has been taken up with IDBI for a settlement. The amount of ₹ 3,62,10,646/- claimed to be payable to IDBI by TDB is contingent to the final settlement.

9. In accordance with the Agreement between Government of India through Department of Economic Affairs (DEA) and Department For International Development (DFID), Government of United Kingdom of Great Britain together with TDB bide Memorandum of Understanding dated 29.8.2013, it was agreed that the incubation component of "Innovative Ventures and Technologies for Development (INVENT) programme will be Implemented and monitored with TDB, Department of Science & Technology and government of India. The responsibility of TDB is to ensure that funds will be spent on approved activities required to deliver the overall outputs and outcomes of the project. TDB is obliged to hold this fund in a separate bank account and the interest accrued on the bank deposit are to be credited to the fund as part of additional funds available for the program and as fund manager to be released as per project guideline from time and submit progress report and audited accounts to DFID.
10. TDB had preferred an application before NCLT before the recovery of its Loan and its investments in equity in NICCO Corporation (P) Ltd. The NCLT has ordered the investment in equity to be considered as part of loan given by TDB. All realizations arising out of the liquidation proceedings of the company

have first been adjusted against the outstanding loan amount and the balance against the cost of investment held under equity.

11. The following amount has been written off during the year due to non-recovery and approved by the Board.

(Figures in ₹ Lakhs)

Companies Name	Principal	Interest + Additional interest
M/s Basic Health Care	-	17.26
M/s Sundershan	7.21	152.04
M/s KVB Agro	89.06	16.64
M/s Sankhya Technology	15.28	41.34
<b>Total</b>	<b>111.55</b>	<b>228.57</b>

12. Provision for doubtful interest and additional interest due on loans and also principal amount has been made against the following companies, which have agreed to settled their outstanding/ dues as per a proposed recommendation of Debt Recovery Committee (DRC) and approved by the Sub Committee of the Board or where the matter has been admitted in Debt Recovery Tribunal (DRT) and recovery is considered doubtful.

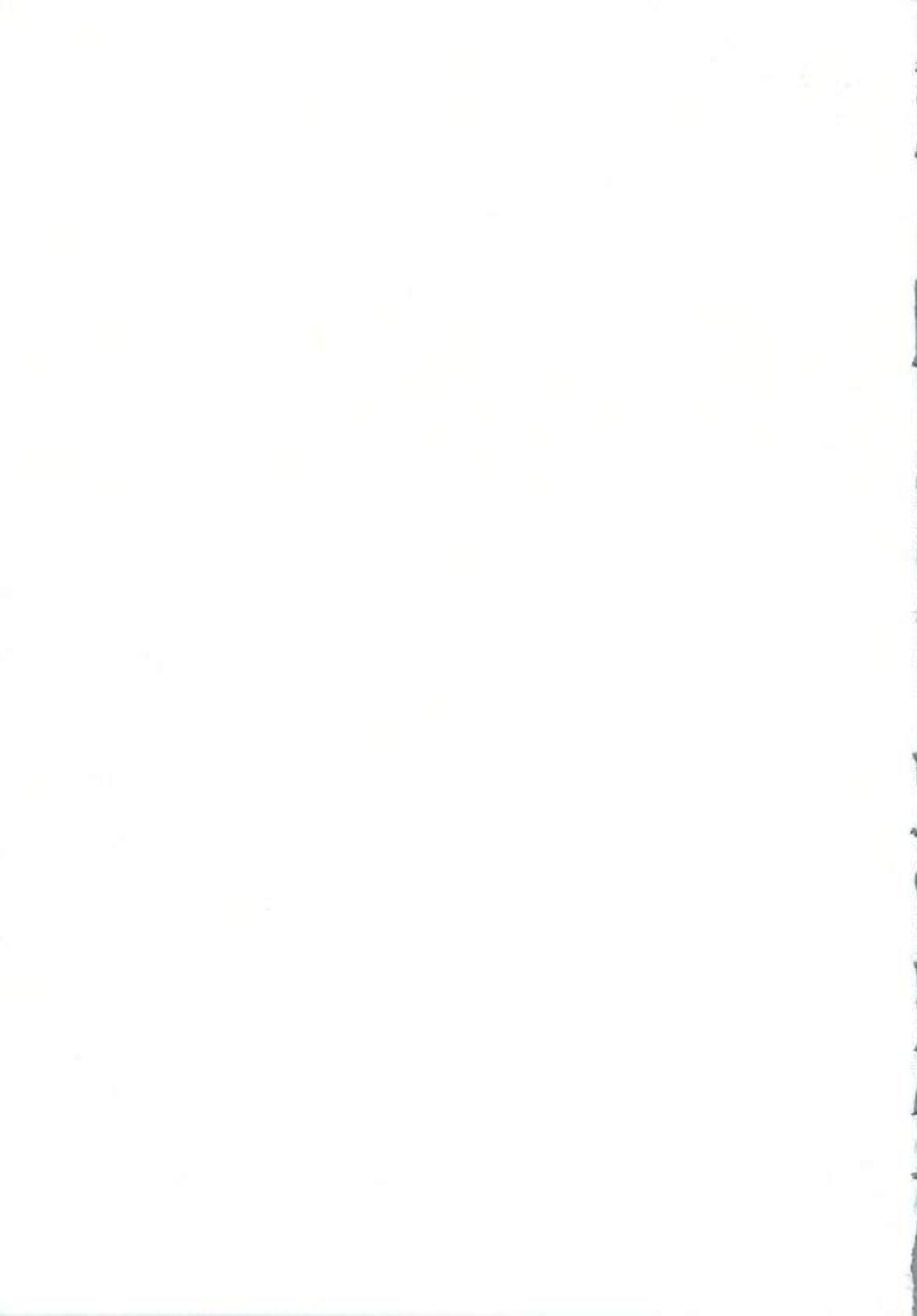
Companies Name	Provision of Interest & additional interest (₹ in lakhs)			
	2016-17	2017-18	2019-20	Total
M/s Medirad	705.40	408.81	-	1114.21
M/s Coral Telecom	100.04	23.29	-	123.33
M/s Waterlife	-	1.01	-	1.01
M/s Amalgam Leather	-	880.78	-	880.78
M/s Exponential	-	92.88	-	92.88
M/s DorvanAgro	-	-	116.16	116.16
<b>Total</b>	<b>805.44</b>	<b>1,406.77</b>	<b>116.16</b>	<b>2,328.37</b>

13. Previous year figures have regrouped and reclassified to make them comparable with current year figures.

-Sd-  
**(Rajesh Jain)**  
Director  
Technology Development  
Board

-Sd-  
**(Dr. Neeraj Sharma)**  
Secretary  
Technology Development  
Board

-Sd-  
**(Prof. Ashutosh Sharma)**  
Chairperson  
Technology Development  
Board





**Separate Audit Report  
of C&AG for the year 2019-20**

**Separate Audit Report of Comptroller and Auditor General of India on the accounts of Technology Development Board, New Delhi for the year 2019-20**

We have audited the attached Balance Sheet of Technology Development Board (TDB), New Delhi as at 31st March 2020 and the Income & Expenditure Account/ Receipts & Payments Account for the year ended on that date under 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 13(2) of the Technology Development Board Act, 1995 (No.44 of 1995). These financial statements are the responsibility of the Board's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/Comptroller and Auditor General's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that –

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit,

(ii) The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government of India,

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Board, as required, in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

**A. Balance Sheet**

**Assets**

**Fixed Assets: Rs.66.77 lakh (Schedule 8)**

Board had capitalized an amount of Rs. 7.19 lakh under the head "Software (PMS)" as additions during the year for development of website modules, which included an amount of Rs. 5.50 lakh already capitalized during the last year (i.e. 2018-19) without imposing any depreciation on the same. The error was also accepted in previous year. Again during current year, the depreciation of Rs. 1.44 lakh was charged for the half year only (i.e. @ 20%) instead of Rs. 3.80 lakh (Rs. 2.10 lakh for the previous year and Rs. 1.70 lakh during current year). Thus, due to improper accounting treatment by the TDB, the assets were overstated by Rs.2.36 lakh besides understatement of expenditure/prior period expenditure towards depreciation not imposed in the prescribed manner.

**B. GENERAL**

**B.1 Investments from Earmarked/Endowment Fund – Rs.65.99 lakh (Schedule 9)**

It was already brought to the notice of TDB through previous years' Separate Audit Report that investments made in companies in a shape of 'Equity' was required to be shown at fair market price.

However, TDB adopted/ incorporated the last year's figure of Rs.65.99 lakh of value of investment made in equity (after diminution in its value). As the actual/ audited figure of equity (after diminution in its value) for the current year was not reported in the

books of accounts for the year 2019-20. Therefore, **Audit is unable to assure that there is no further diminution in the value of equity during the year and the figure of Rs.65.99 lakh reported as Investment (Equity), as on 31 March 2020 is correct and authentic.**

**B.2 Investments others-Rs.14019.52lakh(Schedule 10)  
(Rs.14019.52-2081.63 lakh = Rs.11937.89 lakh)**

An amount of 14019.52 lakh was reported in Schedules 10: 'Investments – others' appended to Balance sheet of TDB for 2019-20, as investments made in different companies in a shape of 'Equity/ Venture Capital Funds (VCFs)'.

It was observed that since last five years, there was persistent decline in the net asset value of four VCFs. The reduction in the carrying amount and any reversals of such reduction was required to be charged or credited to the profit and loss statement. However, despite being mentioned in previous year's Separate Audit Report, TDB did not revalue them at fair market price (*Annexure-A*), therefore, **Audit is unable to assure that there is no further diminution in the value of equity earlier and during the year and the figure of Rs.140.20 crore reported as Investment –others as on 31 March 2020 is correct and authentic.**

**C. Grant-in-aid**

TDB receives grants from Department of Science and Technology out of the R&D Cess levies and collected by the Government at the rate of five per cent on payments made towards import of technology. TDB received a grant of Rs.98.00 crore from the Department of Science and Technology during 2019-20.

In addition to opening balance of Cash/Bank balance of Rs.71.21 crore, an amount of Rs.166.47 crore was received by TDB as interest on short term deposits/loans/royalty/grants, repayment of loans, royalty, income from venture funds, donation etc., during the year 2019-20. After making a total payment of Rs.148.62 crore for investments, establishment/office expenses and disbursement of loans/grants, etc., Rs.187.07 crore was shown as unspent as on 31 March 2020.

#### **D Management Letter**

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of Technology Development Board, New Delhi through a management letter issued separately for remedial/corrective action

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters stated in comment **no. 1 and 2** and other matter stated above, and other matters mentioned in Annexure to the Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

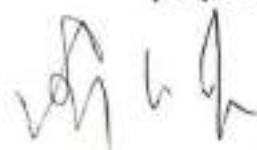
(a) In so far as it relates to the Balance Sheet of the State-of-affairs of the TDB as of 31<sup>st</sup> March, 2020.

(b) In so far as it relates to the Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

Date:

Place: New Delhi

For and on behalf of C&AG of India  
(Inspection)



Director General of Audit  
(Scientific Departments)

## **Internal Control System**

### **1. Adequacy of Internal Audit System**

Internal audit of TDB for the year 2016-18 has been conducted.

### **2. Adequacy of Internal control system**

The following deficiencies in relation to internal control system were observed:

#### **2.2 Outstanding Utilization Certificate**

In terms of Rule 238 of General Financial Rules, each grantee Institution is required to furnish the utilization certificate within 12 months of the closure of the financial year, indicating that the grant has been utilized for the purpose for which it was sanctioned. However, despite being pointed out in earlier Audit Reports, TDB did not obtain the Utilization Certificates in respect of 12 cases aggregating Rs.229.08 lakh from grantee institutions in time.

#### **2.3 Non-conduction of Peer Review of Technology Development Board, New Delhi by the Ministry**

Rule 229 (ix) of GFRs 2017 provides for existence of a mechanism of external or peer review of autonomous organizations every three or five years depending on the size and nature of activity. Such a review should focus, inter alia, on the objective for which the autonomous organization was set up and whether these objectives have been or are being achieved; continuation or otherwise of the activities of the organization either because they are no longer relevant or have been completed or there was substantial failure in achievement of objectives; whether user charges for the services provided are levied at appropriate rates; scope for maximizing internal resources generation so that the dependence upon government budgetary support is minimized, etc.

However, no Peer Review of the Board was conducted by the Ministry as of September, 2020 which was required as per the above stated rules.

#### **2.4 Outstanding bank charges**

Scrutiny revealed that Canara Bank and Union Bank of India (A/c. No. 1484101021952 and A/c. No. 349902010043607) had deducted Rs.184851.99 and Rs. 66704.40 towards outside charges and bank charges respectively up to 31st March, 2020 which had been lying unsettled as of 31<sup>st</sup> August, 2020. The matter may be taken up with the bank authority to identify and settle the issue.

#### **3. System of physical verification of fixed assets**

Physical verification of fixed assets had been conducted for the year 2019-20 and no discrepancy was reported.

#### **4. System of physical verification of inventories**

Physical verification of inventories had been conducted for the year 2019-20 and no discrepancy was reported.

#### **5. Regularity in payment of statutory dues:**

No statutory dues were outstanding.

  
Deputy Director  
(Inspection)

Annexure-A

Sl. No.	Name of the Firm	Face value of equity per unit (Rs.)	NAV as on 31 <sup>st</sup> March 2016	NAV as on 31 <sup>st</sup> March 2017	NAV as on 31 <sup>st</sup> March 2018	NAV as on 31 <sup>st</sup> March 2019	NAV as on 31 <sup>st</sup> March 2020
1	Ivy Cap Venture Trust Fund (*)	100000.00	128297.83	160512.17	157348.94	143138.00	79099.00
2	SEAF India Agribusiness Fund	500000.00	360559.00	394294.00	429827.00	251346.00	48754.00
3	SIDBI Venture Capital Ltd. – India Opportunity Fund	1000.00	881.63	800.35	793.86	750.00	677.00
4	Ascent India Fund	100.00	51.87	40.51	32.72	17.00	Nil

(\*) Provisional Net Asset Value as per unaudited results.